चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित

दिल्ली, 08 अगस्त–14 अगस्त 2011

मूल्य 5 रुपये

सपने संजोने और बिखरने की दास्तां

पेज-3

मौजूदा क़ानून कहीं से कमतर नहीं

पेज-6

हिमालय को बचाने की अंतरराष्ट्रीय पहल

पेज-7

साई की महिमा

पेज-12

लोकपाल बिल

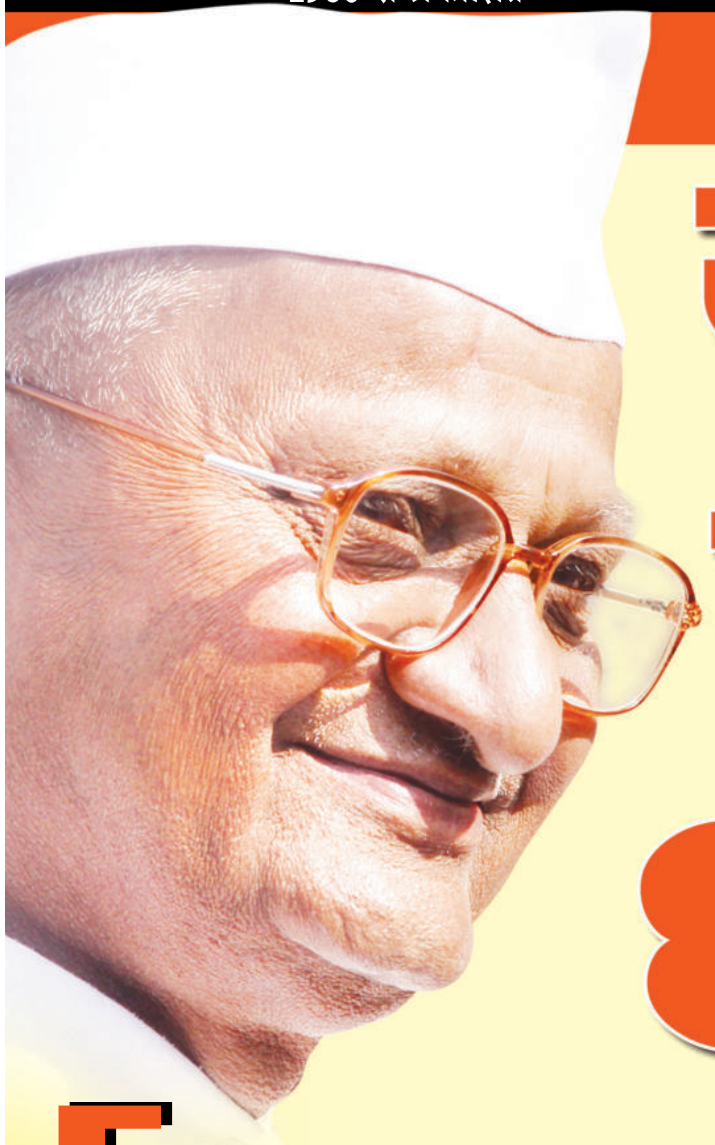

यह जनता के साथ धोखा है

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

सरकार के लोकपाल बिल में टीम अन्ना की मुख्य दलीलों को दरकिनार कर दिया गया. अन्ना हज़ारे ने भूख हड़ताल की घोषणा की है और सरकार ने पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी है. यह संकेत दिया जा रहा है कि अगर अन्ना नहीं माने तो जो हाल पुलिस ने बाबा रामदेव का किया था, वही अन्ना हजारे का होगा. पिछली बार की तरह जन समर्थन और मीडिया का साथ मिलेगा या नहीं, कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार अब कठघरे में आ गई. सरकार भ्रष्टाचार की हिमायती नज़र आने लगी है. यही वजह है कि लोगों को अब उसकी सही दलीलों पर भी भरोसा नहीं रहा.

मनीष कुमार

सरकार ने लोकपाल बिल का मसौदा तैयार कर लिया है. इस मसौदे की एक रोचक जानकारी–अगर कोई व्यक्ति किसी अधिकारी के ख़िलाफ़ शिकायत करता है और वह झूठा निकला तो उसे 2 साल की सज़ा और अगर सही साबित होता है तो भ्रष्ट अधिकारी को मात्र 6 महीने की सज़ा. मतलब यह कि भ्रष्टाचार करने वाले की सज़ा कम और उसे उजागर करने वाले की सज़ा ज़्यादा. इसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी को मुकदमा लड़ने के लिए मुफ्त सरकारी वकील मिलेगा, जबकि उसे भ्रष्ट और ख़ुद को सही साबित करने के लिए शिकायतकर्ता को अपने ख़र्च पर मुकदमा लड़ना होगा. यह सरकार का भ्रष्टाचार से लड़ने का नायाब तरीक़ा है. सरकार ने अपनी नीतियां, मानसिकता और विचारधारा साफ़ कर दी है कि वह भ्रष्टाचार को लेकर कितनी गंभीर है. एक शर्मनाक बयान आया, देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. कौशिक बसु का. उन्होंने कहा कि घूसखोरी को ही वैध बना देना चाहिए. अजीबोगरीब बात यह है कि इंफोसिस के मालिक और देश के जाने–माने उद्योगपति नारायण मूर्ति भी इसका समर्थन करते हैं. अब जब प्रधानमंत्री के इतने क़रीबी अर्थशास्त्री और नारायण मूर्ति जैसे समझदार लोग घूसखोरी की पैरवी करने लगें तो इस देश का क्या होगा, यह शायद ऊपर वाला भी नहीं बता सकता. लेकिन सरकार इन सबसे दो कदम आगे है. पहले उसने सीबीआई को सूचना अधिकार कानून से बाहर कर दिया और अब एक कमज़ोर लोकपाल बनाकर यह बता दिया कि वह, अधिकारी और नेता देश में मौजूद भ्रष्टाचार के साथ ख़ुद को आनंदित महसूस करते हैं, सब मस्त हैं.

देश की जनता लोकपाल इसलिए चाहती है, क्योंकि वह भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है. लोगों में गुस्सा है. सरकार ने जो लोकपाल बिल तैयार किया है, उससे भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा. हां, इस पर राजनीति ज़रूर होगी. अन्ना हज़ारे की टीम और मीडिया को गुमराह करने के लिए इस मुद्दे पर ज़ोर दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में होंगे या नहीं. सरकारी चाल को समझना ज़रूरी है. हैरानी की बात यह है प्रधानमंत्री ख़ुद को लोकपाल के दायरे में रखना चाहते हैं, फिर भी कैबिनेट को यह मंज़ूर नहीं है. प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखना उचित है या नहीं, इस पर विवाद चल रहा है. इस पर दो राय हैं. एक राय यह है कि जिस तरह का लोकपाल अन्ना की टीम चाहती है, उससे संवैधानिक संरचना बिगड़ सकती है. इसलिए देश में प्रजातांत्रिक संस्थाओं के ज़रिए ही कोई हल निकाला जाना चाहिए. प्रधानमंत्री पर कार्रवाई और उनसे पूछताछ करने का अधिकार किसी भी संस्था को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इससे संसद और कार्यपालिका दोनों पर असर पड़ सकता है, सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न हो सकती है और देश में अराजकता आ सकती है. इस तर्क में कोई कमी नहीं है. सरकार भी यही राय दे रही है. लेकिन लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है. दूसरी राय यह है कि अगर प्रधानमंत्री ईमानदार है तो उसे लोकपाल के दायरे में आने में क्या आपत्ति है? लोकतंत्र में जनता की राय सर्वोपरि होती है. जनता पिछले दो सालों से निरंतर नए–नए घोटालों से रूबरू हो रही है. कई घोटालों में मंत्री और नेता जेल में हैं, कई मुख्यमंत्रियों को इस्तीफ़ा देना पड़ा. कुछ घोटालों में प्रधानमंत्री का नाम भी जोड़ा जा रहा है. लोगों के बीच यह धारणा बन गई है कि सरकार में शामिल सारे लोग और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं. ऐसे में जनधारणा यही है कि जो भी सरकारी पदों पर विराजमान है, उसे लोकपाल के दायरे में होना चाहिए, चाहे वह प्रधानमंत्री ही क्यों न हो.

लोकपाल बिल के क़ानून बनने से पहले इस पर राजनीति होगी. प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से जानबूझ कर बाहर रखा गया है, ताकि मीडिया और लोगों का ध्यान भ्रष्टाचार से हट जाए. पहला सवाल तो यह है कि अगर सरकार मज़बूत लोकपाल के पक्ष में नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री या फिर जजों को इसके दायरे में लाने या न लाने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है. हां, ख़तरा तो तब खड़ा होता जब सरकार एक सर्वशक्तिमान लोकपाल बनाती और फिर कहती कि इसके दायरे में प्रधानमंत्री को लाना उचित नहीं है. आगे आने वाले दिनों में रामदेव की ही तरह अनशन भी होगा और फिर सरकार प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लेने के लिए बातचीत करेगी, प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाया जाएगा और पूरे मामले को संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाएगा. सरकार इस तरह विपक्ष को शांत कर सकेगी और टीम अन्ना के लोगों भी लगेगा कि उन्होंने लड़ाई जीत ली. इन सबके बावजूद सरकार ने जो मसौदा तैयार किया है, उसके जरिए भ्रष्टाचार से नहीं लड़ा जा सकता है.

क़ानून बनने या लोकपाल बनने से भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा. लोकपाल बनाने का मक़सद तो यही होना चाहिए कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसे सज़ा मिले और वह बच न पाए. इसकी ज़रूरत इसलिए है, क्योंकि अब तक भ्रष्टाचार करने वाले लोग क़ानून को चकमा देने में कामयाब रहे हैं. जिन लोगों को सज़ा मिली है, उन्हें हम अपवाद मान सकते हैं. अन्ना हज़ारे के आंदोलन के बाद 10 लोगों की संयुक्त समिति बनी. कई बैठकों के बाद सरकार ने लोकपाल बिल का मसौदा तैयार किया, लेकिन कुछ मुद्दों पर सरकार और अन्ना हज़ारे की टीम के बीच मतभेद थे, जो आज भी बरक़रार हैं. सरकार के मसौदे के मुताबिक़, लोकपाल के 9 सदस्य होंगे. सुप्रीम कोर्ट के किसी कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इसका चेयरमैन बनाया जाएगा. इनमें से आधे न्यायिक सदस्य होंगे, जिन्हें चुनने के लिए सरकार ने एक टीम बनाई है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष, एक कैबिनेट मंत्री (जिसे प्रधानमंत्री चुनेंगे), एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाईकोर्ट के जज, एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सरकारी लोकपाल बिल के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी अधिकारी के ख़िलाफ़ शिकायत करता है और वह झूठा निकला तो उसे 2 साल की सज़ा और अगर सही साबित होता है तो भ्रष्ट अधिकारी को मात्र 6 महीने की सज़ा. इसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी को मुकदमा लड़ने के लिए मुफ्त सरकारी वकील मिलेगा, जबकि उसे भ्रष्ट और ख़ुद को सही साबित करने के लिए शिकायतकर्ता को अपने ख़र्च पर मुकदमा लड़ना होगा. यह सरकार का भ्रष्टाचार से लड़ने का कैसा नायाब तरीक़ा है?

टीम अन्ना का कहना है कि यह लोकपाल नहीं, जोकपाल है. सरकारी लोकपाल के दायरे में निचले स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भ्रष्टाचार शामिल नहीं होगा. नगर निगम, पंचायत, विकास प्राधिकरणों का भ्रष्टाचार इसकी जांच के दायरे में नहीं आएगा. एक और पेंच है. सरकारी लोकपाल के दायरे में वैसा कोई मामला नहीं आएगा, जो 7 साल से ज़्यादा पुराना है. मतलब यह कि बोफोर्स और चारा घोटाला जैसे मामले इसकी जांच के दायरे से पहले ही अलग कर दिए गए हैं.

"Cotton ki Jhappi!"

T.T.

Healthy Innerwear

Vest • Brief • Bra-Panties • T-Shirts

Ph. : 011-45060708, E-mail: export@tttextiles.com

मुख्यमंत्री सचिवालय में कुछ बाबुओं की नियुक्ति अतिरिक्त कैबिनेट सचिव के रूप में क्यों की गई है, जबकि इसका कोई प्रावधान नहीं है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

आरबीआई का अगला गवर्नर कौन

महंगाई दर में वृद्धि जारी है और मुद्रास्फीति पर भी काबू नहीं पाया जा सका है, इस कारण वित्तीय क्षेत्र में अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं. इसके साथ ही सत्ता के गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का अगला गवर्नर कौन होगा, क्योंकि वर्तमान गवर्नर डी सुब्बाराव सितंबर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं. कुछ लोगों का विचार है कि सुब्बाराव के कार्यकाल में वृद्धि की जाए, जबकि कुछ लोग दूसरे नामों पर गौर कर रहे हैं. अगले गवर्नर के लिए जिन लोगों की चर्चा हो रही है, उनमें वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाकार रघुराम जी राजन, एशियाई विकास बैंक में कार्यरत अशोक लाहिड़ी और वित्तीय मामलों के सचिव आर गोपालन प्रमुख रूप से शामिल हैं.

वीरप्पा की सलाह

एम वीरप्पा मोइली ने कानून मंत्रालय छोड़ने से पहले भ्रष्टाचार पर काबू पाने और शासन व्यवस्था में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के पास एक दस सूत्रीय प्रस्ताव भेजा है. इस प्रस्ताव में सरकार को एक सलाह यह भी दी गई है कि सेवानिवृत्त बाबुओं की नियुक्ति विनियामक अधिकारी के रूप में न की जाए. यूपीए सरकार के लिए इस सलाह पर अमल करना काफी मुश्किल लगता है, क्योंकि उसने तो सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्त करने की परंपरा बना ली है. देखते हैं, वीरप्पा की सलाह मानी जाती है या फिर उसे डिब्बाबंद कर दिया जाएगा.

उत्तर प्रदेश सरकार और हाईकोर्ट

मायावती सरकार भूमि अधिग्रहण नीति पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से अभी उबर भी नहीं पाई थी कि अदालत ने एक बार फिर सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया. सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एस एन शुक्ला ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसके माध्यम से सरकार से पूछा गया है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में कुछ बाबुओं की नियुक्ति अतिरिक्त कैबिनेट सचिव के रूप में क्यों की गई है, जबकि इसका कोई प्रावधान नहीं है. मुख्यमंत्री सचिवालय में केवल मुख्य सचिव का पद होता है. यही नहीं, उनके वेतनमान भी नियम विरुद्ध हैं. जानकारी के अनुसार, ऐसे बाबुओं में नवनीत सहगल, नेतराम, दुर्गा शंकर मिश्रा और आर पी सिंह आदि शामिल हैं.

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

भूसरेड्डी जेएस बने

1989 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी संजय आर भूसरेड्डी को कृषि मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है. उन्होंने स्वर्ण माला रावल का स्थान लिया.

चटर्जी बनेंगे प्रधान सचिव

1974 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी पुलक चटर्जी का पीएम का प्रधान सचिव बनना तय हो गया. वह अक्टूबर में कार्यभार ग्रहण करेंगे. चटर्जी अभी विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के पद पर हैं.

पंकज अग्रवाल बने एएस

1978 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल को उपभोक्ता मामलों के विभाग का अतिरिक्त सचिव बनाया गया. उन्होंने राकेश कक्कड़ का स्थान लिया, जिन्हें खाद्य प्रसंस्करण विभाग का सचिव बनाया गया है.

एस के सिन्हा चले मनीला

1994 बैच के असम कैडर के आईएएस अधिकारी एस के सिन्हा को एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार बनाया गया है. सिन्हा अभी डीएसएफ के निदेशक हैं.

नारायण की जगह पवाडिया

1981 बैच के आईआरटीएस अधिकारी अशोक कुमार पवाडिया को पब्लिक इंटरप्राइजेज विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है. उन्होंने जीतेंद्र नारायण की जगह ली. नारायण लंबी छुट्टी पर चले गए हैं.

यह जनता के साथ धोखा है

पृष्ठ एक का शेष

यही लोकपाल के चेयरमैन और सदस्यों को चुनेंगे. अब एक सवाल उठता है कि इनमें से जितने भी लोग हैं, उसमें सरकारी पक्ष का पलड़ा भारी दिखाई देता है. खतरा इस बात का है कि इनके द्वारा चुने गए लोकपाल भी राजनीति का शिकार हो सकते हैं, जैसा कि सीवीसी के साथ हुआ. इस लोकपाल को ग्रुप ए के अधिकारियों, मंत्रियों और सांसदों (संसद के बाहर के मामलों में) की जांच करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन किसी को सज़ा देने का हक़ नहीं है. यह सुप्रीम कोर्ट को सज़ा के लिए सुझाव दे सकता है, लेकिन मंत्रियों के मामले में यह भी नहीं कर सकता. अन्ना हजारे की टीम लोकपाल को सज़ा देने के अधिकार के पक्ष में थी और साथ ही वह सीवीसी और सीबीआई को लोकपाल में जोड़ने की बात कहती आई है. सरकार ने अन्ना की टीम के सुझावों को दरकिनार कर दिया.

टीम अन्ना के लोगों का कहना है कि यह लोकपाल नहीं, जोकपाल है. जनता के साथ किया गया एक मज़ाक़ है. उनकी दलील है कि रिश्वतख़ोरी से पीड़ित आम आदमी की शिकायतें लोकपाल नहीं सुनेगा. सरकारी लोकपाल के दायरे में निचले स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भ्रष्टाचार शामिल नहीं होगा. नगर निगम, पंचायत, विकास प्राधिकरणों का भ्रष्टाचार इसकी जांच के दायरे में नहीं आएगा, राज्य सरकारों का भ्रष्टाचार भी इसके दायरे में नहीं आएगा. टीम अन्ना की तरफ़ से यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री, जजों और सांसदों का भ्रष्टाचार भी लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है. इसका मतलब यह है कि 2-जी स्पेक्ट्रम, कैश फॉर वोट, कामनवेल्थ, आदर्श सोसाइटी और येदियुरप्पा के खनन जैसे घोटालों के ख़िलाफ़ सरकारी लोकपाल कुछ नहीं कर सकेगा. सरकार ने एक और पेंच लगा दिया है. सरकारी लोकपाल के दायरे में वैसा कोई मामला नहीं आएगा, जो 7 साल से ज्यादा पुराना है. मतलब यह कि बोफोर्स और चारा घोटाला जैसे मामले इसकी जांच के दायरे से पहले ही अलग कर दिए गए हैं. लोकपाल के सदस्यों को ही सारा काम करना होगा. यानी सब कुछ 9 सदस्य करेंगे, अफ़सरों के पास निर्णय लेने के अधिकार नहीं होंगे, इससे सारा का सारा काम दो-तीन महीने में ही ठप हो जाएगा. टीम अन्ना का आरोप है कि नेता एक अच्छा लोकपाल बिल नहीं ला सकते, क्योंकि अगर एक सख्त लोकपाल कानून बना तो देश के आधे से अधिक नेता दो साल में जेल चले जाएंगे और बाक़ी की भी दुकानदारी बंद हो जाएगी.

सवाल तो यह है कि सरकार सचमुच भ्रष्टाचार से लड़ना चाहती भी है या नहीं. भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इसके स्वरूप को समझना ज़रूरी है. भारत के सरकारी तंत्र में अलग-अलग स्तर पर भ्रष्टाचार मौजूद है. सरकार की समस्या यह है कि वह जिन नीतियों को बढ़ावा दे रही है, जिस विचार को सही मान रही है, असल में वही भ्रष्टाचार की जड़ है. 1991 के बाद से भारत में भ्रष्टाचार का स्वरूप बदल गया है. जबसे देश में उदारवाद और निजीकरण का

फोटो- प्रभात पाण्डेय

दौर चला है, तबसे हमने उद्योग जगत के जानवरों को समाज में लूट मचाने की खुली छूट दे दी है. पिछले बीस साल का इतिहास यही बताता है कि कॉरपोरेट जगत भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है. बड़े-बड़े उद्योगों ने अपने मुनाफ़े के लिए न सिर्फ़ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, बल्कि पूरे सरकारी तंत्र को दूषित कर दिया. मनमोहन सिंह की उदारवादी नीतियों ने न सिर्फ़ कोटा राज और लाइसेंस राज को ख़त्म किया, बल्कि उद्योगों पर लगने वाले टैक्स को कम कर दिया. उद्योग जगत पर लगने वाले टैक्स इंदिरा गांधी के शासनकाल की तुलना में आज सिर्फ़ एक तिहाई हैं. उदारवाद की नीतियां इसलिए लागू की गई थीं कि उद्योग जगत टैक्स चोरी नहीं करेगा, भारत की अर्थव्यस्था में मौजूद काले धन और कालाबाज़ारी में कमी आएगी. हैरानी की बात यह है कि 1991 में उदारवाद की नीतियां लागू करने से पहले काला धन 27 फ़ीसदी था, लेकिन आज यह बढ़कर 43 फीसदी पहुंच चुका है. भ्रष्टाचार की स्थिति इतनी गंभीर है कि भारत सरकार को देश के 57 फ़ीसदी मुनाफ़े का पता ही नहीं चल पाता है. एक आंकड़े के मुताबिक़, भारत में हर साल 35 लाख करोड़ रुपये काला धन बनते हैं, जिसका सिर्फ़ 10 फ़ीसदी हिस्सा विदेश भेज दिया जाता है. उदारवाद की नीतियां इस संदर्भ में पूरी तरह विफल रही हैं. मनमोहन सिंह के उदारीकरण के बाद सरकार ने आर्थिक विकास का जो मॉडल अपनाया है, वही भ्रष्टाचार की मुख्य वजह है. यही उद्योग जगत भारत के आर्थिक विकास के एक आंकड़े (जिसे हम जीडीपी कहते हैं) को मज़बूती देता है. हमारी सरकार को आंकड़ों से इतना प्यार है कि इसके लिए उसने देश की जनता को लूटने वाले उद्योगों को खुली छूट दे रखी है.

विभिन्न राजनीतिक दल, नेता और अधिकारी भ्रष्टाचार के इस भयंकर खेल में एक छोटे खिलाड़ी बन गए हैं, पालतू जीव की तरह बड़े-बड़े उद्योगपतियों की कठपुतली बन गए हैं. येदियुरप्पा को ले लीजिए. कर्नाटक के लोकायुक्त ने कहा कि खनन घोटाले से राज्य को क़रीब 16 हज़ार करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ. येदियुरप्पा को क्या मिला, सिर्फ 10 करोड़. उद्योगपति 16 हजार करोड़ रुपये का मुनाफ़ा कमा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को मिला सिर्फ़ 10 करोड़! यह तो भीख की राशि से भी कम है. इसी तरह 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले को देखिए. सीएजी के मुताबिक़, इस घोटाले से भारत सरकार को एक लाख 76 हज़ार करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ. अब कोर्ट में ए राजा के ख़िलाफ़ मामला चल रहा है 200 करोड़ रुपये का. अब यह समझ में नहीं आता कि केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर ऐसा क्या दबाव है, जिसकी वजह से वे इन उद्योगपतियों के सामने झुक जाते हैं. सरकार के दृष्टिकोण में ही समस्या है, वह भ्रष्टाचार को ख़त्म ही नहीं करना चाहती.

देश की जनता का भ्रष्टाचार से रोज सामना होता है. बीडीओ, तहसीलदार, जिला मजिस्ट्रेट, स्कूल, थाना, अस्पताल, कचहरी यानी किसी भी सरकारी विभाग के दफ्तर में घुसते ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा सरकारी तंत्र किस तरह भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है. देश के मंत्रियों और नेताओं की आंखों को यह सब नज़र नहीं आता है, लेकिन यह यत्र-तत्र-सर्वत्र मौजूद है. अगर सरकार भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए लोकपाल लाना चाहती है तो सबसे पहले उसे ग्रास रूट लेवल पर मौजूद भ्रष्टाचार को ख़त्म करना होगा. यह करना आसान भी है, लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने लोकपाल को ज़मीनी स्तर पर मौजूद भ्रष्टाचार से दूर रख दिया. वैसे एक बात माननी पड़ेगी कि यूपीए सरकार की योजनाओं की वजह से भ्रष्टाचार ने अब पंचायत और गांवों तक अपनी पैठ बना ली है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, मनरेगा हो या फिर जन वितरण प्रणाली, अब गांव वाले भी भ्रष्टाचार में भागीदारी कर रहे हैं. सरकार को अपनी योजनाओं के सही कार्यान्वयन के लिए मजबूत लोकपाल बनाना चाहिए था. सरकार की मानसिकता पर इसलिए सवाल उठता है, क्योंकि ज़मीनी स्तर के भ्रष्टाचार से लोकपाल को बाहर रखा गया और बहाना बनाया गया कि यह राज्यों का विषय है. यह दलील न तो उचित है और न तर्कसंगत. दूसरा सवाल यह है कि सीबीआई को लोकपाल से बाहर रखने का क्या मकसद है? इसके अलावा यह कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता है या उसकी जानकारी लोकपाल को देता है तो उसे इस क़ानून के तहत क्या सुरक्षा मिली है? ऐसे लोगों को सुरक्षा न देकर सरकार ने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई में जनता की हिस्सेदारी ख़त्म करने की कोशिश की है. अगर सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने के प्रति गंभीर होती तो एक मज़बूत लोकपाल बनाती. सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच को लोकपाल को सौंप देती, जांच के लिए ज़रूरी सारे संसाधन मुहैया कराती. लोकपाल अगर मानवाधिकार आयोग की तरह एक दंतहीन, विषहीन संस्था बनता है तो फिर भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई में इसका कोई योगदान नहीं होने वाला है.

संसद, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका पर संविधान और देश के प्रजातंत्र को बचाने की ज़िम्मेदारी है. आज हम इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं, जहां यह कहा जा सकता है कि पिछले साठ सालों में इन तीनों संस्थाओं ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में चूक की है. उसी चूक की वजह से भ्रष्टाचार ने पूरे सरकारी तंत्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया है. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से लोगों में आशा जगी है. मीडिया, रामदेव और अन्ना हजारे जैसे लोग यह आशा जगाते हैं कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है. सरकार में विद्वान लोग हैं, क़ानून और अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं, भ्रष्टाचार को समझने और पकड़ने का हुनर इनसे ज्यादा किसी के पास नहीं है. फिर भी जब पी जे थामस के पक्ष में बयान आते हैं, जब ए राजा को निर्दोष बताया जाता है, जब थलसेना अध्यक्ष के ख़िलाफ़ साज़िश होती है, जब अदालत प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकार को हलफ़नामा दाखिल करने का आदेश देती है, जब घोटालों में बड़े-बड़े नेताओं और उनके परिवार के लोगों के नाम आते हैं तो देश के हर नागरिक का विश्वास हिल जाता है. जनता का विश्वास बचाए रखने की सबसे पहली ज़िम्मेदारी सरकार की है. डर इस बात का है कि कहीं सरकार से चूक न हो जाए.

1991 में उदारवाद की नीतियां लागू करने से पहले काला धन 27 फ़ीसदी था. आज यह 43 फीसदी हो गया है. भारत सरकार को देश के 57 फ़ीसदी मुनाफ़े का पता ही नहीं चल पाता है. एक आंकड़े के मुताबिक़, भारत में हर साल 35 लाख करोड़ रुपये काला धन बनते हैं, जिसका सिर्फ़ 10 फ़ीसदी हिस्सा विदेश भेजा जाता है. मनमोहन सिंह के उदारीकरण के बाद सरकार ने आर्थिक विकास का जो मॉडल अपनाया है, वही भ्रष्टाचार की मुख्य वजह है.

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 22
दिल्ली, 08 अगस्त-14 अगस्त 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के -2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-4783999/011-23418962
0120-6450888, 0120-6452888
0120-6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120-4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120-4783950

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

किसानों के विरोध के कारण नोएडा एक्सटेंशन के फ्लैटों का निर्माण ख़तरे में पड़ गया है. नोएडा में अब तक बिल्डरों ने एक लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा धनराशि का निवेश कर रखा है.

ग्रेटर नोएडा

सपने संजोने और बिखरने की दास्तां

फ़िरदौस ख़ान

भूमि अधिग्रहण मामले में सरकार का रवैया और आला अफ़सरों का लालच किसानों, बिल्डरों और अपने घर का सपना संजोने वाले लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है. सरकार की कोताही यह है कि भूमि अधिग्रहण संशोधित विधेयक को अब तक क़ानून का रूप नहीं दिया गया. अंग्रेज़ी शासनकाल के क़ानून आज भी लागू हैं, जिसके कारण अक्सर जनता और सरकार के बीच टकराव के हालात पैदा हो जाते हैं. मौजूदा भूमि अधिग्रहण क़ानून 1894 में लागू किया गया था. उस वक़्त सरकार ने इस क़ानून के ज़रिए सार्वजनिक विकास कार्यों के अलावा पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया था. आज़ादी के बाद ख़ासकर 1990 के दशक में उदारीकरण और निजीकरण को बढ़ावा मिलने के दौर में इसी क़ानून का सहारा लेकर पूंजीपतियों ने लोगों की ज़मीनें हथियाना शुरू कर दिया. साल 2005 में विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज़) अधिनियम पास होने के साथ ही पूंजीपतियों को और ज़्यादा भूमि अधिग्रहण के मौक़े मिल गए. हालांकि सेज़ का काफ़ी विरोध भी किया गया. कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र की यूपीए सरकार ने भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक लाने का वायदा किया है. ग़ौरतलब है कि 6 दिसंबर, 2007 को तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद लोकसभा में भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक–2007 पेश कर चुके हैं. उस वक़्त यह विधेयक विचार–विमर्श के लिए ग्रामीण विकास समिति को दिया गया था. क़रीब आठ माह बाद समिति ने अक्टूबर 2008 में संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की थी. फिर दिसंबर 2008 में मंत्री समूह ने समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों पर सहमति जताई थी और इसे भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक–2009 का नाम देते हुए 25 फ़रवरी, 2009 को लोकसभा में पेश कर दिया गया था, मगर इसके बाद इस विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया.

भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ ग्रेटर नोएडा के गांव भट्टा–पारसौल में किसानों और पुलिस के बीच हुए ख़ूनी संघर्ष के बाद उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने बीते जून माह में नई भूमि अधिग्रहण नीति का ऐलान कर किसानों को मनाने की कोशिश की. इस नई भूमि अधिग्रहण नीति के मुताबिक़ निजी कंपनियों को किसानों से सीधे ज़मीन ख़रीदनी होगी. राज्य सरकार सिर्फ़ मध्यस्थ की भूमिका में होगी और वह सिर्फ़ भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करेगी. निजी कंपनियां उस वक़्त तक किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण नहीं कर पाएंगी, जब तक उस इलाक़े के 70 फ़ीसदी किसान इसके लिए सहमत नहीं हो जाते. नीति में यह भी साफ़ किया गया है कि अधिग्रहीत भूमि का 16 फ़ीसदी हिस्सा विकसित कर संबंधित किसान को नि:शुल्क देना होगा, जिस पर स्टांप शुल्क नहीं लगेगा. भूमि अधिग्रहण की एवज में किसान को 33 साल के लिए 23 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की दर से सालाना भुगतान किया जाना है, जो भूमि प्रतिकर के अतिरिक्त होगा. इस भुगतान पर सालाना 800 रुपये की बढ़ोत्तरी होगी. अगर किसान सालाना भुगतान नहीं लेना चाहेगा तो उसे एकमुश्त 2,76,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से पुनर्वास अनुदान दिया जाएगा. अगर मुआवज़े की राशि से एक साल के भीतर प्रदेश में कहीं भी कृषि भूमि ख़रीदी जाती है तो उसमें भी स्टांप ड्यूटी से पूरी छूट मिलेगी. इसके अलावा निजी कंपनियों को भूमि अधिग्रहण से भूमिहीन हो रहे परिवार के एक सदस्य को नौकरी देनी होगी. भूमि अधिग्रहण से प्रभावित प्रत्येक ग्राम में विकासकर्ता संस्था द्वारा एक किसान भवन का निर्माण अपने ख़र्च पर कराना होगा. इसके अलावा परियोजना क्षेत्र में कक्षा आठ तक एक मॉडल स्कूल खेल के मैदान सहित संचालित करना होगा.

इस नीति में राजमार्ग एवं नहर जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य क़रार नियमावली के तहत आपसी सहमति से तय किया जाना भी शामिल है. ग़ौरतलब है कि 165 किलोमीटर यमुना एक्सप्रेस–वे की 2500 करोड़ की इस योजना के तहत नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा के क़रीब 334 गांवों की ज़मीन अधिग्रहीत की जानी है. इस हाइवे के क़रीब पांच स्थानों पर टाउनशिप और स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बनाए जाने हैं. ये परियोजनाएं जेपी ग्रुप, मोंटी चड्ढा और अन्य बिल्डरों की हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बीते जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में ग्रेटर नोएडा ज़मीन अधिग्रहण मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले को सही बताते हुए ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. जस्टिस जीएस सिंघवी और जस्टिस एके गांगुली की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकारों ने भूमि अधिग्रहण क़ानून को दमन का क़ानून बना दिया है. देश भर में एक ख़तरनाक अभियान चलाया जा रहा है और अंग्रेज़ों के ज़माने के क़ानून के ज़रिए ग़रीबों का दमन किया जा रहा है. अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इससे कुछ बिल्डर फ़ायदा उठाते हैं और ग़रीब किसान बर्बाद हो जाते हैं. अदालत ने पूछा कि मॉल और ऊंची इमारतें बनाना क्या जनहित में है? जजों को बेवकूफ़ न समझा जाए. इससे पहले की सुनवाई में भी अदालत ने सख़्त टिप्पणियां करते हुए कहा था कि वह राज्यों में नंदीग्राम जैसी घटनाएं नहीं चाहती है. यह मामला सुप्रीम कोर्ट में तब आया, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के ग्रेटर नोएडा में 400 हेक्टेयर ज़मीन के अधिग्रहण को ग़ैरक़ानूनी ठहराते हुए रद्द कर दिया था. हाईकोर्ट के इस फ़ैसले के बाद ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण और कुछ डेवलपर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. ग्रेटर नोएडा की इस अधिग्रहीत भूमि पर 50 से ज़्यादा डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे थे. इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्जेंसी कलॉज़ के तहत ज़मीन का अधिग्रहण किया था. इस क्लॉज़ के तहत सरकार किसानों से उनकी आपत्तियां सुने बिना ही ज़मीन अधिग्रहीत कर सकती है. इससे पहले 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए किसानों की 205 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को रद्द करते हुए कहा था कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीक़े से किसी व्यक्ति को उसकी ज़मीन से वंचित नहीं कर सकती. न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति एके गांगुली की खंडपीठ ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 300–ए के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता. ज़मीन के मालिकों राधेश्याम और अन्य ने अदालत में एक याचिका दायर करके मार्च 2008 में किए गए भूमि अधिग्रहण को चुनौती दी थी. उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2007 में भूमि अधिग्रहण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया और इसके बाद किसानों से 850 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से ज़मीन ली गई थी. किसानों का आरोप है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने औद्योगिकीकरण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया था, लेकिन उसे ज़्यादा क़ीमत पर बिल्डरों को बेच दिया गया.

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने किसानों, नोएडा अथॉरिटी और बिल्डरों से मामला आपसी बातचीत के ज़रिए सुलझाने को कहा है. न्यायमूर्ति अमिताव लाला और अशोक श्रीवास्तव की खंडपीठ ने गौतमबुद्ध नगर के दर्जनों गांवों के सैकड़ों किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जो किसान भूमि अधिग्रण के बदले मुआवज़ा लेना चाहते हैं, वे 12 अगस्त तक ले सकते हैं. साथ ही अदालत ने यह मामला बड़ी बेंच को सौंप दिया है. अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी. इन किसानों ने राज्य सरकार द्वारा क़रीब 3000 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण को चुनौती दी थी. अदालत ने निवेशकर्ताओं और बिल्डरों की याचिका पर कोई आदेश पारित नहीं किया. निवेशकर्ताओं ने नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट बायर्स एसोसिएशन के बैनर तले, बिल्डरों के साथ ख़ुद को इस मामले में पार्टी बनाने की अपील की थी. अदालत को बिसरख, रोजा याक़ूबपुर और हैबतपुर की कुल 3251 एकड़ ज़मीन के अधिग्रहण पर फ़ैसला सुनाना है. इसके साथ ही नोएडा एक्सटेंशन के क़रीब एक लाख फ्लैटों का भविष्य तय हो जाएगा. 12 मई को अदालत ने शाहबेरी गांव की 388 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण रद्द कर दिया था. इससे क़रीब साढ़े आठ हज़ार फ्लैट अधर में लटक गए थे. इसके बाद अदालत ने 21 जुलाई को गांव पतवाड़ी की 450 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण रद्द कर दिया था. अदालत के इस फ़ैसले से क़रीब 20 हज़ार फ्लैट खटाई में पड़ गए. अगर अदालत ने इन तीनों गांवों की ज़मीन का अधिग्रहण रद्द कर दिया तो ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन की कुल 4089 एकड़ ज़मीन किसानों को वापस करनी पड़ेगी. नोएडा एक्सटेंशन कुल 13 गांवों की 8607 एकड़ ज़मीन को मिलाकर बना है. अगर इसमें से 4089 एकड़ ज़मीन घटा दी जाए तो नोएडा एक्सटेंशन के नाम पर महज़ 4518 एकड़ ज़मीन बचेगी यानी आधा नोएडा एक्सटेंशन ख़त्म हो जाएगा. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने गांव शाहबेरी और पतवाड़ी में अधिग्रहण रद्द किए जाने के बाद यहां लगे बिल्डरों के होर्डिंग्स हटवा दिए. इसके अलावा किसानों ने भी कार्यस्थलों पर जाकर वहां चले रहे निर्माण कार्यों को रुकवा दिया. किसानों के विरोध के कारण नोएडा एक्सटेंशन के फ्लैटों का निर्माण ख़तरे में पड़ गया है. नोएडा में अब तक बिल्डरों ने एक लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा धनराशि का निवेश कर रखा है. नोएडा में यूनिटेक, लोटस, अजनारा, सुपरटेक और ओमैक्स समेत क़रीब 26 बिल्डरों के प्रोजेक्ट बन रहे हैं. इसके साथ ही नोएडा में फ्लैट बुक कराने वाले लोगों पर भी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है. असंख्य लोगों ने यहां घर ख़रीदने के लिए अपनी जमा पूंजी लगाने के अलावा बैंकों से भी क़र्ज़ लिया था. इन परियोजनाओं में क़रीब 25 हज़ार करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है. अदालतों द्वारा भूमि अधिग्रहण रद्द किए जाने से उनके आशियाने के सपने पर बिजली गिर पड़ी है. किसानों के बाद निवेशकों ने भी अदालत की शरण ली है. 20 जुलाई को नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट बायर्स एसोसिएशन (एनईएफबीडब्ल्यूए) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर आग्रह किया है कि भूमि अधिग्रहण मामले पर फ़ैसला करने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए. बीती 23 जुलाई को एनईएफबीडब्ल्यूए के बैनर तले निवेशकों ने पैदल मार्च निकाल कर विरोध जताया. उनका कहना था कि हमें पैसा नहीं घर चाहिए, हमें भी न्याय चाहिए. उनका कहना था कि सरकार किसानों को वाजिब मुआवज़ा दिलाकर उनके घर के सपने को टूटने से बचाए. हालांकि बिल्डरों का कहना है कि अदालत का आदेश कुछ फ्लैटों के लिए है, पूरे एक्सटेंशन को लेकर परेशानी की कोई बात नहीं है. बिल्डरों को यह ख़ौफ़ ज़रूर है कि अगर सभी किसान अदालत चले गए तो उनका भारी नुक़सान हो सकता है. बिल्डरों ने भी सरकार से इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की है. कंफेडरेशन ऑफ रीयल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों गीतांबर आनंद, अनिल शर्मा, आरके अरोड़ा एवं मनोज गौड़ का कहना है कि सरकार और अथॉरिटी को ऐसा तरीक़ा अपनाना चाहिए, जिससे फ्लैट बुक कराने वालों के साथ–साथ उनके नुक़सान की भी भरपाई हो सके. एक अनुमान के मुताबिक़, विभिन्न बैंकों के क़रीब 1200 करोड़ रुपये फंस गए हैं. हालांकि बैंकों ने इस मामले में अभी तक ख़ामोशी अख्तियार कर रखी है. बताया जा रहा है कि इस मामले में बैंक ख़ुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अलावा बिल्डरों और निवेशकों को भी क़र्ज़ दिया है यानी एक ही संपत्ति के लिए तीन–तीन क़र्ज़ दिए गए. इन परियोजनाओं में सबसे ज़्यादा पैसा भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कारपोरेशन बैंक और आईसीआईसीआई का लगा हुआ है. फ़िलहाल बैंकों ने नोएडा एक्सटेंशन के फ्लैटों के लिए क़र्ज़ देने पर पाबंदी लगा दी है. नोएडा एक्सटेंशन में निर्माण कार्य में लगे कॉन्ट्रेक्टरों ने भी कार्य रोके जाने पर रोष जताते हुए प्रदर्शन किया. उनका कहना है कि अदालत के आदेश से उनका कामकाज ठप हो गया है. साथ ही निर्माण कार्यों में लगे हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए हैं.

उधर,केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण से पैदा हुए हालात में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से इंकार किया है. उधर, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण से पैदा हुए हालात में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से इंकार किया है. उनका कहना है कि यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह इस मामले का समाधान कराए. अब सरकार, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, बिल्डरों और निवेशकों को 17 अगस्त के फ़ैसले का इंतज़ार है. बहरहाल, सभी की कोशिश है कि मामला आपसी सहमति से ही सुलझा लिया जाए.

firdaus@chauthiduniya.com

क्या है भूमि अधिग्रहण क़ानून

संपत्ति का अधिग्रहण और मांग भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची द्वारा समवर्ती सूची में सूचीबद्ध विषय है. ऐसे अनेक स्थानीय और विशिष्ट कानून हैं, जो भूमि अधिग्रहण के लिए हैं, लेकिन मुख्य क़ानून जो भूमि के अधिग्रहण से संबंध रखता है, वह है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894. ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्रीय सरकार का नोडल मंत्रालय है, जो भूमि अधिग्रहण पर केंद्रीय विधान का प्रशासन करता है, जबकि शहरी विकास मंत्रालय शहरी भूमि (उच्चतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 और शहरी भूमि (उच्चतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम 1999 का प्रशासन करता है. राज्यों में शहरी संपदाओं के समग्र विकास के लिए अनेक शहरी विकास प्राधिकरण होते हैं. साथ ही ऐसे विभिन्न विभाग हैं, जो भूमि अधिग्रहण, आवास, मूल संरचना, शहर की योजना आदि से संबंधित मामले निपटाते हैं, जैसे ग्रामीण विकास विभाग, योजना विभाग एवं भूमि विभाग.

उत्तराखण्ड उत्कर्ष की ओर...

अटल खाद्यान्न योजना

महंगाई से राहत
मात्र 100 रूपये में महीने का राशन

- बी.पी.एल. कार्ड धारकों के लिए
  - 2 रू. प्रति किलो गेंहू
  - 3 रू. प्रति किलो चावल
- ए.पी.एल. कार्ड धारकों के लिए
  - 4 रू. प्रति किलो गेंहू
  - 6 रू. प्रति किलो चावल

उत्तराखण्ड के मेरे सम्मानित
बहिनों एवं भाइयों,

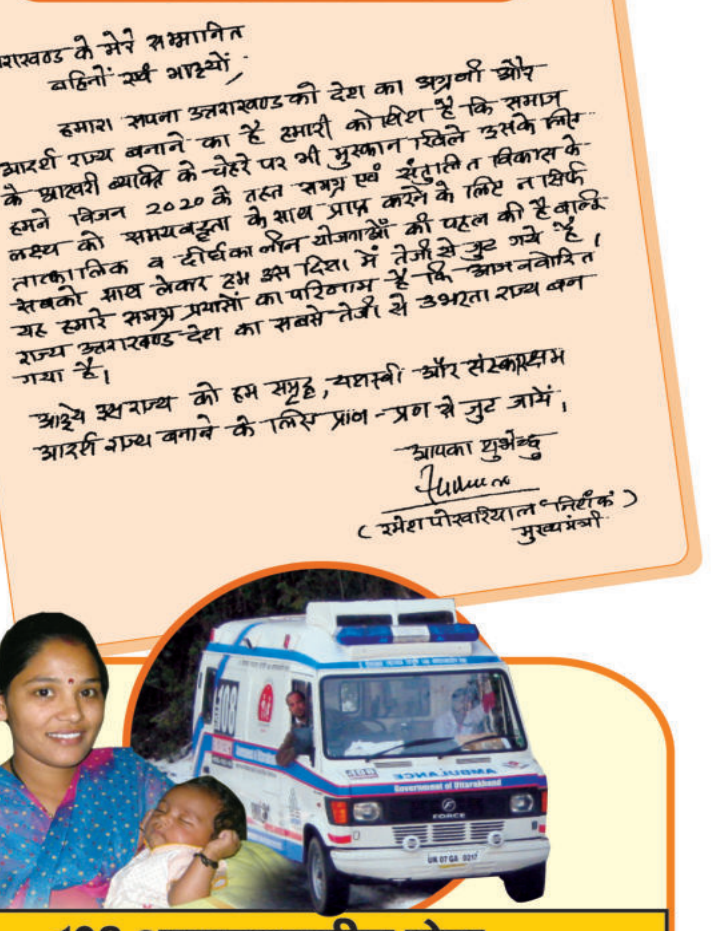

हमारा सपना उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी और आदर्श राज्य बनाने का है। हमारी कोशिश है कि समाज के आखरी व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान खिले उसके लिए हमने विजन 2020 के तहत समग्र एवं संतुलित विकास के लक्ष्य को समयबद्धता के साथ प्राप्त करने के लिए न सिर्फ तात्कालिक व दीर्घकालीन योजनाओं की पहल की है बल्कि सबको साथ लेकर हम इस दिशा में तेजी से जुट गये हैं। यह हमारे समग्र प्रयासों का परिणाम है कि आज नवोदित राज्य उत्तराखण्ड देश का सबसे तेजी से उभरता राज्य बन गया है।

आइये इस राज्य को हम समृद्ध, यशस्वी और संस्कारक्षम आदर्श राज्य बनाने के लिए प्राण-प्रण से जुट जायें।

आपका शुभेच्छु
(रमेश पोखरियाल 'निशंक')
मुख्यमंत्री

स्पर्श गंगा अभियान – निर्मल गंगा

निर्मल नीर की अनूठी पीर

- गंगा और उसकी सहायक नदियों की निर्मलता और स्वच्छता को बनाये रखने के लिए 'स्पर्श गंगा अभियान'।
- लगभग एक लाख युवा इस अभियान से प्रारम्भिक रूप से जुड़े। स्पर्श गंगा बोर्ड का गठन।
- 17 दिसम्बर को गंगा सफाई दिवस घोषित।
- निर्मल गंगा–स्पर्श गंगा का चारों धामों से शुभारम्भ।
- गंगा का संरक्षण – राज्य सरकार का संकल्प।

आशीर्वाद योजना के तहत उद्योगों में प्रशिक्षण

रोजगार के खुले द्वार

- 50 हजार युवाओं के लिए रोजगार का लक्ष्य
- लगभग 21 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरु
- 4 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती
- आशीर्वाद योजना बनी निर्धन एवं दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार देने का माध्यम। इस योजना के तहत निजी कम्पनियों द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के साथ विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

108 आपातकालीन सेवा

पं० दीनदयाल उपाध्याय देवभूमि '108' आपातकालीन सेवा

- अब तक 51 लाख से अधिक लोगों की बनी सहारा
- 3 लाख से ऊपर आपातकालीन सेवा का बना रिकार्ड
- 2 लाख लोगों को 'जीवन–दान' का विश्व कीर्तिमान
- एक लाख से अधिक गर्भवती बहनों को मिला नया जीवन
- सड़क दुर्घटनाओं में 36 हजार से अधिक की बचायी जान
- पहाड़, नदी–नाले फाँदते चलती एम्बुलेन्स में ही 2474 से अधिक शिशुओं के जन्म का अनूठा विश्व कीर्तिमान

अटल आदर्श ग्राम योजना

गाँवों का समग्र विकास
न्याय पंचायतों में अटल मिनी सचिवालय

- 670 न्याय पंचायतों में अटल मिनी सचिवालय स्थापित।
- 16 विभाग इस योजना में शामिल, जिससे ग्राम स्तर पर सभी अवस्थापना सुविधाऐं जैसे बिजली, पानी, चिकित्सा स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आदि मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध।

उत्तराखण्ड : देश में अग्रणी राज्य

- तेजी से उभरते राज्यों में नम्बर 1 राज्य।
- आर्थिक विकास की दर 2.9 प्रतिशत (राज्य गठन के समय) से बढ़कर आज 11.30 प्रतिशत।
- राजस्व प्राप्तियां 2 हजार 733 करोड़ से बढ़कर आज 14 हजार 633 करोड़।
- औद्योगिक निवेश 5 हजार 500 करोड़ से बढ़कर अब 30 हजार करोड़ से ऊपर।
- उद्योगो में अब तक 1.5 लाख लोगों को रोजगार।
- पहाड़ के लिए विशेष औद्योगिक नीति, 200 करोड़ का पूंजी निवेश।
- पर्यावरण वन संरक्षण में भी उत्तराखण्ड देश में शीर्ष पर।
- राज्य के 96 प्रतिशत से अधिक ग्राम विद्युतीकृत जो राष्ट्रीय औसत से आगे है।
- देववाणी संस्कृत को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य।
- आयुष क्षेत्र में भी उत्तराखण्ड देश में शीर्ष पर।
- सैनिको को आर्थिक सुविधाएं देने वाला पहला राज्य।
- बीपीएल परिवार की कन्याओं को इण्टर पास करने पर 25 हजार रूपये की एफ.डी.।
- गांव–गांव पहुँच रहे हैं सभी सुविधाओं से युक्त डॉ हेडगेवार सचल चिकित्सा वाहन।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शीघ्र ही पूरे प्रदेश में।

विज़न 2020: पाँच सूत्र

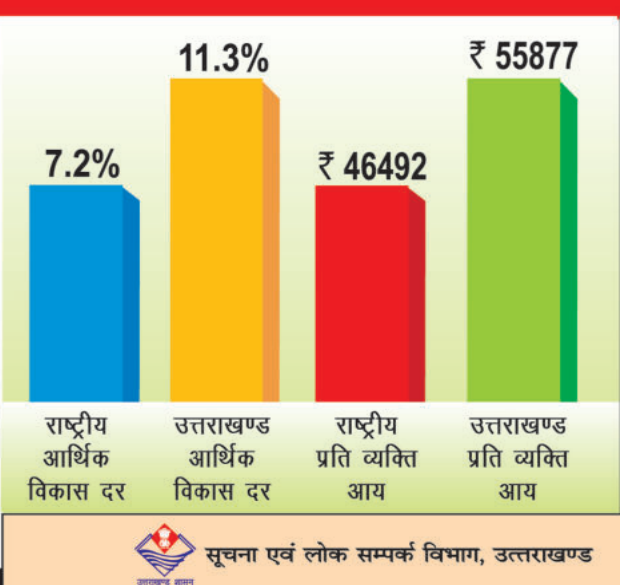

समृद्ध उत्तराखण्ड
शिक्षित उत्तराखण्ड
स्वस्थ उत्तराखण्ड
सुसंस्कृत उत्तराखण्ड
हरित उत्तराखण्ड

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

विदर्भ जन आंदोलन समिति ने राजनाथ की यात्रा पर कई सवाल उठाए हैं. समिति का कहना है कि राजनाथ सिंह को विदर्भ की ज़मीनी हक़ीक़त का पता नहीं है.

बिहार

पांच हज़ार एकड़ भूमि पर माओवादी प्रतिबंध

सुनील सौरभ

प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने ज़िले के विभिन्न प्रखंडों में सौ से अधिक लोगों की लगभग पांच हज़ार एकड़ भूमि पर आर्थिक नाकेबंदी लगा रखी है, जिसके कारण पिछले कई वर्षों से इस भूमि पर खेती नहीं हो पा रही है. माओवादियों के डर से प्रतिबंधित भूमि पर कोई भी व्यक्ति बटाई खेती करने के लिए भी तैयार नहीं है. जिन लोगों की भूमि पर खेती प्रतिबंधित की गई है, उनमें अधिकांश अपने-अपने गांव छोड़कर ज़िला मुख्यालय गया अथवा अन्य शहरों में रह रहे हैं. जो लोग गांव में रह रहे हैं, माओवादियों द्वारा खेती पर प्रतिबंध लगा देने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है. बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी-विवाह तक के सारे कार्य ठप्प हैं. माओवादियों के डर से कोई इन लोगों की भूमि ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है. प्रशासन भी इनकी मदद के लिए कोई कारगर क़दम नहीं उठा रहा है. गया के तत्कालीन जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को इस आर्थिक नाकेबंदी को गंभीरता से लेने और वहां खेती शुरू कराने का निर्देश दिया था. कुछ प्रखंडों में अंचलाधिकारियों और थानाध्यक्षों की सक्रियता से प्रतिबंधित भूमि पर खेती शुरू भी की गई, लेकिन इन अधिकारियों के जाते ही माओवादी पुन: हावी हो गए और उन्होंने किसानों एवं भू-स्वामियों पर फिर से आर्थिक नाकेबंदी लगा दी. शेरघाटी अनुमंडल पर इस प्रतिबंध का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है. इस अनुमंडल की तक़रीबन चार हज़ार एकड़ भूमि पर माओवादियों ने प्रतिबंध लगा रखा है. घोर नक्सल प्रभावित डुमरिया में एक हज़ार एकड़ से अधिक भूमि प्रतिबंधित है. नारायणपुर पंचायत के चोनहा गांव के पूर्व मुखिया मसूद अहमद ख़ां उर्फ़ छोटे ख़ां, पिपरा गांव के मेन सिंह एवं पिपरवार गांव के छट्ठन ख़ान की कई एकड़ भूमि पर माओवादियों ने वर्षों से प्रतिबंध लगा रखा है. इसी प्रकार बांके बाज़ार प्रखंड के विभिन्न गांवों में क़रीब पांच सौ एकड़ भूमि प्रतिबंधित की गई है, जिनमें विशनपुर गांव में पूर्व ज़मींदार गया लाल एवं टोहा लाल और अंबाखार के पूर्व मुस्लिम ज़मींदार की ज़मीनें शामिल हैं. इमामगंज प्रखंड में क़रीब पांच सौ एकड़, गुरुआ प्रखंड में पांच सौ एकड़, आमस प्रखंड में तीन सौ एकड़ और बाराचट्टी प्रखंड में क़रीब दो सौ एकड़ भूमि पर नक्सलियों ने प्रतिबंध लगा रखा है, जिसके कारण वर्षों से उक्त ज़मीनें ख़ाली पड़ी हैं. प्रतिबंधित की गई ज़मीनों का मालिकाना हक़ रखने वाले अधिकांश लोग बड़े भूपति और ज़मींदार रह चुके हैं.

माओवादियों ने इन पर ग़रीबों का शोषण और पुलिस के लिए मुख़बिरी करने का आरोप लगाकर उन्हें अपनी हिट लिस्ट में शामिल कर रखा है. माओवादियों के भय से इन लोगों ने अपना गांव ही छोड़ दिया और कोई इनकी ज़मीनें ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है. ज़िले के टेकारी अनुमंडल का कोच प्रखंड भी पिछले दो दशकों से नक्सलियों की गिरफ़्त में है. यहां भी क़रीब एक हज़ार एकड़ भूमि पर माओवादियों ने प्रतिबंध लगा रखा है. इस प्रखंड के अमरा, कुरमावां, गौहरपुर, खबासपुर एवं कमलबिघा आदि गांवों में भी बड़े भूपतियों की क़रीब एक हज़ार एकड़ भूमि पर माओवादियों ने प्रतिबंध लगा रखा है. कुरमावां निवासी रंजीत सिंह और उनके परिवार की सैकड़ों एकड़ भूमि पर नक्सलियों ने वर्षों से प्रतिबंध लगा रखा था. पिछले साल उनकी भूमि को प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन इस बार पुन: उनकी सारी भूमि पर लाल झंडा लगाकर नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने आर्थिक नाकेबंदी लगा दी. इस प्रकार ज़िले में क़रीब पांच हज़ार एकड़ भूमि पर खेती नहीं हो पा रही है. इस मामले में किसानों एवं भूपतियों को ज़िला प्रशासन की ओर से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है. छोटे किसान आर्थिक नाकेबंदी के चलते भुखमरी की स्थिति में पहुंच गए हैं और उनके बच्चों की शादियां तक नहीं हो पा रही हैं.

प्रशासन भी इनकी मदद के लिए कोई कारगर क़दम नहीं उठा रहा है. गया के तत्कालीन जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को इस आर्थिक नाकेबंदी को गंभीरता से लेने और वहां खेती शुरू कराने का निर्देश दिया था.

feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र

राजनाथ का विदर्भ दौरा सवालों के घेरे में

राजेश नामदेव

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह की विदर्भ यात्रा पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं. उनकी इस यात्रा को कुछ संगठन व्यक्तिगत यात्रा तक क़रार दे रहे हैं और पार्टी की नीति पर भी प्रश्नचिन्ह लग रहे हैं. भाजपा नेताओं की औद्योगिक इकाइयों द्वारा भी किसानों की ज़मीन हड़पने का आरोप लगाया जा रहा है. इससे राजनाथ की विदर्भ यात्रा विफल होती लग रही है. ग़ौरतलब है कि राजनाथ सिंह ने किसानों द्वारा आत्महत्या के लिए चर्चित यवतमाल एवं चंद्रपुर ज़िले का दौरा करके वहां के लोगों की व्यथा कथा सुनी थी. किसानों की समस्याओं की जानकारी लेने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र और केंद्र सरकार से मांग की थी कि वे अपनी कृषि नीति का ख़ुलासा करें. उन्होंने सरकार द्वारा किसानों की ज़मीन अधिग्रहीत करने पर भी सवाल उठाए और इन गंभीर मुद्दों पर राज्य एवं केंद्र में सत्तारूढ़ दल को ललकारा, परंतु अब उनकी यह यात्रा विवादों में पड़ती नज़र आ रही है. विदर्भ जन आंदोलन समिति ने राजनाथ की यात्रा पर कई सवाल उठाए हैं. समिति का कहना है कि राजनाथ सिंह को विदर्भ की ज़मीनी हक़ीक़त का पता नहीं है. उनकी ही पार्टी के कई नेताओं के कई प्रोजेक्ट किसानों की ज़मीन पर खड़े हैं. इसलिए राजनाथ सिंह को पहले अपनी पार्टी की नीति स्पष्ट करनी चाहिए. उन्हें पहले यह पता करना चाहिए कि उनकी पार्टी के नेताओं के प्रोजेक्ट कहां-कहां हैं और उनकी वस्तुस्थिति क्या है? उसके बाद ही उन्हें किसी और पर कोई आरोप लगाना चाहिए.

समिति का कहना है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के उद्योग समूह पूर्ति द्वारा यवतमाल में बिजली उत्पादन प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना है. यदि यह योजना साकार होती है तो इससे सैकड़ों किसानों का भूमिहीन होना तय है. इसके अलावा भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र की सीमा पर अदानी समूह द्वारा बिजली प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसे पानी पेंच से दिया जाएगा, जिससे नागपुर ज़िले को पेयजल की आपूर्ति की जाती है. यदि पेंच का पानी अदानी समूह के बिजली प्लांट को दिया जाएगा तो भविष्य में नागपुर की जलापूर्ति प्रभावित होना स्वाभाविक है. इससे क्षेत्र के खेतों को सिंचाई के लिए मिलने वाले पानी में भी कमी आने की आशंका है. ऐसी स्थितियों के बावजूद भाजपा के राष्ट्रीय नेता अपनी सुविधा के स्थानों पर जाकर किसानों के हितों की बात करते हैं और अपनी पार्टी के नेताओं द्वारा निजी प्रोजेक्ट स्थापित करने और सरकार द्वारा उनके लिए किसानों की ज़मीन अधिग्रहीत करने के मामलों को अनदेखा कर देते हैं. किसानों के हक़ का पानी निजी समूहों को देना राजनाथ सिंह को दिखाई नहीं देता.

विदर्भ जन आंदोलन समिति के अध्यक्ष किशोर तिवारी का कहना है कि भाजपा को पहले विदर्भ सहित मध्य भारत में प्रस्तावित 116 बिजली परियोजनाओं और उनसे प्रभावित होने वाले किसानों एवं ग्रामवासियों के बारे में अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि राजनाथ सिंह द्वारा यवतमाल एवं चंद्रपुर ज़िले का दौरा करके जो किसान-आदिवासी प्रेम प्रकट किया गया, वह मात्र दिखावा था. कोलुरा एवं बिजोरा में स्थित प्रोजेक्ट से कई किसान-आदिवासी प्रभावित हुए हैं. यह प्रोजेक्ट भाजपा के उत्तम इगले और मदन येरावार केहैं, इस संबंध में राजनाथ सिंह ने कुछ नहीं कहा. इसलिए उन्हें यवतमाल में बैठकर राहुल गांधी को सलाह देने के बजाय भाजपा की कार्यकारिणी में चर्चा करके किसानों के हित में एक ठोस कृषि नीति बनानी चाहिए. तिवारी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सहित मध्य भारत में प्रस्तावित 116 बिजली परियोजनाओं में से 40 से अधिक मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाली हैं. इन परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए नितिन गडकरी का पूर्ति उद्योग समूह विशेष रूप से सक्रिय है. विदर्भ के कपास उत्पादक किसान भी राजनाथ सिंह के कारण ही आज संकट में हैं. कपास उत्पादकों के सामने आज जो आर्थिक संकट है, उसके ज़िम्मेदार राजनाथ सिंह हैं. केंद्र में एनडीए सरकार के दौरान जब वह मंत्री थे, तब उनकी खुली आयात-निर्यात नीति और बीज प्रसंस्करण के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को मुक्त प्रवेश देने के कारण आज किसानों को कई तरह की दिक्क़तों का सामना करना पड़ रहा है. इसी नीति की वजह से किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा. आज वही राजनाथ सिंह किसानों के हितों की बात कर रहे हैं, आत्महत्या करने वाले किसानों की विधवाओं के पुनर्वास की गुहार लगा रहे हैं.

तिवारी का कहना है कि यह किसानों का दुर्भाग्य है कि जिस व्यक्ति की नीतियों की वजह से वे संकट में हैं, वही आज उनके हितों की बात कहकर राजनीति कर रहा है. ऐसे में भला कैसे विश्वास किया जा सकता है कि भाजपा किसानों के संघर्ष में उनके साथ खड़ी होगी. राजनाथ सिंह ने चंद्रपुर ज़िले की वणी तहसील का दौरा किया और वेकोलि खदान से प्रभावित ग्रामवासियों की समस्याओं को सुना और समझा, मगर उन्होंने झरी तहसील जाकर रिलायंस प्रेजेंटेशन कंपनी द्वारा पीड़ित किसानों की समस्याएं सुनने की ज़रूरत नहीं समझी. रिलायंस ने यहां पिछले कई महीनों से बेहद कम राशि में किसानों की ज़मीन की ख़रीद शुरू कर दी है. किसानों का कहना है कि भाजपा सांसद हंसराज अहीर से भी उनकी उम्मीद ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि जब भी जाओ, वह मात्र आश्वासन देकर टाल देते हैं. राजनाथ सिंह एक ओर यवतमाल-चंद्रपुर के किसानों की समस्याएं सुनने के लिए विदर्भ का दौरा कर रहे हैं, पर अमरावती जिले के किसानों को वह भूल गए. जब बुल इंडिया का सोफिया प्रोजेक्ट चल रहा था, तब राजनाथ सिंह को उनकी याद क्यों नहीं आई. तब उन्होंने किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा. अब ऐसा क्या हो गया कि उन्हें विदर्भ के किसानों की याद सताने लगी. अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है. कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी वहां पूरे राज्य का दौरा करके किसानों, दलितों एवं ग़रीबों की दुआएं बटोर रहे हैं. ऐसे में विदर्भ आकर राजनाथ सिंह क्या बताना चाहते हैं? यह सवाल पार्टी कार्यकर्ता आपस में कर रहे हैं. इस समय राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश के किसानों की अधिक चिंता होनी चाहिए. कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह यह जताना चाहते हों कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्षेत्र विदर्भ है, जो किसानों की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. शायद ऐसे में राजनाथ सिंह यह जताना चाहते हैं कि वह विदर्भ के किसानों की चिंता पार्टी अध्यक्ष से ज़्यादा कर रहे हैं. यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि राजनाथ सिंह के विदर्भ दौरे को पार्टी नेताओं ने भी ख़ास तवज्जो नहीं दी. उनके साथ यवतमाल एवं चंद्रपुर के कार्यकर्ता ही देखे गए. पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता उनके साथ दौरे पर नहीं गया, जबकि महाराष्ट्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गृहराज्य है और विदर्भ उनका क्षेत्र. इसके अलावा प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार चंद्रपुर ज़िले के ही रहने वाले हैं. उनकी अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी हुई है. राजनाथ सिंह के दौरे पर उठे सवालों को लेकर पार्टी क्या रुख़ अपनाती है, यह भविष्य में ही पता चलेगा, मगर इससे यह ज़रूर साबित हो गया कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है.

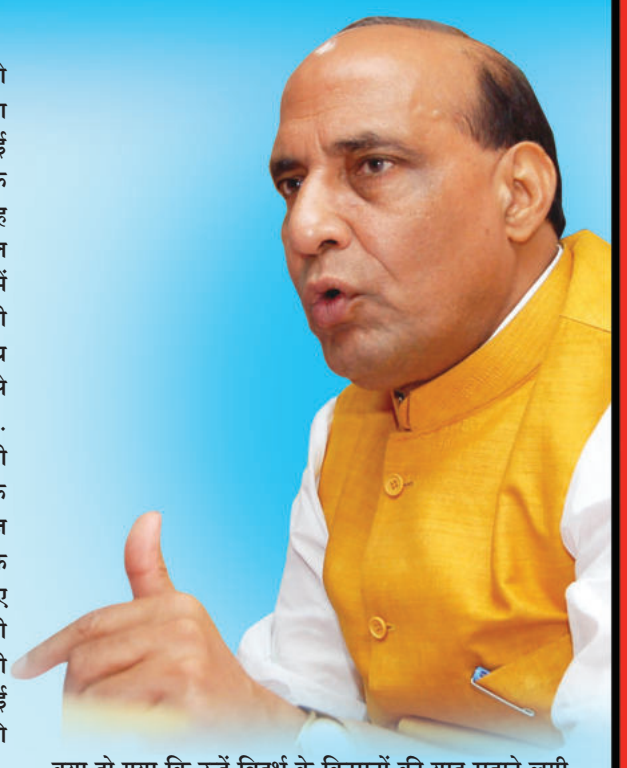

feedback@chauthiduniya.com

सवाल है कि अगर भारतीय दंड संहिता की धारा 120, 153-ए 153, 302 एवं 307 बी के तहत ठीक से अपराधों की जांच की जाती तो क्या संभव था कि मोदी की टोली, आडवाणी की टोली अब तक जेल की सलाख़ों के पीछे नहीं गई होती.

सांप्रदायिक दंगा निरोधक विधेयक

मौजूदा क़ानून कहां से कमतर नहीं

वसी अहमद नोमानी

भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के बावजूद देश में टाडा जैसे क़ानून लागू हुए, मगर अपराध फैलते ही रहे. परिणाम यह हुआ कि जनता की मांग के मद्देनज़र न्याय की प्राप्ति के लिए 2005 और 2009 में विभिन्न सिफ़ारिशों एवं संशोधनों पर आधारित नया विधेयक प्रस्तुत किया गया. अब 2011 में पुराने क़ानूनों में संशोधन करके नया बिल पेश कर दिया गया है. आश्चर्य की बात है कि सबकी ख़ुशफ़हमी यह है कि बस अब तो दंगे-फ़साद बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और गुजरात, अयोध्या जैसे कांड दोबारा नहीं होंगे. ऐसी भावनाओं की क़द्र की जानी चाहिए, मगर इतनी मासूमियत पर तरस भी आता है. सवाल है कि अगर भारतीय दंड संहिता की धारा 120, 153-ए 153, 302 एवं 307 बी के तहत ठीक से अपराधों की जांच की जाती तो क्या संभव था कि मोदी की टोली, आडवाणी की टोली अब तक जेल की सलाख़ों के पीछे नहीं गई होती. क्या दुनिया के किसी क़ानून में फांसी से बड़ी सज़ा कोई और हो सकती है? हरगिज़ नहीं. अब आप कौन सा क़ानून लाकर ऐसे अपराधों को रोकना चाहते हैं?

क्या इस बात पर विश्वास करना संभव है कि मौजूदा बिल के क़ानून बनने के बाद गुजरात और अयोध्या दोहराए नहीं जाएंगे. ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि क़ानून बनने के बावजूद उसे लागू करने की ज़िम्मेदारी उसी मानसिकता के लोगों को दिए जाने की बात कही गई है, जो वर्तमान व्यवस्था के मुखिया हैं. यह बात ज़रूर मानी जा सकती है कि नई-नई नीतियों और उनकी सराहना करके उन्हें नए शब्दों में ढालने की कोशिश की गई है, जैसे Assault, Sexual, Group Trageted Attack आदि. अलग-अलग गतिविधियों को नए शब्दों में बांधकर बिल को विस्तृत रूप दिया गया है और इसमें भारत के वर्तमान क़ानूनों के संशोधित रूप को शामिल किया गया है. साथ ही अनगिनत धाराओं को उनके अपने वास्तविक एक्ट से लेकर वर्तमान सांप्रदायिक दंगा निरोधक विधेयक 2011 में शामिल कर दिया गया है. यही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ आदि के क़ानूनों को भी इसमें शामिल किया गया है. इस तरह विधेयक प्रगतिशील, विस्तृत और नया लगता है, मगर असली जिन्न जो बोतल में बंद है, उसे खोलकर सज़ा देने के लिए कोई बेहतर उपाय इसमें न के बराबर हैं. इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि एक और धारा इस बिल में जोड़ी जाए कि देश एक ऐसा विभाग गठित करेगा, जो ईमानदार, मानवतावादी, ग़रीबों, पीड़ितों, मासूमों, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए सोचने वाले, क़ानून से डरने वाले, अपनी अंतर्रात्मा से डरने वाले प्रतिनिधि और अधिकारी पैदा करेगा. ऐसे कारख़ाने का निर्माण संभव नहीं है. इसलिए कोई भी एक्ट या क़ानून कारगर नहीं है. फिर क्या क़ानून बनना ही नहीं चाहिए? ज़रूर बनना चाहिए, मगर क़ानून सिर्फ़ दोहराए न जाते रहें, बल्कि जो क़ानून हैं उन्हें उसी भावना से लागू किया जाए, जिस भावना के साथ वे बनाए गए थे.

मौजूदा विधेयक की धाराओं से बिल्कुल साफ़ लगता है कि सरकार ने सिफ़ारिशों को व्यवहारिक रूप देने की कोशिश की है, लेकिन इस बात पर कम तवज्जो दी गई है कि आख़िर धाराओं को लागू करने वाली ईमानदार मशीनरी कहां गढ़ी जाएगी? चलिए इस जवाब का इंतज़ार किया जाए. हो सकता है कि ईमानदार अधिकारियों और ईमानदार प्रतिनिधियों की पैदावार के लिए कोई बेहतर कारख़ाना अस्तित्व में आ जाए और इस देश का भाग्य बदल जाए. इस मुद्दे पर वापस आया जाए कि यह विधेयक दूरदर्शिता पर आधारित है, क्योंकि इसे विभिन्न हादसों, घटनाओं, अनुभवों और ज़रूरत के अनुसार लाभकारी रूप में बनाया गया है. देश में सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं और इनकी आशंका लगातार बनी रहती है, इसलिए इनकी रोकथाम के लिए ऐसा क़ानून बनाया जाना चाहिए. यही कारण है कि केंद्र सरकार ने क़ानून बनाने का फ़ैसला किया तो भारतीय संविधान के विभिन्न अधिनियमों और संयुक्त राष्ट्र संघ की अनेक धाराओं को लेकर इस नए विधेयक 2011 को अंतिम रूप दिया गया. इस विधेयक में कुछ धाराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं. साथ ही बहुत से क़ानूनों एवं उनकी धाराओं की पूर्व की कमियों को दूर करके इसमें नयापन पैदा करने की कोशिश की गई है.

इस विधेयक का अधिकांश भाग पुराने भारतीय क़ानूनों और उनकी विभिन्न धाराओं पर ही आधारित है यानी दो तिहाई क़ानून जो इस विधेयक में पेश किए गए हैं, वे पहले से ही मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद दंगे, अत्याचार, बलात्कार एवं हत्या जैसे अपराध नियंत्रित नहीं हो पा रहे हैं. इस समय तो यह स्थिति है कि अव्यवस्था, भ्रष्टाचार एवं लापरवाही को लेकर जब भी सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद होती है तो पूरा देश एकजुट नज़र आता है. अन्ना हज़ारे और उनका अभियान क़ानून और न्याय के प्रति लोगों के रोष को ज़ाहिर करता है. ऐसी स्थिति में यह विधेयक क्या प्रभाव दिखाएगा, जगज़ाहिर है. अगर यह विधेयक ईमानदारी से लागू किया गया तो न जाने कितने अभियान जन्म लेंगे और दोषियों को सबक़ सिखाएंगे. इस विधेयक में शामिल दो तिहाई क़ानून का 10 प्रतिशत भाग भी ठीक से लागू कर दिया जाता है तो भारत की 60 प्रतिशत समस्याएं ख़ुद-ब-ख़ुद हल हो जाएंगी. अगर दो तिहाई क़ानून का ही सिर्फ़ 90 प्रतिशत भाग लागू करने के लिए सिर्फ़ पांच प्रतिशत ईमानदार अधिकारी मिल जाएं तो इस विधेयक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. क़ानून बनाने की ज़रूरत उस स्थिति में पड़ती है, जब अव्यवस्था फैलने लगती है और यह तब होता है, जब क़ानून को गूंगा और असक्षम समझ लिया जाता है, जैसा कि अब तक हमारे मौजूदा क़ानूनों के साथ होता चला आया है, जहां अपराधी आज़ाद घूमते हैं और निर्दोष जेल में ज़िंदगी गुज़ारने के लिए मजबूर कर दिए जाते हैं.

हम नई धाराओं और शक की रोशनी में स्थिति का अध्ययन और इस बात की कोशिश करेंगे कि जनता के सामने स्वदेशी, अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों से लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जिस विधेयक का निर्माण किया गया है, संसद में पेश होने के बाद उसका हश्र क्या होगा, इस सिलसिले में भाजपा नेता इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं. अगर यह विधेयक पारित भी हो गया तो भारत के भाग्य पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इसकी 138 धाराओं में से सिर्फ़ सात धाराओं को ईमानदारी से लागू किया गया तो भारत स्वर्ग बन जाएगा, अन्यथा सिर्फ़ यही कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार 2004 के चुनाव में किए गए अपने वायदे के मुताबिक़ और 2014 के आम चुनाव के मद्देनज़र यह विधेयक लाकर मुसलमानों को बहलाना चाहती है.

(लेखक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं)

feedback@chauthiduniya.com

क़ानून, जिनकी मदद से बिल का प्रारूप तैयार हुआ

1. इंडियन पैनल कोड
2. क्रिमिनल एक्ट
3. विटनेस एक्ट 1872
4. प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसिज बिल 2011
5. अन लॉ फुल एक्टिविटी (प्रीवेंशन) एक्ट 1967
6. नेशनल कमीशन फ्रॉर वूमेन एक्ट 1990
7. प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988
8. द प्रीवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल 2010
9. द विटनेस आइडेंटिटी प्रोटेक्शन बिल 2006
10. द एचआईवी, एआईडी एक्ट 1993
11. भारतीय दंड संहिता 1860
12. महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ़ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) 1999
13. प्रोटक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993
14. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट
15. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पलाइमेंट गारंटी एक्ट 2005
16. द फीटल एक्सीडेंट एक्ट 1885
17. द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885

संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित धाराएं

1. संयुक्त राष्ट्र कंवेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड क्रिवेल ऑन ह्यूमन या डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट या पनिशमेंट 1984
2. रोम स्टेच्यूएट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 1998
3. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट रूम स्टेच्यूएट 1998

मेरी दुनिया.... कलमाडी की याद्दाश्त

संस्कृत के शब्द हिम (बर्फ़) और आलय (घर) से मिलकर बने हिमालय को पुराणों में देव स्थान के नाम से भी पुकारा गया है. हज़ारों वर्षों से यह ऋषि-मुनियों की भूमि रही है.

हिमालय को बचाने की अंतरराष्ट्रीय पहल

जलवायु परिवर्तन और प्रकृति के साथ बढ़ती छेड़छाड़ का जैव विविधता पर नकारात्मक असर पड़ा है. इंसान अपने फ़ायदे के लिए एक तरफ़ जहां जंगलों का सफाया कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उसने प्राकृतिक संपदा की लूटखसोट मचा रखी है, बग़ैर इस बात का ख्याल किए हुए कि इस पर अन्य जीवों का भी समान अधिकार है. बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप ने पर्वतीय क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र को भी गड़बड़ कर दिया है, जिससे यहां पाए जाने वाले कई जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं या होने के कगार पर हैं. पहाड़ों पर हो रही पेड़ों की अवैध कटान एवं खनन कार्यों ने इस क्षेत्र को अंदर से खोखला कर दिया है. जलवायु परिवर्तन के कारण हर साल बढ़ती गर्मी से ग्लेशियरों का पिघलना लगातार जारी है. ऐसे में पहाड़ों पर रहने वालों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है. हिमालय जहां हमारे लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, वहीं इसे जड़ी-बूटियों की उपलब्धता के लिए भी जाना जाता है.

संस्कृत के शब्द हिम (बर्फ़) और आलय (घर) से मिलकर बने हिमालय को पुराणों में देव स्थान के नाम से भी पुकारा गया है. हज़ारों वर्षों से यह ऋषि-मुनियों की भूमि रही है. धर्मग्रंथों में कई जगह हिमालय की विशेषता का उल्लेख मिलता है. 12 हज़ार वर्ग किलोमीटर इलाक़े में फैले हिमालय में 15 हज़ार से ज़्यादा ग्लेशियर मौजूद हैं. भारत और नेपाल के लोगों की प्यास बुझाने और कृषि कार्यों के लिए पानी की अधिकांश आपूर्ति इसी से निकलने वाली नदियां करती रही हैं. वहीं पन बिजली उत्पादन के लिए भी यह हमारा प्रमुख स्रोत रहा है, लेकिन विकास के नाम पर इंसानों द्वारा नासमझी में किए जा रहे कार्यों और इसके परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन ने इसे बुरी तरह प्रभावित किया है.

वैश्वीकरण के बढ़ते असर से पर्वतीय क्षेत्रों की आबादी के समक्ष खाद्य सुरक्षा का ख़तरा पैदा हो गया है. वहीं पर्यटन और आधुनिक तकनीक ने इन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रभावित किया है. वास्तव में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के अपार भंडार हैं. जम्मू-कश्मीर से उत्तराखंड होते हुए उत्तर पूर्व तक फैला हिमालय अपने अंदर विविधताएं समेटे हुए है, जिन्हें विकास के नाम पर नष्ट किया जा रहा है. हालांकि इस संबंध में अब कई अहम क़दम उठाए जा रहे हैं. भू-वैज्ञानिकों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के प्रति व्यक्त की जा रही चिंताएं सार्थक साबित हो रही हैं और इस दिशा में प्रयास शुरू हो चुके हैं. पिछले दिनों पर्यटन नगरी नैनीताल में भूगोल वेत्ताओं के अंतरराष्ट्रीय संगठन आईजीयू की संगोष्ठी को इसी संदर्भ में एक कड़ी के रूप में देखा जा सकता है. कुमांऊ विश्वविद्यालय में आयोजित इस संगोष्ठी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात भू-वैज्ञानिक प्रो. मार्टिन प्राइस समेत देश एवं विदेश के तक़रीबन दो सौ से अधिक भूगोलविदों ने हिस्सा लिया और ख़तरे में पड़े पारिस्थितिक तंत्र, जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ विकास जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की. प्रो. मार्टिन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पर्वतीय क्षेत्रों के पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए वैज्ञानिक आधार पर योजनाएं बनाने की आवश्यकता है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि विकास के नाम पर हो रहे प्राकृतिक दोहन को अगर वक़्त रहते नहीं रोका गया तो इसका ख़ामियाज़ा आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ सकता है.

आईजीयू कमीशन के महासचिव प्रो. वाल्टर लिमग्रूवर ने कहा, पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, जिनके उपयोग के लिए उचित तकनीक की आवश्यकता है, ताकि बिना नुक़सान पहुंचाए उनका भरपूर उपयोग किया जा सके और इसके लिए सरकार को जल्द से जल्द पहल करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि विशेष नियोजन के माध्यम से ही पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोका जा सकता है. भूगर्भ विज्ञानी प्रो. खडग सिंह वल्दिया के अनुसार, पर्वतीय क्षेत्रों में ज़मीन के अंदर सबसे ज़्यादा हलचल रहती है, जिससे भूकंप की आशंका बनी रहती है. शिवालिक की पहाड़ियों से लेकर हिमालय

वैश्वीकरण के बढ़ते असर से पर्वतीय क्षेत्रों की आबादी के समक्ष खाद्य सुरक्षा का ख़तरा पैदा हो गया है. वहीं पर्यटन और आधुनिक तकनीक ने इन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रभावित किया है. वास्तव में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के अपार भंडार हैं.

तक के क्षेत्र की ज़मीन के नीचे कई फाल्ट मौजूद हैं. भारतीय प्लेट तिब्बत से शुरू होने वाली एशियन प्लेट में हर साल पांच सेंटीमीटर समाहित हो रही है, जिसके कारण हिमालय साल में औसतन 18 से 20 मिमी ऊंचा हो रहा है. इस हलचल का असर उत्तराखंड के भूभाग पर भी पड़ता है और यह अपनी सतह से 3 से 5 मिमी ऊपर उठ रहा है. ऐसे में विकास का मॉडल बनाते वक़्त इन बातों को नज़रअंदाज़ करना महंगा साबित हो सकता है.

जैविक विकास में पहाड़ों का अहम योगदान रहा है. विश्व का 24 प्रतिशत हिस्सा पहाड़ों से घिरा है, जिस पर कुल आबादी का 12 प्रतिशत हिस्सा सामाजिक और आर्थिक रूप से निर्भर है. यह निर्भरता केवल जनजातीय समुदायों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विकास की अंधी दौड़ में शामिल आम इंसान भी उतने ही निर्भर हैं. यह समझना ज़रूरी है कि जैव विविधता अमूल्य है, उसे बचाने के ठोस प्रयास करने होंगे. यह कार्य किसी एक व्यक्ति, संगठन अथवा सरकार द्वारा नहीं, बल्कि सामूहिक इच्छाशक्ति और प्रयासों से संभव है. समय की मांग है कि हम विकास की रूपरेखा को तैयार करते वक़्त टिकाऊ विकास के मॉडल को अपनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित भविष्य का निर्माण हो सके. इसके लिए विकसित देशों को पहल करने की आवश्यकता है. (चरखा)

दिनेश पंत
feedback@chauthiduniya.com

बांस बना रोज़गार का साधन

पिछले दिनों केंद्र सरकार ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखकर यह साफ़ कर दिया कि बांस पेड़ नहीं, बल्कि घास की श्रेणी में आते हैं. अत: इन्हें काटने के लिए वन विभाग से विशेष अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी. सरकार की इस पहल से उन लोगों को राहत पहुंची है, जो बांस उत्पाद के माध्यम से रोज़गार हासिल कर रहे हैं. बांस से बने सामान वास्तव में इको फ्रेंडली होते हैं. इसे प्लास्टिक के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है. यही वजह है कि देश और विदेशों में बांस से बने सामानों की मांग में तेज़ी से वृद्धि हो रही है. बढ़ती मांग ने ही झारखंड के आदिवासियों को रोज़गार उपलब्ध कराया है, जिससे न सिर्फ़ वे आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बल्कि रोज़ी-रोटी की तलाश में होने वाले पलायन में भी कमी आई है. रोज़गार के अभाव में राज्य से आदिवासियों की एक बड़ी संख्या परिवार सहित पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब और दिल्ली जाकर घरों एवं खेतों में काम करने के लिए मजबूर है, लेकिन अब धीरे-धीरे हालात बदलने लगे हैं. बांस से बनने वाले सामानों ने उन्हें घर में ही रोज़गार का साधन उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है. इस काम में आदिवासी महिलाएं बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और परिवार की आमदनी में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही हैं.

दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के लवाडीह गांव की बसंती टुडू आज प्रतिमाह दस हज़ार रुपये कमा रही है. उसका पति सुभाष हंसदा ज़िले का सिद्धहस्त बांस कारीगर माना जाता है. उसे हाल में राज्य के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार के रूप में सम्मानित भी किया. इस रोज़गार से जुड़ने से पहले दोनों खदान में पत्थर तोड़ने का काम करते थे, लेकिन उससे होने वाली आमदनी से घर के आवश्यक ख़र्च भी पूरे नहीं हो पाते थे. अत्यधिक श्रम के कारण इन्हें टीबी की बीमारी हो गई और आय का साधन छिन गया. इसी दौरान आदिवासियों के बीच काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था ईवैंजेलिकल सोशल एक्शन फोरम (ईसाफ) ने इन्हें बांस के माध्यम से रोज़गार हासिल करने की जानकारी दी और प्रशिक्षण के लिए केरल के त्रिचूर भेजा. तीन माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन्होंने बांस के माध्यम से कई तरह की वस्तुएं बनाना सीखा. वहां से लौटकर आने के बाद इन दोनों ने अपने गांव में समूह बनाकर यह काम शुरू किया और घासीपुर, रामपुर, लखीकुंडी, पिपरा, बरगाछी एवं केंदुआ जैसे पिछड़े क्षेत्रों के आदिवासी परिवारों को भी प्रशिक्षित किया. ये राज्य के वे इलाक़े हैं, जहां के लोगों की आय का एकमात्र साधन खेती है, लेकिन बेरोज़गारी के दिनों में परिवार के लिए दो जून की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में काम की तलाश में दूसरे राज्यों की तरफ़ पलायन करना इनकी मजबूरी है. आज शिकारीपाड़ा प्रखंड में 20 समूह काम कर रहे हैं, जिनसे क़रीब दो सौ महिलाएं और पुरुष जुड़े हुए हैं. इनके द्वारा बांस की सहायता से बनाए गए डस्टबीन, सजावटी सामान और फर्नीचर की मांग आज महानगरों के अलावा विदेशों में भी ख़ूब हो रही है.

आदिवासियों में बढ़ती रुचि को देखते हुए ईसाफ ने राज्य के अन्य ज़िलों गिरिडीह, पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा और राज्य से सटे पश्चिम बंगाल के मोहम्मदा बाज़ार में भी अपने प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं, जहां लगभग दो हज़ार परिवारों को घर बैठे रोज़गार हासिल हो रहा है. संस्था यह कार्य सेल्फ हेल्प ग्रुप और नाबार्ड के सहयोग से अंजाम दे रही है. ईसाफ के बिजनेस मैनेजर सुधीर कुमार के अनुसार, इस वर्ष आठ केंद्रों से क़रीब 17 लाख रुपये के उत्पाद बिक चुके हैं. संस्थान महानगरों में लगने वाले मेलों में भी इन उत्पादों को प्रदर्शित करता है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं और कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने ऑर्डर भी दिए हैं. फैब इंडिया चेन्नई और नार्वे आदि तक यहां के उत्पाद निर्यात किए जाते हैं. बांस व्यवसाय से जुड़कर आदिवासी कई अनूठी चीज़ें बनाने लगे हैं. वे हुनरमंद हो चुके हैं, अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी संवार रहे हैं. वे अपने द्वारा बनाए गए सामानों को इस संस्था के हाथ बेच देते हैं. इस प्रकार उन्हें बिक्री संबंधी दिक़्क़तों का भी सामना नहीं करना पड़ता. कारीगर लाल टुडू के अनुसार वह एक बांस से कई प्रकार की चीज़ें बनाने में महारथ हासिल कर चुका है और यह काम वह एक सप्ताह में पूरा कर लेता है. डेनियल मोहली और उर्मिला मोहली काम की तलाश में दर-दर भटकने से कहीं ज़्यादा अच्छा इस काम को मानते हैं. एक परिवार से जितने सदस्य इस काम से जुड़ेंगे, आमदनी उतनी ही ज़्यादा होगी. महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशिक्षण केंद्र के बग़ल में ही बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं. एक तरफ़ आदिवासी जीविकोपार्जन करते हैं, वहीं बाल शिक्षा केंद्र में उनके बच्चे भविष्य के बेहतर सपने बुनते हैं.

वैज्ञानिक आधार पर बांस को ग्रामिनीई कुल का बीजपत्री पौधा माना जाता है. विश्व के लगभग सभी हिस्सों में इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं. अकेले भारत में ही बांस की 24 प्रजातियां मौजूद हैं. महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्य पेड़-पौधों को जहां सूखे, कीटों एवं बीमारियों का ख़तरा रहता है, वहीं बांस हर हाल में आसानी से फलता-फूलता है. यह ज़मीन पर सबसे तेज़ बढ़ने वाला पौधा है. झारखंड में 23,605 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जंगल है, जो कुल क्षेत्रफल का 30 प्रतिशत है. इनमें से 843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बांस पाया जाता है. बांस का काम मुख्यत: महली जनजाति द्वारा किया जाता है, जिसकी आबादी राज्य में अन्य जनजातियों के मुक़ाबले ज़्यादा है, लेकिन आर्थिक रूप से यह काफ़ी पिछड़ी मानी जाती है. ऐसे में बांस न सिर्फ़ इनके लिए रोज़गार का एक बेहतर विकल्प बन रहा है, बल्कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भी साबित हो सकता है. (चरखा)

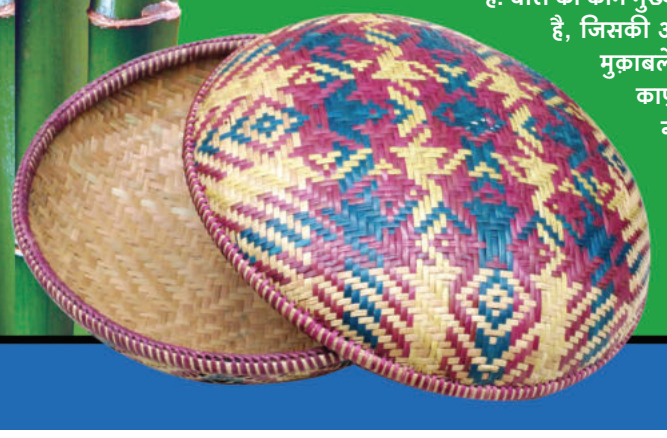

शैलेंद्र सिन्हा
feedback@chauthiduniya.com

महावीर प्रसाद आर मोरारका

समाज का अभिशाप, अमीरों का शौक़

एक संयुक्त परिवार को ले लीजिए. आप परिवार के बड़े हैं. कई बच्चे हैं. रुपये आपके पास मान लीजिए 500 हैं. सबसे पहला प्रश्न उठेगा कि पहले-पहल क्या चीज़ ख़रीदी जाए, उसके बाद क्या? इस तरह परिवार की ज़रूरत की चीज़ों की सूची बनेगी और आप वस्तुएं उपलब्ध कर लेंगे. मान लीजिए, खाने के लिए घर में अन्न नहीं है. स्वाभाविक तौर पर पहले-पहल आप अन्न ख़रीदने की व्यवस्था करेंगे, बाद में सबके लिए कपड़े की व्यवस्था करनी होगी. फिर मान लीजिए, जिस मकान में आप रहते हैं, उसका किराया देना है. अगर वह मकान आपके घर का है तो उसके टैक्स वग़ैरह, टूट-फूट, साफ़-सफ़ाई का ख़र्च देना होगा. फिर कुछ रुपये बचेंगे तो आप बच्चों के लिए खिलौने, स्त्री के लिए ज़ेवर या इत्र की शीशियां ख़रीदेंगे. मान लीजिए, ऐसे ही परिवार के एक मुखिया हैं, उनको पहले क्या चाहिए, इसका अर्थात उन्हें प्राथमिकता का समुचित ज्ञान नहीं है. पहले वे रुपयों से इत्र-सेंट या अन्य शृंगार के प्रसाधन ख़रीदते हैं, बढ़िया सोने के नेकलेस ख़रीदते हैं. आप यही कहेंगे कि वह अजीब मूर्ख आदमी है, घर में खाने को दाना भी नहीं है, इत्र या ज़ेवर ख़रीदने में व्यर्थ रक़म डुबोता है. आप जानते हैं कि इत्र या ज़ेवर ख़रीदने में रक़म बर्बाद नहीं होती, फिर भी उसको प्राथमिकता का समुचित ज्ञान नहीं होने से उसके कार्य को मूर्खतापूर्ण कहा जाएगा. बच्चों को भूख लगी है, दूध चाहिए या रोटी चाहिए. उसके बदले में वह बढ़िया सुंदर जिल्द वाली रामायण या गीता की पुस्तक ला दें तो क्या होगा? रामायण या गीता में रुपया ख़र्च करना ग़लत नहीं है, पर बच्चों के लिए दूध या रोटी का प्रबंध करना उसका प्रथम कर्तव्य था. रामायण या गीता की पुस्तक, बाद में कुछ बचता तो वह ख़रीद सकता था, अन्यथा नहीं. मान लीजिए, परिवार के कई सदस्यों को उसी संयुक्त कोष या धन में से ख़र्च करने का अधिकार है. उनमें से एक भाई सेंट, लवेंडर इत्र में ख़र्च करता है, कोई भाई को मुर्गे लड़ाने का शौक़ है. अतएव बढ़िया से बढ़िया क़िस्म के, नस्ल के मुर्गे ख़रीदता है. परिणाम यह होता है कि दूसरे दो भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए खाने या पहनने के लिए पर्याप्त साधन नहीं रहता. अब होगा संघर्ष. संयुक्त परिवार भंग होगा, लोग उन भाइयों को धिक्कारेंगे, जो इत्र या मुर्गों में रुपये ख़र्च करते थे.

मान लीजिए, सारा राष्ट्र ही एक बड़ा संयुक्त परिवार है और इसमें रहने वाले इस बड़े परिवार के बालिग़ या नाबालिग़ सदस्य हैं. अब आप देखते हैं कि देश में सैकड़ों, हज़ारों, लाखों की तादाद में ऐसे आदमी हैं जिन्हें दो जून पूरा खाने को भी उपलब्ध नहीं होता और वे फटे चिथड़े पहनते हैं. कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास इतना खाने को है कि उन्हें बदहज़मी हो जाती है. डॉक्टर-वैद्य रोज़ाना बुलाने पड़ते हैं. घुड़दौड़ में घोड़े दौड़ाते हैं, अच्छी से अच्छी नस्ल के घोड़े ख़रीदने में लाखों रुपये ख़र्च करते हैं. बढ़िया विलायती शराब पीते हैं. फिर भी काफ़ी फ़िज़ूल रुपया उनके पास बच जाता है तो साल में दो बार विदेश भ्रमण करने चले जाते हैं, वहां अपने ऐश-ओ-आराम के लिए लाखों रुपये ख़र्च कर आते हैं. कितनी विषम परिस्थिति है यह! देश के इतने आदमी खाने को तरसते हैं और कुछ आदमी इतना ज़्यादा फ़िज़ूल ख़र्च करते हैं कि जिसकी इंतहा नहीं. अब आप क्या करेंगे? परिवार का तो, संघर्ष हो जाने पर, विभाजन हो जाता है. पर जब सारे राष्ट्र में यह बीमारी हो तो क्या करें, किस तरह इसको रोका जाए, यही तो प्रश्न आपके, हमारे, सबके दिमाग़ में आएगा.

माना कि हीरे-मोती भी विश्व के लिए आवश्यक हैं, अच्छे घोड़ों की नस्ल क़ायम रहना भी बड़ा ज़रूरी है, रेशमी वस्त्र परिधानों को प्रोत्साहन भी समुचित है, डॉक्टर-वैद्य भी समाज में लगे रहने चाहिए. यह सब ठीक है, पर इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पेट भर सबको खाना मिले, तन ढांपने को कपड़ा मिले, रहने को स्थान-घरबार मिले. तो फिर शायद मौज-शौक़ भी कुछ अंशों में क्षम्य हो सकता है. इन लोगों का दावा है कि हम अपने शौक़ से कितने आदमियों को रोज़ी देते हैं. आपने इसका भी ख़्याल किया है? क्या? सैकड़ों-हज़ारों आदमी काम पर लगे हुए हैं, जो बढ़िया कपड़े हम पहनते हैं उनको बनाने में. जो घोड़ों का शौक़ हम करते हैं उनकी देखभाल करने में. जो हीरे-मोती हम संग्रह करते हैं, उनको प्राप्त करने में समुद्र के गोताख़ोरों से लेकर, खानों में काम करने वालों से लेकर, मशीनों पर पालिश वग़ैरह करने वाले जाने कितने ही हज़ारों आदमी काम पर लगे रहते हैं. हम उन्हें रोज़ी देते हैं. क्या अजीब दावा है. शायद यह ठीक भी हो. पर क्या इसी तरह का दावा ये ख़ूनी या डाकू नहीं कर सकते? हत्या या लूट के अपराधी, वे भी कह सकते हैं कि हम कितने ही आदमियों को रोज़ी देते हैं. पुलिस फ़ोर्स सारा का सारा, फिर डॉक्टर-सर्जन, श्मशान घाट पर लकड़ी देने वाला, लकड़ी काटकर लाने वाला लकड़हारा, कफ़न के लिए कपड़ा बनाने वाला इत्यादि सैकड़ों आदमी काम पर लगे हुए हैं, वे रोज़ी पाते हैं. वे ख़ूनी या लुटेरे हैं, पर वे कहते हैं कि अगर हम लुटेरे या ख़ूनी न हों तो इतने सब आदमी बेकार हो जाएंगे. क्या ख़ूब दलील है. उन दोनों विभिन्न मतों में मुझे विशेष फ़र्क़ नज़र नहीं आता.

इसलिए जिस रुपये से धनिक अपने शौक़ों को पूरा करने के लिए जो ग़लत तरीक़े से रोज़गार उत्पन्न करते हैं, वे ही रुपये अगर समान भाग से सबको बंटवारा करके मिल जाएं तो वे ही रोज़गार सही अर्थ में उत्पन्न होंगे. राष्ट्र के पास खाने के लिए ज़्यादा अन्न होगा, पहनने के लिए ज़्यादा कपड़ा होगा, रहने के लिए ज़्यादा घर होंगे, कला और विज्ञान को बाद में समुचित प्रोत्साहन मिलेगा ही.

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

feedback@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

ब्रिटेन, रूपर्ट मार्डोक और डेविड कैमरून

ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेराल्ड मैकमिलन से जब पूछा गया कि आपको अपने कार्यकाल में सर्वाधिक भय किस बात का होता था तो उन्होंने उत्तर दिया कि घटनाओं से उन्हें सबसे अधिक भय लगता था. प्रधानमंत्री के रूप में उनके नौवें उत्तराधिकारी डेविड कैमरून भी इस बात से सहमत होंगे. अभी ब्रिटेन को जिस घटना ने सबसे अधिक परेशान किया है, उसकी शुरुआत रूपर्ट मार्डोक प्रकरण से नहीं हुई, बल्कि उसकी शुरुआत हुई मिली डाउलर की हत्या के मुक़दमे की जांच और उसके बाद उसके परिवार वालों को हुई परेशानी से. उसके पिता के बारे में ऐसा कहा गया कि उन्होंने उस अश्लील वीडियो को देखा, जिसमें मिली को दिखाया गया था और वह काफ़ी दु:खी हुए. उसकी माता से काफ़ी पूछताछ की गई. अत: जबकि अभियुक्त को दोषी क़रार दे दिया गया, फिर भी यह प्रश्न अभी भी शेष है कि क्या मिली के परिवार वाले इससे संतुष्ट हैं. रूपर्ट मार्डोक ने अपने एक समाचारपत्र को बंद किया, जिसका संबंध फोन हैकिंग से रहा है, उसकी पृष्ठभूमि यही थी. न्यूज ऑफ द वर्ल्ड समाचारपत्र, जिसे बंद करने की घोषणा मार्डोक ने की, मुख्य रूप से अमीर और प्रसिद्ध लोगों के निजी संबंधों के बारे में लिखने के लिए जाना जाता है. उस पर शाही परिवार के फोन हैक करने का आरोप लगा. एंडी कौल्सन, जो शाही परिवार के फोन हैकिंग की घटना के समय न्यूज ऑफ दी वर्ल्ड समाचारपत्र के संपादक थे, ने इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने उन्हें अपना जनसंपर्क सलाहकार नियुक्त कर लिया. उस समय इस फ़ैसले पर कुछ लोगों ने नाराज़गी जताई, लेकिन कैमरून पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा.

मिली डाउलर की मृत्यु के बाद न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने उसका फोन हैक किया था. यह कोई सामान्य बात नहीं है. डेविड बेखम के निजी संबंधों को उजागर करना एक अलग बात है और किसी लड़की के मरने के बाद उसका फोन हैक करना बिल्कुल अलग बात है. इस रहस्योद्घाटन के बाद तो यही कहा जा सकता है कि इस समाचारपत्र ने बहुत ग़लत किया है. साथ ही यह भी ख़ुलासा हो गया कि इस समाचारपत्र को पुलिस ने ही फोन नंबर दिए थे और पुलिस को इसके लिए पैसा भी मिला था. क्या ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ गया है? यहां भ्रष्टाचार का मतलब टूजी अथवा कॉमनवेल्थ जैसे घोटालों से नहीं है, बल्कि नियम-क़ानूनों को तोड़ने से है. प्रधानमंत्री को वैसे लोगों को किसी पद नियुक्त नहीं करना चाहिए, जो किसी भी प्रकार के आपराधिक मामलों में संलिप्त रहे हों. जब कोई पत्रकार किसी पीड़ित, अपराधी अथवा अफ़गान युद्ध में मरने वाले सैनिकों के परिवारों से संबंधित समाचारों की खोज कर रहा हो तो पुलिस को उसकी मदद नहीं करनी चाहिए.

इन घटनाओं के बाद रूपर्ट मार्डोक ने न्यूज ऑफ द वर्ल्ड नामक समाचारपत्र बंद कर दिया. इस समाचारपत्र से उन्हें लाभ होता था, लेकिन समाचारपत्र बंद कर देना ही काफ़ी नहीं है. मार्डोक ने वैसे भी टीवी चैनल बीएसकेवाइबी के 39 फ़ीसदी शेयर ले लिए हैं और बाक़ी भी लेने का मन बना रहे हैं. इस चैनल ने जो निविदा निकाली थी, उसकी सावधानी से जांच करने की आवश्यकता है, लेकिन संदेह इस बात का है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ मार्डोक के संबंध उन्हें लाभ दिला सकते हैं. मार्डोक को पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और गॉर्डेन ब्राउन का भी समर्थन प्राप्त था और फिर कैमरून भी मार्डोक की मदद में पीछे रहने वाले नहीं हैं. वैसे टीवी चैनल की निविदा जांच के घेरे में है. जल्द ही कैमरून के साथ मार्डोक और उनके सहयोगियों विशेषकर न्यूज ऑफ द वर्ल्ड के पूर्व संपादक रेबेक ब्रुक्स के संबंध भी जांच के घेरे में आ जाएंगे. वामपंथी और प्रगतिशील लोग मार्डोक से घृणा करते रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मार्डोक ने टोनी ब्लेयर को दक्षिणपंथ की तरफ़ धकेल दिया और लेबर पार्टी को समाजवाद से भटका दिया. ब्रिटेन के ही एक अख़बार गार्जियन ने मिली डाउलर का मोबाइल हैक करने की घटना को उजागर किया और इसने दशकों तक मार्डोक के समाचारपत्र द्वारा अपने ऊपर किए जा रहे हमले का बदला ले लिया.

इसके अलावा कई और जांचें चल रही हैं. पुलिस के दो उच्चाधिकारियों ने इस्तीफ़ा दे दिया है. कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कइयों से पूछताछ की गई है. एक न्यायाधीश इस मामले की जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे. संसद में इस मुद्दे पर बहस हो चुकी है. प्रधानमंत्री के बयान के बाद कई प्रश्न पूछे गए. मार्डोक ने टीवी चैनल बीएसकेवाइबी के लिए अपनी निविदा वापस ले ली है और उसके दो बड़े निदेशकों ने इस्तीफ़ा दे दिया है. इन घटनाओं का ब्रिटेन में असर तो पड़ेगा ही और कुछ बड़े सुधार भी होंगे.

मिली डाउलर की मृत्यु के बाद न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने उसका फोन हैक किया था. यह कोई सामान्य बात नहीं है. डेविड बेखम के निजी संबंधों को उजागर करना एक अलग बात है और किसी लड़की के मरने के बाद उसका फोन हैक करना बिल्कुल अलग बात है. इस रहस्योद्घाटन के बाद तो यही कहा जा सकता है कि इस समाचारपत्र ने बहुत ग़लत किया है.

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

सर्वश्रेष्ठ पत्र

सरकार से सवाल

चौथी दुनिया के माध्यम से कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं. राजनीतिक पार्टियां चुनाव में पानी की तरह बहाने के लिए पैसा कहां से प्राप्त करती हैं? क्या चुनावी फंड प्राप्ति का स्रोत वैधानिक है? प्रत्याशियों द्वारा शपथपत्र में अपनी संपत्ति और अपराध के बारे में जो जानकारी दी जाती है, उसकी जांच करने के बाद अयोग्य लोगों को अपात्र घोषित क्यों नहीं किया जाता? सरकारें नशीले पदार्थों की बिक्री की अनदेखी करके जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही हैं? प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से बिगड़ रहे पर्यावरण संतुलन के कारण आने वाली आपदाओं से कैसे बचाव होगा? नक्सलियों के विरुद्ध सरकार सेना का उपयोग क्यों नहीं कर रही है? रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से जमीनें बंजर होती जा रही हैं, इसकी रोकथाम कैसे हो? विषाक्त खाद्यान्न और फल-सब्ज़ियों के सेवन से जनसामान्य को कैसे रोका जाए?

–रामावतार गुप्त, *रवेली-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश.*

बेमानी सरकारी योजनाएं

सरकार ने मुसलमानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू कर रखी हैं, लेकिन ये सिर्फ़ नाममात्र की हैं. अफ़सोस तो इस बात का है कि सरकार सिर्फ़ योजना की घोषणा या उन्हें शुरू करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है, लेकिन योजना को ठीक से कार्यान्वित कराने के बारे में कोई क़दम नहीं उठाती. कोई भी योजना उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकती, जब तक ज़रूरतमंद लोगों तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंचता. देश के ज़्यादातर मुसलमान अशिक्षित या कम पढ़े-लिखे हैं, उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है और जिन्हें जानकारी है, उन्हें भी उनका लाभ हासिल करने के लिए सरकारी दफ्तरों के इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि वे इनसे तौबा कर लेते हैं.

–सरफ़राज़ ख़ान, *दिल्ली.*

आरक्षण की राजनीति

भारत में राजनीति, समाज एवं आरक्षण का घालमेल सबसे ज़्यादा तनावकारी और विघटनकारी रहा है. समाज को कई हिस्सों में बांटकर राज करने की परंपरा अंग्रेजों ने डाली थी, किंतु उन्होंने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि आज़ाद भारत का नेतृत्व उनके तौर-तरीक़ों को अपने ही नागरिकों पर इस्तेमाल करेगा. दुर्भाग्य से सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले के नाम पर दलितों-पिछड़ों का राजनीतिक प्रयोग तो चलता ही रहा है, किंतु भारतीय संविधान का मखौल उड़ाते हुए धर्म आधारित आरक्षण की बात भी की जाने लगी है. योग्यता की अनदेखी कर अयोग्य को प्रोत्साहन देने की नीति के तहत तमाम विवादास्पद निर्णय लिए गए, जिनसे देश की सामाजिक समरसता में भारी कमी आई. कमज़ोर और दलित व दमित, वंचित वर्गों के उत्थान की नीति के तहत एकबारगी इसे स्वीकार भी कर लिया जाए, किंतु धर्म के आधार पर भेदभाव और आरक्षण नीति की क्या स्वीकार्यता हो सकती है?

–मो. रफ़ीक़ चौहान, *ईमेल से.*

पानी का कारोबार

बड़ी-बड़ी कंपनियां बोतलबंद पानी के नाम पर जनता को ख़ूब लूट रही हैं. रेलवे प्लेटफॉर्म हो, बस स्टैंड हों या फिर कोई अन्य सार्वजनिक स्थान, सभी जगहों पर बोतलबंद पानी बिक रहा है. लोग बोतलबंद पानी ख़रीदते हैं और फिर पानी पीकर ख़ाली बोतलें यहां-वहां फेंक देते हैं, जिनमें पानी भरकर फिर से बेच दिया जाता है. इस तरह लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है.

–आबिद मजीद इराकी *जहानाबाद, बिहार.*

तेल के दाम

सरकार अगर यह दलील देती है कि कच्चे तेल की क़ीमत बढ़ने से दाम बढ़ाए गए हैं तो अब जब इसकी क़ीमत में गिरावट आई है तो उसे देश में पेट्रोल की क़ीमत कम करनी चाहिए थी. असल में सरकार सिर्फ़ जनता को मूर्ख ही नहीं समझती, बल्कि उसकी मूर्खता का जमकर फ़ायदा भी उठाती है, क्योंकि जनता मूर्ख है, तभी तो वह ऐसे नेताओं को सत्ता सौंपती है.

–मुरारी लाल पारीक, *ईमेल से.*

बुंदेलखंड की दयनीय स्थिति

लंबे अरसे से चौथी दुनिया का पाठक हूं. पिछले कई अंकों में बुंदेलखंड के हालात के बारे में पढ़ा. पैकेज मिलने के बाद भी वहां की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है. अगर वहां के अधिकारियों की संपत्ति की जांच कराई जाए तो सारा सच सामने आ जाएगा. ललितपुर का दर्द भी बहुत गहरा है.

–अनिल चंद, *हरदोई, उत्तर प्रदेश.*

ऐतिहासिक फ़ैसला

भूमि अधिग्रहण विकास के लिए होता है तो क्या बिल्डरों द्वारा फ्लैटों, मल्टीप्लेक्स, स्वीमिंग पुल, हाईटेक सेंटर एवं एमपी थिएटर का निर्माण आम लोगों के लिए किया जाता है? हक़ीक़त में तो यह विकास आम लोगों की पहुंच से दूर ही है. विकास का अर्थ समग्रता से होना चाहिए न कि वर्ग विशेष से. सिंगुर, नंदीग्राम एवं जगतसिंहपुर आदि प्रकरणों से भी सरकार ने सबक़ नहीं लिया. सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्रकरण पर आम आदमी का हित साधते हुए जो फ़ैसला दिया है, वह ऐतिहासिक है और भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा.

–हर्षवर्द्धन कुमार, *पटना, बिहार.*

राजकमल प्रकाशन समूह

चौथी दुनिया में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की ओर से 700 रुपए की किताबें दी जाएंगी.

राजकमल प्रकाशन की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें. हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

संभलिए, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है

बहुत सारी चीजें अमेरिका में बनती हैं, अमेरिका में खुलती हैं, तब हमें पता चलता है कि हम किस तरह के जाल में कभी फंस चुके थे, इन दिनों फंस रहे हैं या आगे फंसने वाले हैं. हमारे देश की धुरंधर हस्तियां, जो लोगों की राय बनाती हैं, जिनमें जस्टिस राजेंद्र सच्चर, दिलीप पडगांवकर, उम्र के आखिरी पड़ाव पर खड़े प्रसिद्ध संपादक, लेखक एवं सोशल एक्टिविस्ट कुलदीप नैय्यर साहब और गौतम नवलखा शामिल हैं, जिन्होंने रूरल जर्नलिज्म और वैचारिक पत्रकारिता में नाम कमाया तथा इनके साथ बहुत सारे लोग एक साजिश में फंसे नजर आ रहे हैं, जिसका खुलासा अमेरिका में हुआ. आईएसआई भारत में ऐसे लोगों की तलाश में रहती है, जो सेक्युलर हों, निर्भीक हों, साथ ही जिनकी बात पर देश का एक बड़ा वर्ग विश्वास भी करता हो. अक्सर वह इस तलाश में सफल हो जाती है और उन्हें इस तरह संगठित करती है कि जो शिकार हो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे अनजाने में देश के खिलाफ खड़े हो गए हैं. कश्मीर एक ऐसा विषय है, जिस पर हिंदुस्तान में दो राय हैं. एक राय यह है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अविभाज्य अंग है और उसे हर कीमत पर हिंदुस्तान से जोड़कर रखना चाहिए. इसके लिए हमें सेना की जितनी भी मदद लेनी पड़े, लेनी चाहिए. दूसरी राय उन लोगों की है, जिनका कहना है कि कश्मीर हमारा है, लेकिन कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए, वहां से सेना की संख्या कम होनी चाहिए, विकास के काम होने चाहिए और ज्यादतियां नहीं होनी चाहिए. कश्मीर के लोगों को भी देश के दूसरे राज्यों की तरह विकसित होने का मौका मिलना चाहिए. पहली धारा के लोग फंडामेंटलिस्ट है और वे आईएसआई के काम के नहीं हैं. उसके काम के लोग दूसरी तरह के हैं. उसने सारी दुनिया में सेमिनार करने की योजना बनाई और उन लोगों को तलाशा, जो ऐसे सेमिनार कर सकें. ऐसे लोगों को छांट-छांटकर आमंत्रित किया, जो दूसरी धारा के हैं और कश्मीर को लेकर पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं. ये लोग सारी दुनिया में गए, लेकिन इन्हें यह समझ में नहीं आया कि जहां वे जा रहे हैं, वहां के लिए इन्हें एक्जीक्यूटिव क्लास की टिकटें कौन दे रहा है, फाइव स्टार होटल में कौन ठहरा रहा है? जो संगठन सेमिनार कर रहा है, क्या उसका घोषित उद्देश्य वही है जो उनके सामने आया है? उस संगठन के तार कहीं किसी दूसरे संगठन से तो नहीं जुड़े हैं? अफसोस इस बात का है कि ये सवाल गौर करने लायक हैं, लेकिन वे लोग जो सही हैं, ईमानदार हैं, वे इन चीजों पर ध्यान नहीं देते. परिणाम यह निकला कि आईएसआई ने एक कोशिश की कि सारी दुनिया में कश्मीर को लेकर भारत पर उंगली उठाई जाए और इसमें उसने उन भारतीयों को शामिल कर लिया, जो सचमुच सही पत्रकार या सही सोच वाले लोग हैं.

ये सही सोच वाले लोग इस साजिश को नहीं पहचान पाए, लेकिन साजिश को न पहचान पाना और उसका हिस्सेदार बन जाना मासूमियत का नहीं, बेवकूफी का उदाहरण है. अफसोस इस बात का है कि ऐसी जगहों पर, जहां हम देश के बाहर होते हैं, वहां कोई ऐसी बात हो जिसमें भारत का नाम आए, उसके बुनियादी सवालों पर बातचीत हो, वहां हम बेवकूफी यह करते हैं कि देश के खिलाफ बोलने लगते हैं. शायद हमारे इन दोस्तों ने कई जगह पर ऐसा किया. मुझे लाहौर का एक किस्सा याद है. लाहौर में बाबा साहब अंबेडकर को लेकर एक सेमिनार हुआ, जिसमें हिंदुस्तान से कई लोग गए, जिनमें दक्षिण के एक दलित नेता भी थे, जो एक अखबार चलाते हैं और फायर ब्रांड माने जाते हैं. उस दलित नेता ने वहां हिंदुस्तान के हितों, आजादी के आंदोलन और देश के वजूद के खिलाफ बातें कहीं. उस शख्स को शर्म नहीं आई कि वह हिंदुस्तान के सहयोग से ही पाकिस्तान में था. जब हम देश के बाहर होते हैं तो हमें बोलते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए. यह न हो कि हम कुछ ऐसा बोल जाएं कि दूसरे देश में हमारा मजाक बन जाए. जब हम देश के खिलाफ बोलते हैं तो मजाक के पात्र होते हैं और किसी के हाथ में खेलने लगते हैं. हमारे इन दोस्तों ने कश्मीर या दुनिया में जो सेमिनार होते हैं, उनमें जाकर यही किया. इन्होंने हिंदुस्तान के हितों के खिलाफ दूसरे देश के हितों का समर्थन किया. आईएसआई यही चाहती थी कि कश्मीर को लेकर भारत के ही लोग तल्ख अंदाज में बोलें. कभी भी हमारे दोस्तों की समझ में यह नहीं आया कि जितनी गड़बड़ियां उस कश्मीर में हैं जो हिंदुस्तान के साथ है, शायद उससे ज्यादा गड़बड़ियां उस कश्मीर में हैं जो पाकिस्तान के साथ है. इन दोस्तों ने कभी पाकिस्तान के साथ वाले कश्मीर और मुजफ्फराबाद में जाकर देखने की कोई कोशिश नहीं की, कभी यह मांग नहीं की कि हम जब इस्लामाबाद या कराची आते हैं तो हमें मुजफ्फराबाद भी जाने की इजाजत दी जाए. अगर इजाजत नहीं मिलेगी तो हम कराची या इस्लामाबाद नहीं जाएंगे.

लेकिन कुलदीप नैय्यर साहब हों या बाकी साथी, इन्हें पाकिस्तान जाने की इतनी जल्दी रहती है कि जैसे अगर ये नहीं गए तो इनके सेकुलरिज्म पर कोई चोट पहुंचेगी या लोग इन्हें सेकुलर मानने से मना कर देंगे. सेकुलरिज्म का मतलब कम्युनलिज्म का साथ देना नहीं है, देश के हितों के खिलाफ बोलना भी नहीं है. अपने देश में सेकुलरिज्म के लिए लड़ना एक बात है और इसे लेकर सारी दुनिया में अपने देश को बदनाम करना बिल्कुल दूसरी चीज है. हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, यहां की सरकार सेकुलर आदर्शों पर चलती है, यहां मुसलमान सुरक्षित हैं. उतने सुरक्षित हैं, जितना दूसरे देशों में नहीं हैं. यहां के मुसलमान देश के साथ हैं, वे दूसरे देशों के मुसलमानों की तरह नहीं हैं, जो रहते कहीं हैं और उनके हित कहीं और जुड़े होते हैं. ये पॉजिटिव चीजें हिंदुस्तान के इथोज़ में हैं, संस्कृति में हैं और यहां के हिंदुओं एवं मुसलमानों की मिली-जुली गंगा-जमुनी संस्कृति में रची-बसी हैं. इन चीजों के बारे में सारी दुनिया में न बोलना और इन इथोज़ के खिलाफ माहौल बनाना शायद हिंदुस्तान के हितों के खिलाफ बोलना माना जा सकता है.

सरकार क्या कर रही है? उसके पास एक नेटवर्क है, अलग-अलग तरह की खुफिया एजेंसियां हैं और खुफिया एजेंसियों से इतर भी जानकारी के स्रोत हैं. वह इजरायल और सीआईए के साथ खुफिया जानकारी शेयर कर रही है. ऐसे में उसे आज तक यह क्यों नहीं पता चला कि दुनिया के वे कौन-कौन से संगठन हैं, जो हमारे देश के हितों के खिलाफ, यहां के लोगों को बरगला कर शामिल करते हैं और अपना हित साधते हैं. चाहे कश्मीर को लेकर, लोकतंत्र को लेकर या जिस तरीके के भी सारी दुनिया में सेमिनार होते हैं, उन्हें अगर हिंदुस्तान से बाहर का कोई संगठन आयोजित करता है तो उसके बारे में सरकार को क्यों पता नहीं होता? अभी जो अमेरिका में नेटवर्क पकड़ा गया, उसमें शामिल फाई, जो बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान में ही पढ़े-लिखे और अब अमेरिका में हैं, ने यह नेटवर्क कैसे बनाया, इस बारे में हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों के पास जानकारी क्यों नहीं आई? यह गंभीर विषय है.

सरकार क्या कर रही है? उसके पास एक नेटवर्क है, अलग-अलग तरह की खुफिया एजेंसियां हैं और खुफिया एजेंसियों से इतर भी जानकारी के स्रोत हैं. वह इजरायल और सीआईए के साथ खुफिया जानकारी शेयर कर रही है. ऐसे में उसे आज तक यह क्यों नहीं पता चला कि दुनिया के वे कौन-कौन से संगठन हैं, जो हमारे देश के हितों के खिलाफ, यहां के लोगों को बरगला कर शामिल करते हैं और अपना हित साधते हैं. चाहे कश्मीर को लेकर, लोकतंत्र को लेकर या जिस तरीके के भी सारी दुनिया में सेमिनार होते हैं, उन्हें अगर हिंदुस्तान से बाहर का कोई संगठन आयोजित करता है तो उसके बारे में सरकार को क्यों पता नहीं होता? अभी जो अमेरिका में नेटवर्क पकड़ा गया, उसमें शामिल फाई, जो बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान में ही पढ़े-लिखे और अब अमेरिका में हैं, ने यह नेटवर्क कैसे बनाया, इस बारे में हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों के पास जानकारी क्यों नहीं आई? यह गंभीर विषय है. अगर सरकार के पास उन संगठनों की जानकारी या विवरण नहीं होगा, कुंडली नहीं होगी, जो देश के हितों के खिलाफ या उन विषयों पर सेमिनार आयोजित करते हैं, जिन पर देश के बुद्धिजीवी उत्तेजित होते हैं, तो वह किस तरह लोगों को चेतावनी दे पाएगी कि आपकी राय सही है. आप अपनी राय देश में लिखिए, यहां अखबार हैं, टेलीविजन है, पब्लिक मीटिंग है. लेकिन आप बाहर जिस मंच पर जा रहे हैं, वह आईएसआई सपोर्टेड है या किसी और मुल्क द्वारा सपोर्टेड है. उसका फाइनेंस वहां से आता है. सरकार उन लोगों को, जो इनमें शामिल हैं, शामिल होना चाहते हैं या शामिल हुए हैं, एक बार चेतावनी तो देती, लेकिन उसने किसी को चेतावनी नहीं दी.

गृहमंत्री ने दिलीप पडगांवकर के बचाव में खुलकर कहा कि वह जिस सेमिनार में गए, कश्मीर में वार्ताकार बनने से पहले गए. इसका मतलब यह है कि आपके पास उस संगठन के बारे में न तब कोई जानकारी थी और न शायद अब कोई जानकारी है. जरूरत इस बात की है कि सरकार देश को लेकर गंभीर हो, सरकारी एजेंसियां गंभीर हों. जो देशभक्त हैं, देश की समस्याओं को लेकर चिंतित हैं, चेतावनी देते हैं, हल बताते हैं, ऐसे लोगों पर नज़र रखने और उनके टेलीफोन टेप करने से ज़्यादा जरूरी है उन लोगों पर नजर रखना, जो उन संगठनों के जाल में फंस सकते हैं, जो देश के हितों के खिलाफ सारी दुनिया में काम कर रहे हैं. हमारे उन सभी लोगों को, जो देश के बाहर किसी भी ऐसे सेमिनार या सभा में जाते हैं, जिसका रिश्ता देश की किसी समस्या से है, जाने से पहले अवश्य पता कर लेना चाहिए कि वह संगठन आखिर है क्या? जब वे वहां जाएं तो बहुत नपा-तुला बोलें. ऐसा न करें कि अपनी ही एक आंख फोड़ लें, इस उत्तेजना या भ्रम में कि वे मानवता के लिए हाथ उठा रहे हैं, जबकि उनका हाथ उनके देश के हितों के खिलाफ उठ रहा है. सांप्रदायिक विचारधारा वाले संगठन उन संगठनों को बढ़ावा देते हैं, जो बुनियादी सवालों पर बाहर सेमिनार या सभाएं करते हैं. उन्हें जब फाइनेंस मिलता है, तब वे यह नहीं देखते कि फाइनेंस आ कहां से रहा है. वे सेमिनार के लिए फाइनेंसर तलाशते हैं और जो भी फाइनेंस कर दे, उसके लिए काम करते हैं. सरकार को इनकी जानकारी रखनी चाहिए और उन लोगों को वक्त रहते चेताना चाहिए, जो इस देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ संपादक हैं, ओपीनियन मेकर हैं और देशद्रोही नहीं हैं. उन्हें समझाना-बताना चाहिए कि आप जहां जा रहे हैं, उस संगठन की असलियत यह है. अगर ऐसा हुआ होता तो हमारे देश के वे लोग, जो सचमुच पत्रकारिता में, समझ में नाम कमा चुके हैं, ऐसे जाल में नहीं फंसते और आज उन्हें शर्म से अपना मुंह छुपाने और टेलीविजन पर आकर माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम क्षमा चाहते हैं, हम नहीं जानते थे कि जिसके आमंत्रण पर सेमिनार में गए, वह आईएसआई फंडेड है. अमेरिका से यह खबर बाहर आई. अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पहले यह जानकारी हिंदुस्तान को क्यों नहीं दी, यह सरकार जाने, लेकिन अगर सरकार थोड़ी सी गंभीर हो जाए तो हम बहुत सारी शर्मनाक स्थितियों से बच सकते हैं.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

पाकिस्तान में स्थानीय निकायों की बदहाली

विकेंद्रीकरण संघीय व्यवस्था को एक मजबूत आधार प्रदान करता है, लेकिन पाकिस्तान में तो विकेंद्रीरण कहीं दिखता ही नहीं है. सवाल यह है कि क्या राज्य सभी शक्तियां अपने पास रखने का अधिकारी है और वह स्थानीय निकायों को कोई भी अधिकार देना अस्वीकार कर सकता है? 18वें संविधान संशोधन के अनुसार, अनुच्छेद 270-एए का क्लॉज-1 लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 को निरस्त करता है. यह ऑर्डिनेंस 2002 के लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अंतर्गत लाया गया था, जबकि समवर्ती सूची को भूलकर अनुच्छेद 270-एए का क्लॉज-6 राज्य की स्वायत्तता को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है. इस संशोधन द्वारा एक नया अनुच्छेद 140-ए लाया गया है. अनुच्छेद 140-ए के क्लॉज-1 में वही व्यवस्था है, जो जनरल मुशर्रफ के समय 2001 में लागू किए गए लोकल गवर्नमेंट आर्डिनेंस में थी. एक तरह से यह उसकी जेरॉक्स कॉपी है.

अनुच्छेद 140-ए के क्लॉज-1 के अनुसार, प्रत्येक राज्य स्थानीय सरकार प्रणाली कायम करेगा और कोई भी राज्य प्राचीन व्यवस्था को पुन: लागू नहीं करेगा. इसके साथ-साथ राज्य के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक अधिकार निर्वाचित स्थानीय सरकार को हस्तांतरित करे. अनुच्छेद 140-ए के क्लॉज-1 के प्रभाव में आने के बाद स्थानीय सरकार बनाने का अधिकार केंद्र के स्थान पर राज्य को दे दिया गया. हालांकि अनुच्छेद 140-ए का क्लॉज-2 पाकिस्तान के चुनाव आयोग को सशक्त करता है, ताकि राज्य के अंतर्गत होने वाले स्थानीय निकाय के चुनावों पर केंद्र का दबदबा रहे, क्योंकि चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है. अत: परोक्ष रूप से स्थानीय निकायों के चुनावों पर केंद्र का ही नियंत्रण होगा. अनुच्छेद 140-ए के क्लॉज-1 में एक शब्द छूटा हुआ है और वह है लेजिस्लेट. अगर स्टेब्लिस्ट से पहले इस शब्द को जोड़ दिया जाता तो विवाद ही समाप्त हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. जिस स्थानीय सरकार की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की गई है, उसका ढांचा मुशर्रफ के समय एनआरबी (नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो) ने तैयार किया था. बाद में राज्य सरकार ने इसे कानूनी आधार प्रदान करने के लिए एनआरबी की अनुशंसा का ही सहारा लिया और इसी के कारण स्टेब्लिस्ट शब्द रखने को सही ठहराया गया और लेजिस्लेट शब्द को नहीं रखा गया.

सितंबर 2009 में होने वाला स्थानीय निकाय चुनाव नहीं हो सका. अप्रैल 2010 में संसद ने 18वां संशोधन पारित किया और जुलाई 2010 में एनआरबी को समाप्त कर दिया गया. अत: राज्य में कैसी स्थानीय सरकार बनाई जाए, इसकी कोई भी रूपरेखा अब उपलब्ध नहीं है. दूसरी तरफ राज्य में पुन: स्थानीय सरकार की बहाली के लिए केंद्र सरकार न कोई कानून बना रही है और न कोई अध्यादेश जारी कर रही है. इसके साथ-साथ राज्य सरकारें भी स्थानीय निकायों के लिए कोई कानून नहीं बना रही हैं, जिसके कारण स्थानीय निकाय चुनाव नहीं हो पा रहे हैं और स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पा रही है. स्थानीय सरकार की जो प्रणाली मुशर्रफ के समय लाई गई थी और 2001 से 2009 तक चलती रही, उसमें कई समस्याएं हो सकती हैं. पहली समस्या तो यही है कि इस व्यवस्था के तहत स्थानीय निकायों के चुनाव पार्टी स्तर पर नहीं होने हैं, जबकि राज्य और केंद्र के चुनाव पार्टी स्तर पर होते हैं. ऐसे में स्थानीय सरकार के लिए जिन लोगों को चुना जाएगा, उनकी पकड़ जनता पर अधिक होगी और सभी पार्टियों को जनता तक अपनी पहुंच बनाने के लिए इन जीते हुए लोगों का सहारा लेना पड़ेगा. एक तरह से केंद्र और राज्य में राजनीति करने वाले नेताओं को ऐसे लोगों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो उन्हें स्वीकार नहीं. यही कारण है कि सरकार स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है. दूसरी समस्या यह है कि जिला प्रबंधक ही स्थानीय स्तर पर सामाजिक समस्याओं के निदान के लिए कार्य करेगा. अत: जनता के बीच उसकी पैठ अधिक होगी. इसके कारण राष्ट्रीय नेताओं की स्थिति कमजोर हो जाएगी. साथ ही साथ जिला स्तर पर शक्ति का एक अन्य केंद्र बन जाएगा, जिसके कारण जिला और राज्य सरकार के बीच शक्ति का संतुलन बिगड़ जाएगा. तीसरी समस्या यह है कि स्थानीय सरकार को टैक्स लगाने और राजस्व वसूलने का अधिकार होगा, जिसके चलते धन के मामले में वह आत्मनिर्भर हो जाएगा. इन संसाधनों का उपयोग स्थानीय सरकार अपने क्षेत्र के विकास के लिए करेगी, जिससे जनता पर उसका प्रभाव बढ़ेगा और बड़े नेताओं के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि जनता पर उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी. स्थानीय सरकार से राजनीतिक दल एवं नेता और अधिक लाभ उठा सकते हैं. राज्य स्तर पर शक्ति का केंद्रीयकरण असंतोष को बढ़ावा दे रहा है और साथ ही चारों राज्यों के विभाजन की मांग को भी जन्म दे रहा है. स्थानीय सरकार इसे कम कर सकती है. इसके साथ-साथ स्थानीय सरकार की उपस्थिति राज्यों के बीच के आपसी विवादों को भी कम करेगी.

सबसे बड़ी समस्या तो उन लोगों की है, जो न लोकतंत्र की कीमत समझते हैं और न स्थानीय सरकार की बहाली के लिए आवाज उठाते हैं. बहुत कम लोगों ने स्थानीय सरकार न होने के विरुद्ध आंदोलन किया है. आज आवश्यकता इस बात की है कि पाकिस्तान में किसी भी प्रकार की स्थानीय शासन प्रणाली लाई जाए, ताकि जनता जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की तलाश कर सके. एक बार ये लोग स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को जान लें, फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकतंत्र की कीमत समझ जाएंगे.

सबसे बड़ी समस्या तो उन लोगों की है, जो न लोकतंत्र की कीमत समझते हैं और न स्थानीय सरकार की बहाली के लिए आवाज उठाते हैं. बहुत कम लोगों ने स्थानीय सरकार न होने के विरुद्ध आंदोलन किया है. आज आवश्यकता इस बात की है कि पाकिस्तान में किसी भी प्रकार की स्थानीय शासन प्रणाली लाई जाए, ताकि जनता जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की तलाश कर सके.

डॉ. कैसर रशीद
feedback@chauthiduniya.com
(लेखक पाकिस्तान के पत्रकार हैं)

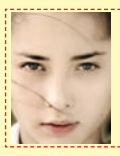

शंघाई एक्पो गॉर्डन में कचरा उठाने वाली एक 15 वर्षीया तिब्बती किशोरी को चीनी इंटरनेट फोरम ने सबसे ख़ूबसूरत लड़की का दर्जा दिया है.

सूचना का अधिकार जानने का अधिकार जीने का अधिकार चौथी दुनिया की पहल

बीपीएल चयन प्रक्रिया की जांच और आरटीआई

जिस देश की 37 फ़ीसदी से ज़्यादा आबादी ग़रीब हो, वहां यह ज़रूरी हो जाता है कि ग़रीबी से जुड़ी योजनाओं को ईमानदारी से लागू किया जाए, लेकिन व्यवहार में अब तक यही देखने को मिला है कि ग़रीबों के विकास के लिए बनाई गईं लगभग सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है. इस अंक में हम एक ऐसे ही मसले पर बात कर रहे हैं, जो सीधे-सीधे ग़रीबों के अधिकारों और उनके विकास से जुड़ा हुआ है यानी बीपीएल सूची, जिसके आधार पर ग़रीबों को बहुत सी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है. ज़ाहिर है, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बहुत से लोग किसी भी प्रकार अपना नाम बीपीएल सूची में शामिल करा लेते हैं. नतीजतन, जो ज़रूरतमंद लोग हैं और जिन्हें वाक़ई सरकारी मदद की ज़रूरत होती है, वे इससे वंचित रह जाते हैं. इस अंक में एक ऐसा ही आवेदन प्रकाशित किया जा रहा है, जिसके इस्तेमाल से आप बीपीएल सूची में पारदर्शिता बनाने का दबाव डाल सकते हैं और साथ ही सूची तैयार करते वक़्त इसमें होने वाली गड़बड़ियों को पकड़ सकते हैं या उसका ख़ुलासा कर सकते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि आप इस आवेदन का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और अन्य लोगों को भी इसके लिए उत्साहित करेंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

(बीपीएल के चयन के लिए किए गए सर्वे का विवरण)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,
.....ग्राम में ग़रीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के सर्वेक्षण केसंबंध में निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करें:

1. उपरोक्त गांव में ग़रीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के कितने कार्डधारक हैं, उनकी सूची निम्नलिखित विवरण के साथ उपलब्ध कराएं:
क. कार्डधारक का नाम
ख. पिता का नाम
ग. कार्ड संख्या
घ. कार्ड पर सदस्यों की संख्या (यूनिट)
2. उपरोक्त लोगों का ग़रीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड किस आधार पर बनाया गया? इस संबंध में कार्डधारकों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों की प्रति उपलब्ध कराएं.

3. उपरोक्त गांव में ग़रीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों का सर्वेक्षण पिछली बार कब हुआ था? उस सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएं, साथ ही सर्वेक्षण करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम व पद बताएं?

4. ग़रीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के सर्वेक्षण केसमय चयन के लिए क्या मापदंड/मानक बनाए गए हैं? इस संबंध में समस्त शासनादेशों/नियमों एवं निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं.
5. उपरोक्त सर्वेक्षण के उपरांत क्या कोई पुन: निरीक्षण (रिव्यू) किया गया? यदि हां, तो समस्त दस्तावेज़ों की प्रतियां उपलब्ध कराएं.

6. पुन: निरीक्षण (रिव्यू) के संबंध में समस्त शासनादेशों/नियमों एवं निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं.

7. सर्वेक्षण के दौरान किसी अनियमितता का मामला सामने आया? यदि हां, तो शिक़ायत पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण दें.

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.....रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम.....
पता.....
फोन नंबर.....

संलग्नक.....
(यदि कुछ हो तो)

राशिफल

मेष 21 मार्च से 20 अप्रैल
इस सप्ताह दूसरों के व्यवहार को सुधारने के लिए आपकी युक्ति ही कामयाब होगी. आप हमेशा बदलाव और आधुनिक सोच का स्वागत करते हैं. जहां तक हो सके, अपने आपको दूसरों के बीच सही साबित करने का उचित मौक़ा ढूंढ लें.

वृष 21 अप्रैल से 20 मई
आपके अंदर जो ज्ञान और आत्मविश्वास है, उसके बल पर आप अपनी छवि सुधारने में कामयाब हो सकते हैं. आप अपने प्रियजनों, परिवार के सदस्यों और सहयोगियों का विश्वास पाने में हमेशा सफल रहे हैं.

मिथुन 21 मई से 20 जून
कुछ अज्ञात और अस्वाभाविक परिस्थितियां आपके आगे पैदा होने वाली हैं. किसी ख़ास परिस्थिति में आपको ख़ुद ही ढलने की कोशिश करनी होगी. अगर कोई परेशानी या कष्ट आए तो उसे संभालने के लिए ख़ुद को मानसिक रूप से तैयार करना ज़रूरी है.

कर्क 21 जून से 20 जुलाई
इस सप्ताह आपका ध्यान घर, परिवार, मकान और जायदाद पर ज़्यादा रहेगा. परिवार में किसी बड़े-बुज़ुर्ग का स्वास्थ्य आपकी चिंता बढ़ा रहा है. संभव है, इसके लिए आपको कुछ आर्थिक उपाय भी करने पड़ें. जहां तक हो सकता है, आप तालमेल बैठाकर चलने में विश्वास रखते हैं.

सिंह 21 जुलाई से 20 अगस्त
आपको अपने व्यवहार के बारे में नई रणनीति अपनानी होगी. अगर आप दूसरों को सही तरीक़े से काम करने के लिए राज़ी नहीं कर सकते तो यही लगेगा कि आपका नेतृत्व कमज़ोर पड़ता जा रहा है. बेहतर यही है कि आप ख़ुद को ऐसी ज़िम्मेदारी से अलग करके सोच लें कि आपने एक नया रास्ता पकड़ लिया है.

कन्या 21 अगस्त से 20 सितंबर
यह सप्ताह आपके लिए व्यवसाय और कामकाज का दायरा बढ़ाने में मदद कर रहा है. यह दायरा आपकी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है. जहां तक संभव है, थोड़ा-बहुत फेरबदल करने के बाद आप एक नई व्यवस्था से अवगत हो जाएंगे. आज के समय में व्यापार में तरक्की का सबसे सुगम तरीक़ा यही है.

तुला 21 सितंबर से 20 अक्टूबर
इस सप्ताह कुछ समस्याएं हैं, जो आपके निजी और व्यवसायिक जीवन से जुड़ी हुई हो सकती हैं, लेकिन आपको अपने रवैये में सुधार लाना होगा. संवाद क्षमता और कूटनीति इस मामले में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है.

वृश्चिक 21 अक्टूबर से 20 नवंबर
आपको अपने कामकाज में एक नया जोश भरने की ज़रूरत है. आपके सहयोगी या सहकर्मी इस बात को लेकर काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय बने हुए हैं. अपने कार्यक्षेत्र या व्यापार में यदि आप इस प्रकार की रणनीति नहीं अपनाएंगे तो दूसरों के मुक़ाबले काफ़ी पीछे रह जाएंगे.

धनु 21 नवंबर से 20 दिसंबर
यदि कुछ उपयोगी तत्व और लोग आपसे विपरीत व्यवहार रखते हुए आपके कामकाज में दखल दे रहे हैं तो यह सप्ताह ऐसी दिक्क़तों को दूर करने में सहायक हो रहा है. उनके साथ संवाद स्थापित करने में आपकी सूझबूझ बहुत उच्च कोटि की है.

मकर 21 दिसंबर से 20 जनवरी
दूसरों को सुधारना आपके वश की बात नहीं है. इस सप्ताह भी कुछ ऐसी ही चुनौती आपको मिल सकती है. कई बार आप इस प्रकार के धर्म संकट से निकलने में कामयाब रहे. अब भी अच्छा यही है कि वाद-विवाद से दूर रहें.

कुंभ 21 जनवरी से 20 फरवरी
किसी संपत्ति या जायदाद से जुड़ी समस्या को आप इस सप्ताह गंभीरता से ले सकते हैं. यदि कोई सरकारी या क़ानूनी दांवपेच है और उसे आप ध्यान लगाकर टटोलते हैं तो आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा.

मीन 21 फरवरी से 20 मार्च
व्यापार या कारोबार में किसी नई चीज़ पर आपका ध्यान केंद्रित होगा. आपको आत्मविश्वास और लगन का परिचय देना होगा. यदि आप इधर-उधर भटक रहे हैं तो यह संभव नहीं होगा कि आप किसी जटिल काम को समय पर पूरा करने का बीड़ा उठाएं.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

चमत्कार को नमस्कार

कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार. फिर अगर बात भारत की हो तो फिर चमत्कार होना आम बात है. ऐसा आपने अक्सर फिल्मों में ही देखा होगा कि किसी व्यक्ति को मरा समझ कर नदी में बहा दिया जाता है और कई साल बाद वह वापस घर लौट आता है. एक ऐसा ही मामला असल में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में सामने आया है. बिजनौर निवासी डालचंद्र की मौत लगभग 12 साल पूर्व हो गई थी, मगर पिछले दिनों वह अचानक अपने घर आ गया. मरे हुए व्यक्ति की 12 साल बाद अचानक घर वापसी की ख़बर पूरे गांव में फैल गई. डालचंद्र के परिवारीजनों की ख़ुशी का ठिकाना नहीं था. दूसरी तरफ़ पूरा गांव उसे देखने के लिए घर के बाहर एकत्र हो गया. डालचंद्र जैसे ही घर पहुंचा, घर वाले आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे. डालचंद्र के साथ एक सपेरा भी था, जिसके साथ वह 12 साल तक रहा. घरवालों के अनुसार, डालचंद्र की मौत 9 जून, 1999 को हो गई थी. उसे खेत में काम करने के दौरान एक सांप ने काट लिया था. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. गांव की परंपरा थी कि सांप काटने से जिसकी मौत हो, उसे न जलाया जाए और न दफ़नाया जाए, बल्कि पानी में बहा दिया जाए. परंपरानुसार डालचंद्र को भी नदी में बहा दिया गया. डालचंद्र के साथ आए सपेरे रमेश ने बताया कि वह उसे नदी में बहता मिला था. रमेश ने बताया कि उसे लगा कि वह उसका इलाज अपनी जड़ी-बूटियों से कर सकता है, इसलिए वह डालचंद्र को अपने घर ले गया. सपेरे रमेश की मानें तो कुछ महीने बाद ही डालचंद्र की सांसें वापस आ गईं, मगर उसे कुछ याद नहीं रहा. भीख मांगते-मांगते जब वह पिछले दिनों अपने गांव के समीप पहुंचा तो उसे सभी बातें याद आ गईं और वह घर पहुंच गया. जब डालचंद्र को सांप ने काटा था, तब उसकी उम्र 20 साल थी और अब वह 32 साल का है.

कचरा और ख़ूबसूरती

कहते हैं कि ख़ूबसूरती की कोई परिभाषा नहीं होती, वह कहीं भी पाई जा सकती है. शंघाई एक्पो गॉर्डन में कचरा उठाने वाली एक 15 वर्षीया तिब्बती किशोरी को चीनी इंटरनेट फोरम ने सबसे ख़ूबसूरत लड़की का दर्जा दिया है. फोरम ने इंटरनेट का उपयोग करने वालों की राय के आधार पर इस लड़की को यह उपाधि दी है. समाचारपत्र चाइना डेली में प्रकाशित ख़बर के मुताबिक़, वेबसाइट सिना डॉट कॉम पर जारी एक सर्वेक्षण में इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों से पूछा गया कि शंघाई एक्पो की सबसे ख़ूबसूरत लड़की कौन है? जवाब में इस वेबसाइट पर एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें उस लड़की को एक्पो गॉर्डन में शीतलपेय की बेकार पड़ी बोतलें उठाते दिखाया गया है. इस लड़की का नाम ड्रोल्मा है और यह भूकंप की आपदा झेल रहे शंघाई प्रांत के यूशू नामक स्थान की निवासी है. ड्रोल्मा उन 300 ग़रीब लड़कियों में शामिल है, जिन्हें एक्पो में मुफ्त की सैर के लिए लाया गया था. वेबसाइट के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया कि ड्रोल्मा का काम एक्पो में कूड़ा उठाना नहीं था, लेकिन उसने शहरी लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बेकार पड़े कूड़े को उठाकर कूड़ेदान में डाला. इसी से प्रभावित होकर इंटरनेट का उपयोग करने वालों ने ड्रोल्मा को सबसे ख़ूबसूरत लड़की का दर्जा दिया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

लगता है, ब्रीविक को भारत से लगाव रहा है, लेकिन यह लगाव भारत की संस्कृति के प्रति कतई नहीं है. दरअसल, वह जिस बहु संस्कृतिवाद का विरोध करता है, भारत उसका प्रतिनिधि है.

नार्वे
मौत का तांडव

राजीव कुमार

विश्व के बेहद शांतिप्रिय देशों में शुमार नार्वे के लोगों को 22 जुलाई का दिन हमेशा याद रहेगा. यह नार्वे के लिए एक काला दिन था. द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद देश को पहली बार इतनी बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा. इस दिन प्रधानमंत्री कार्यालय से महज़ कुछ दूर स्थित एक सरकारी भवन के पास एक ज़ोरदार बम धमाका हुआ. यह बम एक कार में रखा हुआ था. प्रधानमंत्री कार्यालय की खिड़कियों के शीशे टूट गए. वित्त मंत्रालय और तेल मंत्रालय के भवनों को भी नुक़सान हुआ. इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. लोग चीख़ते-चिल्लाते हुए इधर-उधर भाग रहे थे. सड़क पर अफ़रातफ़री का माहौल छा गया. जिस बिल्डिंग के पास धमाका हुआ, उसके आसपास के मकानों की खिड़कियों के शीशे टूटकर बिखर गए. चारों ओर धुएं के बादल छा गए. एक प्रत्यक्षदर्शी जीम कैंटर कहती हैं, हम लोग हतप्रभ थे, किसी को कुछ पता नहीं कि अचानक यह क्या हो गया! सड़क पर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे. घायलों के शरीर से लगातार ख़ून बह रहा था. इसी तरह डेनियल चेरुविनी उस वक़्त अपने दोस्तों के साथ कॉफ़ी पी रहे थे, तभी अचानक हुए इस धमाके ने उन्हें चौंका दिया. वह कहते हैं, चारों तरफ़ चीख़-पुकार मची हुई थी, पुलिस और राहतकर्मी घायलों की सहायता में जुटे हुए थे और लोग इधर-उधर भाग रहे थे.

इस हादसे में तो जान का कम, माल का अधिक नुक़सान हुआ, लेकिन मात्र डेढ़ घंटे बाद जो घटना घटी, वह इस धमाके से ज़्यादा दिल दहला देने वाली थी. राजधानी ओस्लो से 35 किलोमीटर दूर स्थित यूटोया टापू पर एक हथियारबंद युवक ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं. इस गोलीबारी में दस लोगों ने तो मौक़े पर ही दम तोड़ दिया. धीरे-धीरे मरने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती चली गई और अंत में 85 लोगों के मारे जाने की ख़बर आई. एक ही दिन में बम और गोलीकांड में 93 लोग काल के गाल में समा गए. बताया जाता है कि टोटोया आईलैंड पर सत्ताधारी लेबर पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं का एक शिविर चल रहा था, तभी पुलिस की वर्दी में एक युवक वहां आया और उसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. अपनी जान बचाने में सफल रही एक युवती हाना बारजिंगी ने कहा कि हमलावर युवक पुलिस की वर्दी पहने हुए था, वह आया और बोला कि सारे लोग मेरे पास आ जाओ. यह सुनकर लोग उसके पास चले आए, तभी उसने फायरिंग शुरू कर दी. यह सब कुछ एक डरावने सपने की तरह था. लेबर पार्टी के उक्त शिविर में गईं सांसद स्टाइन हेहेइम भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागीं. उन्होंने बताया कि हम इमारत के भीतर थे. पहले तो हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, केवल गोलीबारी की आवाज़ सुनाई दी. लोग भागने लगे तो हम भी बाहर निकले. किसी ने कहा कि पुलिस आ गई है और अब हम सुरक्षित हैं. मैंने पुलिस की वर्दी में एक आदमी को देखा, जो लोगों की ओर आ रहा था. अचानक उसने फायरिंग शुरू कर दी, तब मैं उल्टे पांव भागी. जैसे ही हमने कुछ नावों को देखा, हम पानी में कूद गए और तैरते रहे. एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, जो लोग पानी में कूदकर भाग रहे थे, वह व्यक्ति उन पर पहले गोली चला रहा था. वह सबको मार देना चाहता था, उसकी आंखों में ख़ून सवार था.

इन दोनों घटनाओं को अंजाम देने वाला एक ही शख़्स था, एंडर्स बेहरिंग ब्रीविक. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. अभी तक जो जानकारी उपलब्ध है, उसके अनुसार, ब्रीविक चरमपंथी विचारधारा वाला युवक है. वह बहु संस्कृतिवाद का विरोधी है. उसने अपने इस कृत्य को वीभत्स तो माना, लेकिन वह ख़ुद को अपराधी नहीं मानता. उसका कहना है कि यह आवश्यक था. उसे किसी भी तरह का अपराधबोध नहीं है. उसके बारे में जानकारी मुख्य रूप से इंटरनेट से ही मिली, ऐसा पुलिस प्रमुख स्वेनंग स्पेनहेम का कहना है. उन्होंने कहा कि उसने इंटरनेट पर जो लिखा, उससे मालूम होता है कि वह दक्षिणपंथी है और मुस्लिम विरोधी विचार रखता है. अपने फेसबुक एकाउंट पर उसने ख़ुद को ईसाई और परंपरावादी बताया है. उसने यह भी लिखा कि उसे बॉडी बिल्डिंग का शौक़ है और उसकी फ्रीमैसन संस्था में दिलचस्पी है. हालांकि उसका फेसबुक एकाउंट अब उपलब्ध नहीं है. महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस फेसबुक एकाउंट से उसके बारे में जानकारी मिली, उसे इस वारदात के महज़ पांच दिन पहले 17 जुलाई को खोला गया था. ट्वीटर पर उसका केवल एक ही संदेश है, जिसमें प्रसिद्ध दर्शनशास्त्री जॉन स्टुअर्ट की एक उक्ति लिखी है कि सिर्फ़ अपने हितों की चिंता करने वाले एक लाख लोगों की फ़ौज से वह एक व्यक्ति अच्छा है, जिसके पास दृढ़ विश्वास है. कितने शर्म की बात है कि इस युवक ने दृढ़ विश्वास की बात तो अपने ज़ेहन में बैठा ली, लेकिन इसने ईसा मसीह की मानव कल्याण के लिए अपना जीवन तक क़ुर्बान करने की बात पर ग़ौर नहीं किया.

दिसंबर, 2009 में नार्वे के एक ऑनलाइन फोरम में एंडर्स बेहरिंग ब्रीविक के नाम से डाली गई एक पोस्ट में कहा गया है कि दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है, जहां मुस्लिम किसी ग़ैर मुस्लिमों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे हों. इसमें कहा गया है कि ग़ैर मुस्लिमों के लिए इसके परिणाम विनाशकारी होते हैं. अगर यह पोस्ट इसी युवक की है तो इसे मुस्लिम विरोधी कहा जा सकता है. वैसे अभी तक जो भी जानकारी मिली है उसके अनुसार, ब्रीविक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. माना जा रहा है कि ब्रीविक ओस्लो में ही पला-बढ़ा है और उसने ओस्लो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाई की है. राष्ट्रीय सेवा में रहने के अलावा उसे कोई सैन्य अनुभव भी नहीं है. बाद में वह ओस्लो से बाहर चला गया और उसने ब्रीविक जियोफार्म नामक एक कंपनी बनाई. यह कंपनी सब्ज़ी, तरबूज़ और शकरकंद उगाने का काम करती थी. खाद आपूर्ति करने वाली एक कंपनी ने कहा है कि उसने ब्रीविक जियोफार्म को छह टन खाद की आपूर्ति की थी. आशंका जताई जा रही है कि ओस्लो में जो बम धमाका हुआ, उसके लिए विस्फोटक तैयार करने के लिए इसी खाद की सहायता ली गई हो.

लगता है, ब्रीविक को भारत से लगाव रहा है, लेकिन यह लगाव भारत की संस्कृति के प्रति क़तई नहीं है. दरअसल, वह जिस बहु संस्कृतिवाद का विरोध करता है, भारत उसका प्रतिनिधि है. हिंदू राष्ट्रवाद से वह ख़ासा प्रभावित था. हमला करने से पूर्व उसने 1518 पन्नों का एक घोषणापत्र तैयार किया था, जिसके 102 पन्नों में किसी न किसी रूप में भारत का ज़िक्र किया गया है. उसने अपने घोषणापत्र में लिखा कि भारत के हिंदू राष्ट्रवादियों को भी भारतीय सांस्कृतिक मॉर्क्सवादियों की ओर से उसी तरह का उत्पीड़न सहन करना पड़ रहा है, जैसे उनके यूरोपीय भाइयों को. ब्रीविक ने अपने संगठन के लिए लोगों बनारस की एक कंपनी से बनवाया, जिसका मालिक मोहम्मद असलम अंसारी है. यह समझ में नहीं आया कि मुसलमानों से नफ़रत करने वाले इस युवक ने लोगो बनाने के लिए एक मुसलमान को ही क्यों चुना. अंसारी ने कहा कि पिछले एक साल से ईमेल के माध्यम से उसका संपर्क इस युवक से था. तो क्या ब्रीविक को उसके मुस्लिम होने की जानकारी नहीं थी? ख़ैर, इस युवक ने संस्कृति की रक्षा के नाम पर जिस तरह एक अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया, वह केवल नार्वे के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए ख़तरनाक है. इससे सांस्कृतिक आतंकवाद का ख़तरा पूरे विश्व पर मंडराने लगा है. ऐसे लोग आख़िर इस बात को कब समझेंगे कि संस्कृति की रक्षा के लिए विचार की ताक़त चाहिए, बंदूक की नहीं.

ब्रीविक को अदालत में पेश किया गया और उस पर आतंकवाद का मुक़दमा चलाया जा रहा है. अदालत ने मुक़दमे की खुली सुनवाई की मांग यह कहकर नामंज़ूर कर दी कि इससे ब्रीविक को अपनी विचारधारा के प्रचार में मदद मिल सकती है. उसके वकील ने बचाव की कोशिशें शुरू कर दी हैं. उसने कहा कि घटना को अंजाम देते वक़्त ब्रीविक ड्रग्स के प्रभाव में था. लेकिन जिस तरीक़े से पूरी योजना के साथ उसने इस घटना को अंजाम दिया, उससे क़तई नहीं लगता कि वह होश में नहीं था. उसने ड्रग्स का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा, क्योंकि ऐसी घटना को बिना किसी नशे के अंजाम नहीं दिया जा सकता. अदालत का फ़ैसला तो आएगा ही, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री स्टॉल्टन बर्ग ने घटना की जांच नार्वे कमीशन से कराने की घोषणा कर दी है. यह कमीशन घटना के सभी पहलुओं की जांच करेगा. सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस को मौक़े पर पहुंचने में इतनी देर क्यों लगी, हेलीकॉप्टर क्यों नहीं मंगाए गए. इसके अलावा इस घटना के तार ब्रिटेन से भी जुड़ रहे हैं, जिसकी जांच वहां के प्रधानमंत्री कैमरून करा रहे हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि घटना के पीछे की असलियत क्या है. प्रधानमंत्री स्टॉल्टन बर्ग ने कहा है कि नार्वे की जनता को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों में ख़ौफ़ अभी तक बरक़रार है. घटना के पांच दिन बाद जब ओस्लो में एक लावारिस बैग मिला तो अफ़रातफ़री मच गई. नार्वे के लोग सहमे हुए हैं और प्रत्येक संदिग्ध चीज़ उनके डर को बढ़ा देती है. सरकार के बार-बार कहने के बावजूद जनता को विश्वास नहीं है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी.

feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी
हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक
दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
स्पेशल रिपोर्ट
नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

मेरी कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनो, मनन करो. सुख और संतोष प्राप्ति का सरल मार्ग ही यही है. केवल साई-साई के उच्चारण मात्र से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे.

बाबा और सच्चरित्र अध्याय

विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा, उसे परमानंद और चिर संतोष की उपलब्धि हो जाएगी. यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो कोई अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, जो श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन, निरंतर स्मरण और ध्यान करता है, उसे मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूं. जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं-लीलाओं का प्रेमपूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं और अज्ञानरूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती हैं. मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूं. मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति मिल जाएगी.

बाबा ने सच्चरित्र लिखने की अनुमति देते हुए कहा कि सच्चरित्र लेखन के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है. तुम अपना मन स्थिर करके मेरे वचनों में श्रद्धा रखो और निर्भय होकर कर्तव्य पालन करते रहो. यदि मेरी लीलाएं लिखी गईं तो अविद्या का नाश होगा और ध्यान एवं भक्तिपूर्वक श्रवण करने से भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी. जो इन लीलाओं की अधिक गहराई तक खोज करेगा, उसे ज्ञानरूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हो जाएगी. इन वचनों को सुनकर हेमाडपंत को अति हर्ष हुआ और वह निर्भय हो गए. उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि अब कार्य अवश्य ही सफल होगा.

बाबा ने शामा की ओर देखते हुए कहा, जो प्रेमपूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा, मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, उसकी भक्ति में वृद्धि होगी. जो मेरे चरित्र और कृत्यों का श्रद्धापूर्वक गायन करेगा, उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूंगा. जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं, उन्हें मेरी कथाएं श्रवण कर स्वभावत: प्रसन्नता होगी. विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा, उसे परमानंद और चिर संतोष की उपलब्धि हो जाएगी. यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो कोई अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, जो श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन, निरंतर स्मरण और ध्यान करता है, उसे मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूं. जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं-लीलाओं का प्रेमपूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं और अज्ञानरूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती हैं. मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूं. मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति मिल जाएगी. अत: मेरी कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनो, मनन करो. सुख और संतोष प्राप्ति का सरल मार्ग ही यही है. केवल साई-साई के उच्चारण मात्र से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे.

● भिन्न-भिन्न कार्यों की प्रेरणा

भगवान अपने किसी भक्त को मंदिर-मठ, किसी को नदी के किनारे घाट बनवाने, किसी को तीर्थ भ्रमण और किसी को भगवत कीर्तन एवं भिन्न-भिन्न कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, परंतु उन्होंने मुझे साई सच्चरित्र लेखन की प्रेरणा दी. किसी भी विधा का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण मैं इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य था. अत: मुझे इस दुष्कर कार्य का दुस्साहस क्यों करना चाहिए. श्री साई महाराज की यथार्थ जीवनी का वर्णन करने की सामर्थ्य भला किस में है. उनकी कृपा मात्र से ही कार्य संपूर्ण होना संभव है. इसीलिए जब मैंने लेखन प्रारंभ किया तो बाबा ने मेरा अहं नष्ट कर दिया और उन्होंने स्वयं अपना चरित्र रचा. अत: इस चरित्र का श्रेय उन्हीं को है, मुझे नहीं. जन्मत: ब्राह्मण होते हुए भी मैं दिव्य चक्षु विहीन था, अत: साई सच्चरित्र लिखने में सर्वथा अयोग्य था, परंतु श्री हरिकृपा से क्या संभव नहीं है. मूक भी वाचाल हो जाता है और पंगु भी गिरिवर चढ़ जाता है. अपनी इच्छानुसार कार्य पूर्ण करने की युक्ति वह ही जानें. हारमोनियम और बंसी को यह आभास कहां कि ध्वनि कैसे प्रसारित हो रही है. इसका ज्ञान तो वादक को ही है. चंद्रकांत मणि की उत्पत्ति और ज्वार-भाटे का रहस्य मणि अथवा उदधि नहीं, वरन शशिकलाओं के घटने-बढ़ने में ही निहित है.

● ज्योति स्तंभ स्वरूप

समुद्र में अनेक स्थानों पर ज्योति स्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं, जिससे नाविक चट्टानों और दुर्घटनाओं से बच जाएं और जहाज़ को कोई हानि न पहुंचे. इस भवसागर में श्री साई बाबा का चरित्र ठीक उसी भांति उपयोगी है. वह अमृत से भी अति मधुर और सांसारिक पथ को सुगम बनाने वाला है. जब वह कानों द्वारा हृदय में प्रवेश करता है, तब दैहिक बुद्धि नष्ट हो जाती है और हृदय में एकत्रित करने से समस्त कुशंकाएं अदृश्य हो जाती हैं. अहंकार का विनाश हो जाता है और बौद्धिक आवरण लुप्त होकर ज्ञान प्रगट हो जाता है. बाबा की विशुद्ध कीर्ति का वर्णन निष्ठापूर्वक श्रवण करने से भक्तों के पाप नष्ट होंगे. अत: यह मोक्ष प्राप्ति का भी सरल साधन है. सतयुग में शम एवं दम, त्रेता में त्याग, द्वापर में पूजन और कलियुग में भगवत कीर्तन ही मोक्ष का साधन है. यह अंतिम साधन चारों वर्णों के लोगों को साध्य भी है. अन्य साधन योग, त्याग, ध्यान-धारणा आदि आचरण करने में कठिन हैं, परंतु चरित्र तथा हरि कीर्तन के श्रवण से इंद्रियों की स्वाभाविक विषयासक्ति नष्ट हो जाती है और भक्त वासना रहित होकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाता है. इसी फल को प्रदान करने के लिए उन्होंने सच्चरित्र का निर्माण कराया. भक्तगण अब सरलतापूर्वक चरित्र का अवलोकन करें और साथ ही उनके मनोहर स्वरूप का ध्यान करके गुरु और भगवत भक्ति के अधिकारी बनें तथा निष्काम होकर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हों. साई सच्चरित्र का सफलतापूर्वक संपूर्ण होना साई की महिमा ही समझें, हमें तो केवल एक निमित्त मात्र ही बनाया गया है.

● मातृ प्रेम

गाय का अपने बछड़े पर प्रेम सर्वविदित है. उसके स्तन सदैव दुग्ध से पूर्ण रहते हैं और जब भूखा बछड़ा स्तन की ओर दौड़कर आता है तो दुग्ध की धारा स्वत: प्रवाहित होने लगती है. उसी प्रकार माता भी अपने बच्चे की आवश्यकता का पहले से ही ध्यान रखती है और ठीक समय पर स्तनपान कराती है. वह बालक का शृंगार उत्तम ढंग से करती है, परंतु बालक को इसका कोई भान ही नहीं होता. माता का प्रेम विचित्र, असाधारण और नि:स्वार्थ है, जिसकी कोई उपमा नहीं है. ठीक इसी प्रकार सद्गुरु का प्रेम अपने शिष्य पर होता है.

● रोहिला की कथा

यह कथा श्री साई बाबा के समस्त प्राणियों पर समान प्रेम की सूचक है. एक समय रोहिला जाति का एक मनुष्य शिरडी आया. वह ऊंचा, सुदृढ़ एवं सुगठित शरीर का था. बाबा के प्रेम से मुग्ध होकर वह शिरडी में ही रहने लगा. वह आठों प्रहर अपनी उच्च और कर्कश ध्वनि में कुरान शरीफ पढ़ता और अल्लाह हो अकबर के नारे लगाता था. शिरडी के अधिकांश लोग खेतों में दिन भर काम करने के बाद जब रात्रि में घर लौटते तो रोहिला की कर्कश पुकार उनका स्वागत करती. इस कारण उन्हें रात्रि में विश्राम न मिलता. जब यह कष्ट असहनीय हो गया, तब उन्होंने बाबा के पास जाकर रोहिला को मना करके इस उत्पात को रोकने की प्रार्थना की.

बाबा ने लोगों की इस प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया. वह गांववालों को ही आड़े हाथों लेते हुए बोले कि वे अपने कार्य पर ध्यान दें और रोहिला की ओर ध्यान न दें. बाबा ने उनसे कहा कि रोहिला की पत्नी बुरे स्वभाव की है और वह रोहिला को और मुझे कष्ट पहुंचाती है, परंतु वह उसके कलामों के सामने उपस्थित होने का साहस करने में असमर्थ है और इसी कारण रोहिला शांति और सुख में है. यथार्थ में रोहिला की कोई पत्नी नहीं थी. बाबा का संकेत केवल कुविचारों की ओर था. अन्य विषयों की अपेक्षा बाबा प्रार्थना और ईश आराधना को महत्व देते थे. अत: उन्होंने रोहिला के पक्ष का समर्थन करके ग्रामवासियों को शांतिपूर्वक थोड़े समय तक उत्पात सहन करने का परामर्श दिया.

● बाबा के अमृतोपदेश

एक दिन दोपहर की आरती के बाद भक्तगण अपने घरों को लौट रहे थे, तब बाबा ने निम्नलिखित अति सुंदर उपदेश दिया. तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो, सो करो, परंतु यह सदैव स्मरण रखो कि जो कुछ तुम करते हो, वह सब मुझे ज्ञात है. मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घट-घट में व्याप्त हूं. मेरे ही उदर में समस्त जड़ और चेतन प्राणी समाए हुए हैं. मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रणकर्ता एवं संचालक हूं. मैं ही उत्पत्ति और संहार कर्ता हूं. मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता. मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पाश में फंस जाता है. समस्त जंतु, चीटियां, दृश्यमान, परिवर्तनमान और स्थायी विश्व मेरे ही स्वरूप हैं.

इस सुंदर और अमूल्य उपदेश को श्रवण कर मैंने तुरंत यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब भविष्य में अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी मानव की सेवा न करूंगा. तुझे नौकरी मिल जाएगी, बाबा का यह वचन सुनकर मुझे विचार आने लगा कि क्या सचमुच ऐसा घटित होगा. बाबा का वचन सत्य निकला और मुझे अल्पकाल में ही नौकरी मिल गई.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

श्री साई महिमा

श्री साई राम परम सत्य, प्रकाश रूप,
परम पावन शिरडी निवासी, परम ज्ञान आनंद
स्वरूप, प्रज्ञा प्रदाता, सच्चिदानंद स्वरूप,
परम पुरुष योगीराज, दयालु देवाधिदेव हैं,
उनको बार-बार नमस्कार.

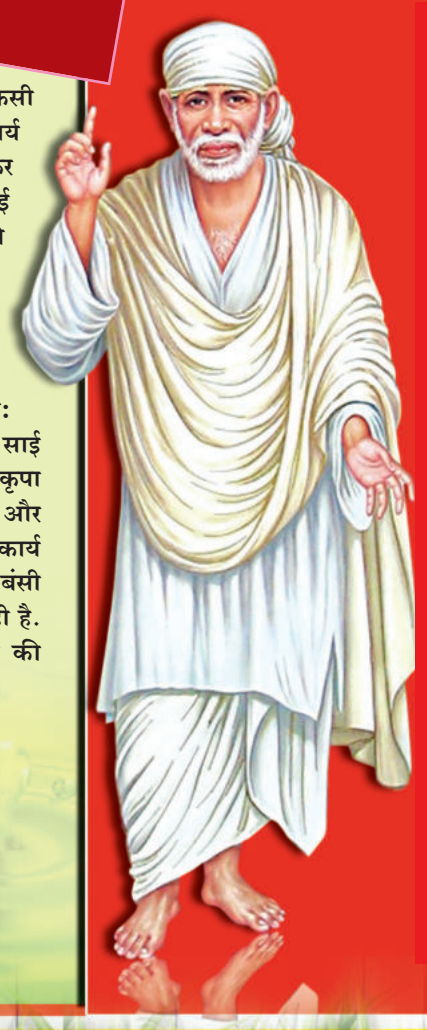

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ ख़ाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

हंस के छब्बीसवें वर्ष के पहले अंक को देखकर मैं थोड़ा नॉस्टेलिक भी हो गया. मुझे अपने कॉलेज के दिनों और अपने शहर जमालपुर की याद आ गई.

अनंत विजय

साहित्यिक डॉन का कारनामा

साहित्यिक पत्र–पत्रिकाओं को ख़रीदने के लिए अक्सर मैं दिल्ली के मयूर विहार इलाक़े में जाता हूं, जहां लोक शॉपिंग सेंटर के पास फुटपाथ पर तीन दुकानें लगती हैं. बिपिन के बुक स्टॉल पर मैं तक़रीबन डेढ़ दशक से जा रहा हूं. इस बीच वहां पत्र–पत्रिकाओं की तीन दुकानें सजने लगीं. जैसे ही मैं बिपिन की दुकान पर पहुंचता हूं, वहां मौजूद शख्स मुझे या तो हंस या कथादेश या फिर पाखी पकड़ा देगा. जब तक मैं मयूर विहार इलाक़े में रहा तो उसकी दुकान पर नियमित जाता रहा. उसके बाद अब तो हफ्ते में एक बार ही जाना हो पाता है. वह भी इस वजह से कि इंदिरापुरम इलाक़े में कोई अच्छी दुकान नहीं है, जहां साहित्यिक पत्र–पत्रिकाएं उपलब्ध हों. यह एक बड़ी समस्या है, किस तरह से किसी ख़ास पत्रिका या अख़बार ख़रीदने के लिए दस–बारह किलोमीटर जाना और फिर लौटना पड़ता है. ख़ैर, अगर मौक़ा मिला तो इस विषय पर फिर कभी विस्तार से लिखूंगा. अभी तो जब मैं मयूर विहार के बुक स्टॉल पर गया तो उसने मुझे हंस, शुक्रवार समेत कई पत्र–पत्रिकाएं पकड़ा दीं. घर लौटकर जब उन पत्र–पत्रिकाओं को उलटना–पलटना शुरू किया तो हंस के ताज़ा अंक पर छब्बीसवें वर्ष का पहला अंक लिखा देखकर चौंका. अगस्त दो हज़ार ग्यारह के अंक का मुखपृष्ठ गर्व से इसकी उद्घोषणा कर रहा था कि हमने अपने प्रकाशन के पच्चीस वर्ष पूरे कर लिए हैं. है भी यह गर्व की ही बात! जब हमारे देश में एक–एक करके सारी साहित्यिक पत्रिकाएं बंद हो रही थीं तो उस माहौल में हंस ने अपने आपको शान से ज़िंदा रखा. न केवल ज़िंदा रखा, बल्कि हिंदी साहित्यिक पत्रिकाओं को सेठाश्रयी पत्रिकाओं की भाषा, कलेवर और तेवर तीनों से मुक्त कर एक नया रास्ता गढ़ा. नए रास्ते पर चलना हमेशा से ख़तरनाक माना जाता है. राजेंद्र जी की इस बात के लिए तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने हंस के लिए न केवल नया रास्ता तलाश किया, बल्कि निर्भीकता के साथ, आलोचनाओं के तीर झेलते हुए उसे नए रास्ते पर ही चलाए रखा.

हंस के छब्बीसवें वर्ष के पहले अंक को देखकर मैं थोड़ा नॉस्टेलिक भी हो गया. मुझे अपने कॉलेज के दिनों और अपने शहर जमालपुर की याद आ गई. हमारे शहर में रेलवे स्टेशन पर एएच व्हीलर का स्टॉल ही हमारे लिए उम्मीद की एकमात्र किरण हुआ करता था. अस्सी के दशक के अंत में जमालपुर का व्हीलर स्टॉल इलाहाबाद के पांडे जी का हुआ करता था. वह साहित्य प्रेमी थे, इस वजह से उनके स्टॉल पर साहित्यिक पत्र–पत्रिकाएं मिल जाया करती थीं. राजस्थान से निकलने वाली पत्रिका मधुमती तक उनके पास पहुंचती थी, पहल, वसुधा, इंद्रप्रस्थ भारती आदि तो आती ही थीं. मैंने पहली बार हंस वहीं से ख़रीदा था, महीना और साल ठीक से याद नहीं है. फिर तो हंस का हर अंक ख़रीदने लगा, पढ़ने लगा. मंडल आंदोलन के दौरान और उसके बाद राजेंद्र यादव के स्टैंड से घनघोर असहमतियां रहीं, लेकिन कभी हंस ख़रीदना बंद नहीं किया. जमालपुर में हंस की दस प्रतियां आती थीं, जो महीने की सात या फिर आठ तारीख़ को पहुंचती थीं. दिल्ली से प्रतियां वीपीपी से आया करती थीं. इस पद्धति में डाकघर जाकर वहां पैसे जमा करने के बाद ही बंडल मिलता था. व्हीलर के हमारे पंडित जी के लिए हंस का बंडल भी अन्य किताबों के बंडल की तरह से होता था. जब वक़्त मिलता था तो किसी को भेजकर डाकघर से बंडल मंगवा लेते थे. लेकिन होता यह था कि पटना में हंस रेल से आता था, जो दो–तीन दिन पहले आ जाया करता था. वहां से मित्रों का फोन आना शुरू हो जाता था कि हंस में फ़लां लेख या फ़लां कहानीकार की कहानियां देखीं, जो हमारी बेचैनी बढ़ा दिया करती थीं.

मुझे याद है कि कई बार मैं ख़ुद डाकघर जाकर हंस का बंडल छुड़वा कर व्हीलर के स्टॉल पर पहुंचाया करता था. बाद में हमने हंस को जल्दी पाने का एक विकल्प निकाला. हमने डाकिया को पटाया और उससे अनुरोध किया कि वह अपनी साइकिल पर हंस का बंडल डाकघर से उठा लाया करे और व्हीलर के पंडित जी को सौंप दे. फ़ायदा यह हुआ कि हंस जिस दिन हमारे शहर के डाकघर में आता, उसी दिन हमें उपलब्ध हो जाता था, लेकिन फिर भी पटना से लेट ही मिलता था. हंस को ख़रीदने की यह बेचैनी अब तक बरक़रार है. महीने की 23–24 तारीख़ से ही राजेंद्र जी के प्राण लेने लग जाता हूं कि हंस जनहित में कब जारी हो रहा है. जनहित का मतलब है कि बिक्री के लिए दिल्ली के स्टॉलों पर कब पहुंच रहा है. कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि हंस लेने राजेंद्र जी के दफ्तर या फिर घर तक पहुंच गया. हंस ने छब्बीसवें साल में क़दम रखते हुए जो पहला अंक निकाला है, उसमें हंस और साहित्यिक पत्रिकाओं पर अशोक वाजपेयी, रवींद्र कालिया, जनसत्ता के कार्यकारी संपादक ओम थानवी, पंकज बिष्ट, अखिलेश और शैलेंद्र सागर के लेख छपे हैं. लगभग सभी लेखों का केंद्रीय भाव एक ही है.

अशोक वाजपेयी ने लिखा है, इसे भी निसंकोच स्वीकार किया जाना चाहिए कि हिंदी में नारी विमर्श और दलित विमर्श की आज जो जगह है, लगभग केंद्रीय, उसे वह दिलाने में हंस ने बड़ी भूमिका निभाई है. ऐसा करके उसने न सिर्फ़ हिंदी साहित्य में इन दोनों विमर्शों और उनसे जुड़ी और प्रेरित रचनात्मकता को स्थापित किया, बल्कि पोसा और बढ़ाया. वाजपेयी आगे लिखते हैं, यह नोट करना सुखद है कि पच्चीस वर्षों तक चलने के बाद भी हंस एक पठनीय पत्रिका है, वह आज भी प्रासंगिक बनी हुई है. ज्ञानोदय के संपादक रवींद्र कालिया ने लिखा है, हंस के अवदान को नज़रअंदाज़ किया ही नहीं जा सकता. हंस दीर्घजीवी न होता तो आज हिंदी कहानी बहुत पिछड़ चुकी होती. हिंदी कहानी को ज़िंदा रखने और बोल्डनेस को डिफेंड करने में राजेंद्र जी की अपूर्व भूमिका है. राजेंद्र जी ने यथास्थितिवाद पर लगातार प्रहार किए और दलित तथा नारी विमर्श को सामने लाने और निरंतर उसे गतिशीलता प्रदान करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी. तद्भव के संपादक अखिलेश भी यह मानते हैं कि हंस ने हिंदी साहित्य का एजेंडा बदल दिया. दलित, स्त्री, पिछड़ा और अल्पसंख्यक यदि आज समाज और साहित्य के सरोकार बने हैं तो इसके पीछे हंस का भी पसीना है.

तो हम यह देख रहे हैं कि हंस के बारे में हिंदी जगत की कमोबेश एक ही राय है. पिछले पच्चीस सालों में हंस ने हिंदी साहित्य को न केवल एक नई दिशा दी, बल्कि उसने दलित और स्त्री विमर्श के साथ–साथ तत्कालीन प्रासंगिक मुद्दों को उठाकर हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता का एक नया इतिहास भी लिखा और साहित्यिक पत्रकारिता के कुछ नए मानक भी स्थापित किए. जिस तरह की खुली बहस से दूसरी पत्रिका के संपादकों के हाथ–पांव फूल जाते थे, उसे राजेंद्र यादव ने हंस में ज़ोरदार तरीक़े से उठाया. ख़ुद अपने संपादकीय में बिना किसी डर और लाग लपेट के यादव जी ने अपनी बातें कहकर बहस में सार्थक हस्तक्षेप किया. अपने प्रकाशन के शुरुआती दिनों से ही हंस ने साहित्यिक माहौल को गर्मागर्म बनाए रखा और जो मुर्दनीछाप शास्त्रीय क़िस्म का माहौल था, उसे सक्रिय करते हुए जुझारू तेवर भी प्रदान किए. इसके अलावा हंस ने कहानीकारों की कई पीढ़ियां भी तैयार कर दीं.

हंस ने अपने प्रकाशन के शुरुआती वर्षों में ही उदय प्रकाश की तिरिछ, शिवमूर्ति की तिरिया चरित्तर, ललित कार्तिकेय की तलछट का कोरस, रमाकांत की कार्लो हब्शी का संदूक, चंद्र किशोर जायसवाल की हंगवा घाट में पानी रे और आनंद हर्षुल की उस बूढ़े आदमी के कमरे में आदि कहानियां छापकर हिंदी कथा साहित्य में हलचल मचा दी थी. कालांतर में भी हंस में ही छपी उदय प्रकाश की चर्चित कहानियां और अंत में प्रार्थना, पीली छतरी वाली लड़की, अरुण प्रकाश की जल प्रांतर, अखिलेश की चिट्ठी, स्वयं प्रकाश की अविनाश मोटू उर्फ़..., संजय की कॉमरेड का कोट आदि कहानियों ने भी कथा साहित्य को झकझोर दिया था. तो हंस को पच्चीस साल पूरे करने पर बधाई और उसके संपादक की जिजीविषा और दृढ़ इच्छाशक्ति को सलाम. ईश्वर से प्रार्थना इस बात की कि राजेंद्र यादव जी को लंबी उम्र मिले और हंस निर्बाध गति से निकलता रहे.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.tbn@gmail.com

सिक्कों की दुनिया की सैर

सर्वश्रेष्ठ पुस्तक समीक्षा

जबसे मुद्रा का विकास हुआ है, तभी से यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग रही है. इसके बिना जीवन की कल्पना तक संभव नहीं है. हाल में राजकमल प्रकाशन की एक किताब भारतीय सिक्कों का इतिहास पढ़ने का मौक़ा मिला. कुछ वक़्त पहले जब चवन्नी का चलन बंद हुआ था, तबसे ही भारतीय मुद्रा के बारे में जानने की जिज्ञासा थी. लेखक गुणाकर मुले ने इस किताब के लिए काफ़ी शोध किया है. इस किताब को कई अध्यायों में बांटा गया है, जैसे सिक्कों की शुरुआत, भारत के सबसे पुराने पंचमार्क सिक्के, मौर्यकाल के पंचमार्क सिक्के, हिंद–यवन शासकों के सिक्के, शक प लव शासकों के सिक्के, कुषाणों के सिक्के, पश्चिमी क्षत्रपों के सिक्के, गणराज्यों और जनपदों के सिक्के, भारत में रोमन सिक्के, सात वाहनों के सिक्के, गुप्त सम्राटों के सिक्के, हेफतालों के सिक्के, मध्यकालीन उत्तर भारतीय मुद्राएं, दक्षिण भारत के सिक्के, पांड्य, चोल और चेर शासकों के सिक्के, इस्लामी शासकों के सिक्के, दिल्ली सल्तनत के सिक्के, सल्तनत कालीन प्रांतीय राज्यों के सिक्के, मुग़ल शासकों के सिक्के, मुग़ल कालीन प्रादेशिक राज्यों के सिक्के, यूरोप की व्यापारी कंपनियों के सिक्के, भारत में अंग्रेजी राज के सिक्के, सिक्कों की लिपियां और भाषा आदि.

इस किताब में सिक्कों के बारे में बेहद रोचक और ज्ञानवर्द्धक जानकारी मिलती है. इस्लाम में सिक्कों पर प्रतिमांकन कराने की प्रथा नहीं थी, इसलिए कुछ अपवादों को छोड़कर, भारत के इस्लामी शासकों के सिक्कों के दोनों तरफ़ केवल मुद्रालेख ही देखने को मिलते हैं. प्राचीन भारत के शासकों की ही तरह इस्लामी शासकों में भी सिंहासन संभालते ही नए सिक्के जारी करने की प्रथा रही है. प्राचीन भारत के सिक्कों को देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि वे किस टकसाल में तैयार किए गए थे, लेकिन इस्लामी शासकों ने सिक्कों पर टकसाल की जगह का नाम अंकित कराने की प्रथा शुरू की. इतना ही नहीं, इन टकसालों को कुछ विशिष्ट नाम भी दिए गए, जैसे दिल्ली को देहली हज़रत, दारुल ख़िलाफ़त, दारुल मुल्क, दारुल इस्लाम. दिल्ली के सुल्तानों ने दौलताबाद में भी टकसाल स्थापित की थी. शेरशाह के समय (1540–1545) में टकसालों की तादाद 23 तक पहुंच गई थी. अकबर के शासनकाल (1556–1605) में देश में 76 टकसालें थीं. सिक्कों पर टकसालों के उल्लेख से उन स्थानों के शासकीय महत्व और राज्य की सीमाओं के बारे में जानकारी मिलती है. ज़्यादातर मुस्लिम शासकों के सिक्के शुद्ध धातु और प्रामाणिक तौल के हैं. अकबर के शासनकाल में कोई भी व्यक्ति अपना सोना या अपनी चांदी टकसाल में ले जाकर उसके सिक्के तैयार करा सकता था. चांदी के रुपये बनवाने के लिए उसे कुल मुद्रांकित धातु का क़रीब 5.6 फ़ीसदी मुद्रा निर्माण के लिए देना होता था. मुग़ल बादशाहों में जहांगीर (1605–1627) के सिक्के सबसे सुंदर हैं. उसे नए–नए सिक्के बनवाने का शौक़ था.

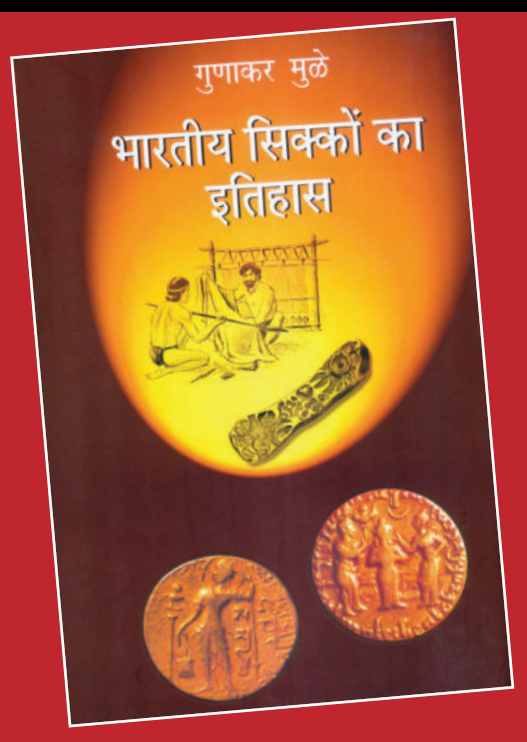

समीक्ष्य कृति : भारतीय सिक्कों का इतिहास
लेखक : गुणाकर मुले
प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
मूल्य : 350 रुपये

बाबर और हुमायूं के चांदी के दिरहम मध्य एशियाई शैली के हैं और तैमूरी वंश के शासक शाहरुख़ के नाम पर शाहरुख़ी कहलाते हैं. क़रीब 72 ग्रेन के इन सिक्कों के पुरोभाग पर कलमा और ख़लीफ़ाओं के नाम तथा पृष्ठभाग पर बादशाह का नाम है. शेरशाह सूरी ने अपने चंद सालों के शासन के दौरान भारतीय मुद्रा प्रणाली को एक नई दिशा दी थी. उसने मिश्र धातु का इस्तेमाल बंद करवा दिया और शुद्ध चांदी के मानक रुपये को चलाया. अकबर ने सोना, चांदी और तांबे के अपने सिक्कों के लिए सूरी शैली, तौल और बनावट को अपनाया. बुनियादी सिक्का चांदी का रुपया था, जिसका तौल 11.5 माशा या 178 ग्रेन के बराबर था. अकबर के पूरे राज्य में एक ही तौल के रुपये का प्रचलन था और उसकी चांदी की मुद्राओं में चार फ़ीसदी से ज़्यादा मिलावट कभी नहीं रही.

टीपू सुल्तान ने अपने 17 सालों (1782–1799) के शासनकाल में तरह–तरह के की मुद्राएं जारी कीं. टीपू ने न केवल सोने के पगोद, पणम, चांदी के रुपये और दोहरे रुपये आदि जारी किए, बल्कि तांबे के भी विविध तौल के सिक्के जारी किए. इन सिक्कों को नाम दिए गए. चौथाई मुहर को फ़ारूख़ी, एक रुपये को अहमदी, दोहरे रुपये को हैदरी आदि. ये सब इस्लाम से संबंधित नाम हैं. कुछ सिक्कों के नाम ग्रहों और नक्षत्रों के नाम पर भी रखे गए.

देश के आज़ाद होने के बाद जो सिक्के ढाले गए, वे 1947 से 1950 के दौर के थे. एक अप्रैल, 1957 को भारतीय मुद्रा अधिनियम लागू हुआ तो सिक्कों में बदलाव आया. इसके पहले आना प्रणाली के सिक्कों का चलन था. इसमें एक रुपया 16 आने के बराबर था. भारतीय मुद्रा अधिनियम के बाद दशमलव प्रणाली आई. रुपये का चलन वैसा ही था, लेकिन आना के बजाय उसकी क़ीमत 100 पैसे के बराबर हो गई. जनता में रुपया नया पैसा के नाम से प्रचलित हुआ. 60 के दशक में तांबे एवं निकल के सिक्के बने. इनमें षटकोण वाले 3 पैसे का सिक्का, लहरियेदार किनारे वाला 20 पैसे का सिक्का प्रचलित था. 70 के दशक में एक, दो एवं तीन पैसे का चलन लगभग ख़त्म होने लगा और उस वक़्त स्टील के 10, 25 एवं 50 पैसे को शामिल किया गया. बाद में विभिन्न विशेष अवसरों पर सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ, जिन पर नहर, हल जोतने और फ़सल काटते किसान आदि अंकित होते थे. कई सिक्कों पर एक तरफ़ भारत गणराज्य का राज्य चिन्ह एवं सत्यमेव जयते और दूसरी तरफ़ महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी आदि की तस्वीरें या राष्ट्रीय इमारतें अंकित थीं. 1972 में 50 पैसे और 10 रुपये के सिक्कों पर सर्वप्रथम संसद भवन का अंकन हुआ था. भारत में चार सरकारी टकसालें हैं. ये महाराष्ट्र में मुंबई, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, आंध्रप्रदेश में हैदराबाद और उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में हैं. भारतीय सरकार पर पर सिक्कों को बनाने की ज़िम्मेदारी है और ये सभी भारतीय टकसालों से भारतीय रिजर्व बैंक पहुंचते हैं. बहरहाल, इतिहास और पुरातत्व में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह किताब बेहद उपयोगी है.

राबिया बेगम
feedback@chauthiduniya.com

किताब मिली

पुस्तक का नाम
ओसामा का अंत

लेखक
राजकुमार सिंह

प्रकाशक
डायमंड बुक्स

मूल्य
95 रुपये

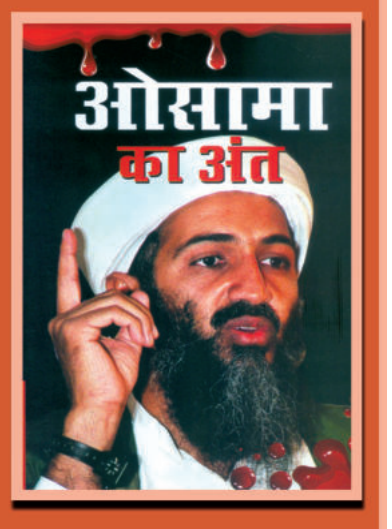

इस किताब में ओसामा बिन लादेन के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है.

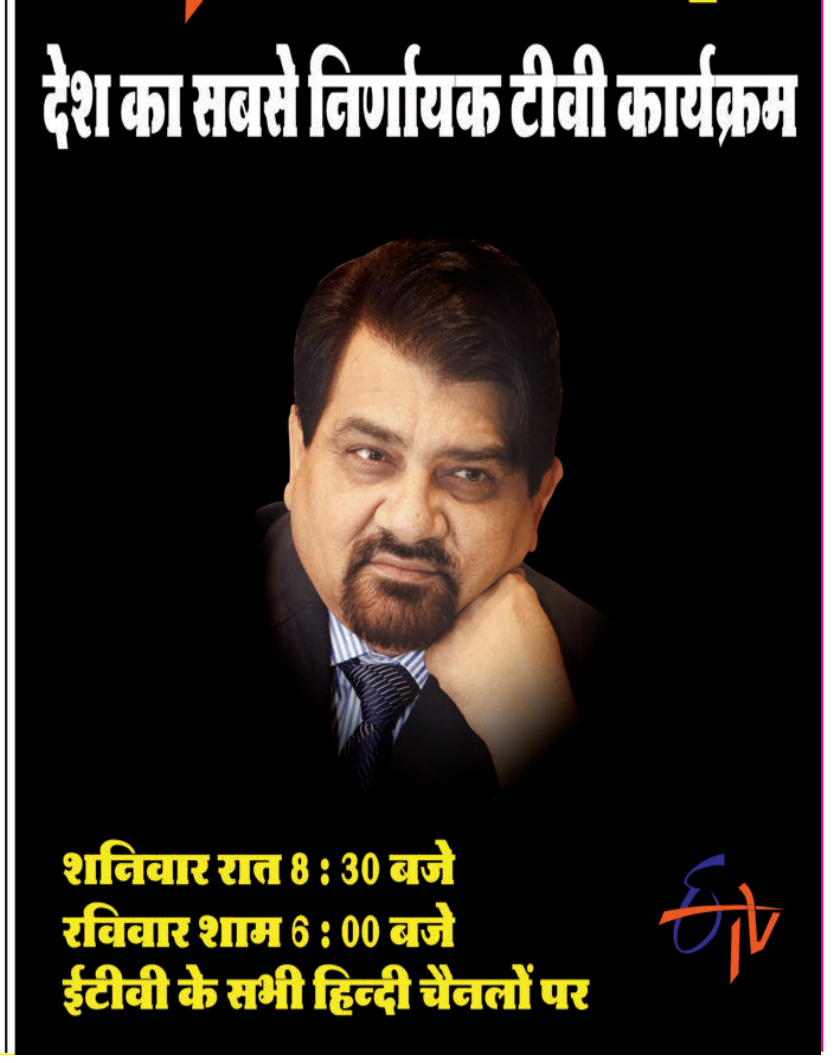

मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी एवं सीईओ पीटर टी होनेग्ग और डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग देवाशीष मित्रा ने कार्ज ऑन रेंट के प्रबंध निदेशक राजीव विज को औपचारिक रूप से ये कारें सौंपीं.

फुजी का आधुनिक डिजिटल कैमरा

इस डिजिटल कैमरे में वाइल्ड लाइफ फोटो के शौक़ीन लोगों के लिए विशेष सुविधाएं हैं. कैमरे में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ के लिए विशेष लेंस दिए गए हैं.

फोटोग्राफी के शौक़ीन लोगों के लिए फुजी फिल्म ने आधुनिक तकनीक से युक्त एक कैमरा बाज़ार में लांच किया है. कंपनी का कहना है कि फाइनपिक्स एचएस ईएक्सआर नामक इस कैमरे में अलग तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इस तकनीक के कारण इस कैमरे से खीची गई तस्वीरें अन्य कैमरों के मुक़ाबले कहीं बेहतर होंगी. इस डिजिटल कैमरे में वाइल्ड लाइफ फोटो के शौक़ीन लोगों के लिए विशेष सुविधाएं हैं. कैमरे में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ के लिए विशेष लेंस दिए गए हैं.

एमटीएस का सुपर फास्ट इंटरनेट

कंपनी ने देश में अपने दूरसंचार परिचालन में अब तक 3 अरब डॉलर से अधिक रक़म का निवेश किया है.

एमटीएस ने सुपर फास्ट इंटरनेट हाईवेज के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है. एनएच-08 का 265 किलोमीटर लंबा दिल्ली-जयपुर राजमार्ग देश के व्यस्त राजमार्गों में शामिल है. अब लोग इस राजमार्ग पर अपनी यात्रा के दौरान एमटीएस टीवी का इस्तेमाल करके लाइव टीवी और ऑन डिमांड वीडियो चैनल का आनंद उठा सकेंगे. कंपनी ने देश में अपने दूरसंचार परिचालन में अब तक 3 अरब डॉलर से अधिक रक़म का निवेश किया है. कंपनी ने सभी सुपर फास्ट इंटरनेट हाईवेज से जुड़े मज़बूत रिटेल नेटवर्क की योजना बनाई है.

कॉर्ज ऑन रेंट ने 90 मर्सिडीज बेंज ख़रीदीं

पीटर टी होनेग्ग और देवाशीष मित्रा ने कहा, भारत में आजकल लोगों की जीवनशैली अंतरराष्ट्रीय है और मोबिलिटी की इनकी प्राथमिकताओं से इनके स्टेटस का पता चलता है.

मोबिलिटी सोल्यूशंस कंपनी कार्ज ऑन रेंट ने 90 मर्सिडीज बेंज सी क्लास कारें ख़रीदी हैं. ये कारें ख़ासतौर से प्रीमियम यात्रियों को लक्ष्य करके तैयार की गई हैं. कार्ज ऑन रेंट पिछले कई वर्षों से ऐसे ग्राहकों को अपनी सेवाएं मुहैया कराती रही है. मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी एवं सीईओ पीटर टी होनेग्ग और डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग देवाशीष मित्रा ने कार्ज ऑन रेंट के प्रबंध निदेशक राजीव विज को औपचारिक रूप से ये कारें सौंपीं. राजीव विज ने कहा, लक्जरीयस पर्सनल मोबिलिटी सोल्यूशन की मांग तेज़ी से बढ़ रही है. हमारी साझेदारी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एवं देशी विमान सेवाओं, होटलों और वित्तीय कंपनियों से है और हम उनके उच्च पदस्थ ग्राहकों को सेवाएं मुहैया कराते हैं. हमारे कार रेंटल राजस्व का क़रीब 25 फीसदी हिस्सा यानी 40 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इसी वर्ग से आता है. मर्सिडीज बेंज का ब्रांड मूल्य बेजोड़ है और ऐसे में यह स्वाभाविक पसंद थी. सी क्लास के जो वाहन इस समय हमारे बेड़े में हैं, बेहद भरोसेमंद साबित हुए हैं. पीटर टी होनेग्ग और देवाशीष मित्रा ने कहा, भारत में आजकल लोगों की जीवनशैली अंतरराष्ट्रीय है और मोबिलिटी की इनकी प्राथमिकताओं से इनके स्टेटस का पता चलता है. उन्होंने कहा, हमारे पास एक पूरी टीम है, जो कॉरपोरेट ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित है.

सिमट्रॉनिक इंडिया का सौर ऊर्जा डेस्कटॉप

इस कंप्यूटर से एक तरफ़ पर्यावरण को लाभ होगा, वहीं दूसरी तरफ़ इससे ऊर्जा की बचत भी होगी. इस डेस्कटॉप की सबसे अच्छी बात है कि यह बिना धूप के भी काम कर सकता है.

बिजली की कमी के कारण कंप्यूटर का इस्तेमाल न कर पाने वाले लोगों के लिए सिमट्रॉनिक इंडिया एक अच्छी ख़बर लेकर आया है. सिमट्रॉनिक सेमी कंडक्टर्स ने दुनिया में पहली बार सौर ऊर्जा से चलने वाले कंप्यूटर डेस्कटॉप की रेंज लांच की है. कंपनी का कहना है कि इस कंप्यूटर से एक तरफ़ पर्यावरण को लाभ होगा, वहीं दूसरी तरफ़ इससे ऊर्जा की बचत भी होगी. इस डेस्कटॉप की सबसे अच्छी बात है कि यह बिना धूप के भी काम कर सकता है. कंपनी इस बात की गारंटी देती है कि यह सर्दी या बरसात के दिनों में कई दिनों तक धूप न निकलने के बावजूद काम करता रहेगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बीटल के नए मोबाइल फोन

बीटल जीडी- 310 द्वारा एसएमएस, काल ब्लैक लिस्ट, मोबाइल ट्रैकर और आपातकालीन एसएमएस सुविधा हेतु बीटल वर्ल्ड का प्रयोग किया जा सकता है. जीडी-218 में ड्यूल सिम सपोर्ट के साथ 1800 मैन मैराथन बैटरी है, जो 15 घंटे का टाकटाइम और 25 दिनों का स्टैंड बाई प्रदान करती है.

भारत में दूरसंचार और संबंधित उत्पादों की अग्रणी वितरक कंपनी बीटल टेलटेक ने मोबाइल फोन की एक सीरीज जारी की है, जिनका नाम है जीडी-310 और जीडी-218. ये आकर्षक एवं अनेक विशेषताओं से युक्त हैं. बीटल जीडी-310 का मूल्य 1799 और बीटल जीडी-218 का मूल्य 1499 रुपये रखा गया है. कंपनी के कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ विनोद सवनी ने बताया कि समझदार भारतीय उपभोक्ताओं के लिए बीटल जीडी-310 एवं जीडी-218 अत्यंत आकर्षक मूल्य पर विशिष्ट गुणों वाले मोबाइल फोन हैं. हम ग्राहकों के लिए आधुनिक मोबिलिटी उपकरण, जो उनकी आवश्यकताओं एवं स्टाइल के अनुरूप होने के साथ-साथ ग्रेट वैल्यू प्रस्तावित करें, उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध हैं. हमारी महत्वाकांक्षी विस्तार योजनाएं हैं और आने वाले दिनों में भारतीय मोबाइल फोन उपभोक्ता कुछ और उम्दा मोबाइल हैंडसेटों की अपेक्षा बीटल से कर सकते हैं. जीडी-310 में उच्च क्षमता वाली बैटरी और ड्यूल सिम सपोर्ट उपलब्ध है. इसमें एफएम रेडियो, आडियो-वीडियो रिकार्डिंग के लिए वीजीए कैमरा, वन टच टार्च और बेहतर साउंड क्वालिटी है. डाटा संग्रह करने संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए जीडी-310 में मेमोरी कार्ड हेतु दो स्लाट हैं, जिनमें एक 8 जीबी और दूसरा 2 जीबी का है. बीटल जीडी- 310 द्वारा एसएमएस, काल ब्लैक लिस्ट, मोबाइल ट्रैकर और आपातकालीन एसएमएस सुविधा हेतु बीटल वर्ल्ड का प्रयोग किया जा सकता है. जीडी-218 में ड्यूल सिम सपोर्ट के साथ 1800 मैन मैराथन बैटरी है, जो 15 घंटे का टाकटाइम और 25 दिनों का स्टैंड बाई प्रदान करती है. इसमें 8 जीबी तक बढ़ाई जा सकने योग्य मेमोरी क्षमता है. यह 1499 रुपये के अधिकतम खुदरा मूल्य पर उपलब्ध है.

उड़ने वाली कार

अब वे दिन लदने वाले हैं, जब ट्रैफिक जाम में फंसकर अपनी मंज़िल तक पहुंचने में घंटों लग जाते हैं. उड़ने वाली कारें बनाने वाली कंपनी टेराफुजिया इस प्रोजेक्ट पर ज़ोर-शोर से जुटी हुई है. कंपनी के मुताबिक़, अगले पांच सालों में यह कार सबके सामने होगी. अमेरिका में इस कार को सरकार की हरी झंडी मिल चुकी है. कंपनी ने इसकी क़ीमत फ़िलहाल 25 हज़ार अमेरिकी डॉलर तय की है. यह वास्तव में एक लाइट एयरक्राफ्ट है, जो सड़क पर भी दौड़ सकने में सक्षम है. सिर्फ 15 सेकेंड में इसके पंख बाहर निकल कर उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएंगे और इसे आप अपने गैरेज में भी रख सकेंगे. यह कार अधिकतम 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकेगी और एक बार में 800 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी. ख़ास बात यह है कि इसे चलाने या उड़ाने के लिए किसी तरह के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ़ 20 घंटे की ट्रेनिंग के बाद आप इस कार को आसानी से उड़ा सकते हैं.

यह कार अधिकतम 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकेगी और एक बार में 800 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी. ख़ास बात यह है कि इसे चलाने या उड़ाने के लिए किसी तरह के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

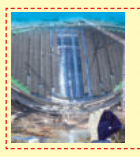

लंदन ओलंपिक से भारतीयों को भी आशाएं हैं. पिछले कुछ सालों में, ख़ासकर निशानेबाज़ी, कुश्ती और भारोत्तोलन में भारतीय खिलाड़ियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन ठीकठाक रहा है.

ओलंपिक 2012

एक साल पहले तैयार है लंदन

याद कीजिए राष्ट्रमंडल खेल 2010 और मेज़बान के रूप में भारत और उसकी तैयारियों को. तैयारी ऐसी कि खेल ख़त्म होने के बाद भी कई निर्माण कार्य चलते रहे. बजट सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता चला गया. अब ज़रा देखिए लंदन ओलंपिक 2012 की ओर. अभी एक साल का समय बाक़ी है, लेकिन खेल की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, स्टेडियम में रौनक़ है और टिकट बिक चुके हैं. आयोजकों के मुताबिक़, सारा काम तय समय सीमा और तय बजट में हुआ है. दरअसल, यह अंतर अपने आप में एक बड़ी कहानी कह जाता है. एक दिलचस्प अंतर यह कि एक ओर लंदन में ओलंपिक पार्क बनने की वजह से जहां पूर्वी लंदन का विकास हुआ, वहीं राष्ट्रमंडल खेल के नाम पर दिल्ली से ग़रीबों को भगाने का काम किया गया था.

ख़ैर, राष्ट्रमंडल खेल में घपले के आरोपी जेल में हैं. उन्हें उनकी करतूतों की क्या सज़ा मिलेगी, यह अदालत तय करेगी. अभी बात लंदन ओलंपिक की. लंदन के पूर्वी हिस्से में ओलंपिक पार्क बनाया गया है. इस वजह से शहर के इस पिछड़े क्षेत्र की दशा और दिशा ही बदल गई है. साथ ही लंदन के ज़्यादातर दर्शनीय और ऐतिहासिक स्थलों का इस्तेमाल खेलों के आयोजन स्थल के लिए किया जाएगा. ओलंपिक खेलों के समय प्रत्येक दिन 12 हज़ार पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भारी सुरक्षा व्यवस्था की वजह से आम नागरिकों या सैलानियों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी. अधिकारियों के मुताबिक़, सुरक्षा के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सुरक्षा व्यवस्था के कारण किसी को कोई दिक्क़त न हो. इसके साथ ही लंदन ओलंपिक की मशाल यात्रा के रास्ते के बारे में भी घोषणा कर दी गई है. महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार यह मशाल यात्रा सिर्फ़ मेज़बान देश ब्रिटेन में ही घुमाई जानी है. दरअसल, बीजिंग ओलंपिक 2008 की मशाल यात्रा के दौरान कई देशों में बाधा पहुंचाने की कोशिशों की वजह से आयोजकों ने मशाल को दूसरे देशों में घुमाने की जगह सिर्फ़ ब्रिटेन में ही घुमाने का फ़ैसला किया है. लंदन ओलंपिक की मशाल ब्रिटेन में 1300 किलोमीटर की यात्रा करेगी और आठ हज़ार लोग इसे लेकर दौड़ेंगे. यात्रा ओलंपिक खेलों के जन्मस्थल ग्रीस से मशाल लाए जाने के एक दिन बाद 19 मई, 2012 को शुरू होगी.

बहरहाल, लंदन ओलंपिक से भारतीयों को भी आशाएं हैं. पिछले कुछ सालों में, ख़ासकर निशानेबाज़ी, कुश्ती और भारोत्तोलन में भारतीय खिलाड़ियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन ठीकठाक रहा है. राष्ट्रमंडल खेलों में भी खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा. इस लिहाज़ से इस बार के ओलंपिक से उम्मीद लगाई जा सकती है. भारतीय निशानेबाज़ गगन नारंग 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं. नारंग को यह उपलब्धि म्यूनिख विश्व चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर मिली है. इसके अलावा शॉटपुट एथलीट ओम प्रकाश करहाना भी लंदन ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर गए हैं. ओम प्रकाश को यह उपलब्धि हंगरी के आईएएएफ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने की वजह से मिली है. ओम प्रकाश ने स्वर्ण पदक जीतने पर कहा कि ख़राब मौसम और बारिश के कारण थ्रो करने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद मैं 20.04 मीटर की दूरी तय कर स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहा. मुझे पूरा भरोसा है कि मैं विश्व चैंपियनशिप के बाद लंदन ओलंपिक खेलों में पदक जीतने में सफल रहूंगा. ज़ाहिर है, खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं और वे जी-जान से खेलने को तैयार भी हैं, लेकिन जिस देश में खेल में भी राजनीति होती हो, वहां बहुत ज़्यादा उम्मीद की गुंजाइश नहीं होती. साथ ही पिछले दिनों डोपिंग के चलते कई एथलीटों के दामन दाग़दार हुए हैं. ऐसे में एथलीटों के मनोबल पर विपरीत असर पड़ना स्वाभाविक है. बावजूद इसके बेहतर की आशा करने में क्या हर्ज है?

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राष्ट्रमंडल खेल में घपले के आरोपी जेल में हैं. उन्हें उनकी करतूतों की क्या सज़ा मिलेगी, यह अदालत तय करेगी. अभी बात लंदन ओलंपिक की. लंदन के पूर्वी हिस्से में ओलंपिक पार्क बनाया गया है. इस वजह से शहर के इस पिछड़े क्षेत्र की दशा और दिशा ही बदल गई है. साथ ही लंदन के ज़्यादातर दर्शनीय और ऐतिहासिक स्थलों का इस्तेमाल खेलों के आयोजन स्थल के लिए किया जाएगा.

सिर्फ़ ब्रिटेन में घूमेगी मशाल

लंदन ओलंपिक 2012 की मशाल यात्रा सिर्फ़ ब्रिटेन में ही संपन्न होनी है. बाक़ी देशों में इसे न ले जाने का फ़ैसला किया गया है. यह मशाल ब्रिटेन में 1300 किलोमीटर की यात्रा करेगी. क़रीब आठ हज़ार लोग इस मशाल को लेकर दौड़ेंगे. मशाल यात्रा 19 मई, 2012 को शुरू होगी. 70 दिनों की यह मशाल यात्रा ब्रिस्टल, कार्डिफ, लिवरपूल, बेलफास्ट, ग्लास्गो, ऐबरडीन, न्यूकासल, मैनचेस्टर, शेफील्ड, नॉटिंघम, ऑक्सफोर्ड, साउथैम्पटन और डोवर शहरों में जाएगी. प्रत्येक दिन क़रीब 12 घंटे की यात्रा होगी और अंत में 27 जुलाई, 2012 को यह लंदन के ओलंपिक स्टेडियम पहुंचेगी. इसी दिन ओलंपिक खेलों का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा. ओलंपिक मशाल की परंपरा प्राचीन ग्रीस से शुरू हुई थी, जहां संदेशवाहकों को मशाल लेकर प्रतियोगिता के समय की जानकारी देने के लिए भेजा जाता था. इस यात्रा का एक उद्देश्य बाक़ी देशों से खेलों के दौरान युद्ध स्थगित रखने की अपील करना भी होता था.

प्यार में स्मार्ट बने वार्न

क्या आपको मोटे-तगड़े और थुलथुल शेन वार्न याद हैं? अगर हां, तो अब यह बात पुरानी हो चुकी है. अब वार्न स्लिम-ट्रिम बन गए हैं और यह कमाल तब हुआ, जब वह एलिजाबेथ हर्ले के क़रीब आए. आस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वार्न ने अपने नए छरहरे लुक का श्रेय गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ हर्ले को दिया है और उन्हें थैंक्स भी कहा है. वार्न कहते हैं कि 22 पाउंड वज़न कम करने के बाद वह काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं. खेलने के दिनों में अपने फिगर को लेकर कभी चिंतित नहीं रहे वार्न हाल में न्यूयार्क में खींची गई तस्वीरों में दुबले, फिट और स्मार्ट दिखे. एक अख़बार की रिपोर्ट के अनुसार, चुस्त नीली टी शर्ट, डार्क रंग के चश्मे और नए आधुनिक हेयर स्टाइल में वार्न पहचान में नहीं आ रहे थे. पहले वह थुलथुल और साधारण सी शख्सियत के मालिक हुआ करते थे. वार्न ने कहा है कि जबसे मेरा हर्ले से अफेयर शुरू हुआ है, मैं काफ़ी आधुनिक हो गया हूं. हर्ले के कारण ही मैंने 22 पाउंड वज़न कम किया है. आजकल मैं स्टाइलिश हो गया हूं. वार्न ने अपनी भौहें दुरुस्त कराई हैं और वह मॉइश्चराइजर भी इस्तेमाल कर रहे हैं.

क्या धोनी बनेंगे पीपुल्स च्वॉइस

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एक बार फिर आईसीसी अवॉर्ड्स में पीपुल्स च्वॉइस अवॉर्ड को शामिल किया है. भारत से टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस बार अंतिम पांच खिलाड़ियों में शामिल हैं. लोगों को ऑनलाइन वोटिंग के ज़रिए इन पांच खिलाड़ियों में से अपनी पसंद के बारे में बताना है. धोनी के अलावा इनमें दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज़ हाशिम अमला, वेस्टइंडीज के क्रिस गेल, श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा और इंग्लैंड के जोनाथन ट्राट हैं. पहला पीपुल्स च्वॉइस अवॉर्ड सचिन तेंदुलकर को मिला था. इस बार धोनी दावेदार हैं. क्रिकेट प्रेमी लगातार दूसरी बार अपनी पसंद के क्रिकेटर को आईसीसी का एक अवॉर्ड दिला सकेंगे. ऑनलाइन वोटिंग 25 अगस्त तक होगी. विजेता के नाम की घोषणा 12 सितंबर को लंदन में की जाएगी.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 08 अगस्त–14 अगस्त 2011

असल ज़िंदगी में रिया सेन पहली बार रितुपर्णो घोष के साथ काम कर रही हैं. हालांकि उनकी बहन राइमा इस मामले में उनसे आगे हैं.

रिया की शरारतें

रिया सेन अपनी बहन राइमा के साथ बांग्ला फिल्म नौका डूबी में नज़र आईं. हिंदी में इसे कशमकश के नाम से रिलीज किया गया है. इस अनुभव से ख़ुश रिया ने बताया कि वह शरारत में एक्सपर्ट हैं, लेकिन काम को लेकर सीरियस हैं. फिल्म नौका डूबी में अपनी बहन के साथ काम करने का क्रेडिट वह हर उस इंसान को देती हैं, जिसने इस फिल्म को बनाने में मदद की. उनके प्रोड्यूसर ने इस प्रोजेक्ट के लिए हामी भरी और अभिभावकों ने कहा कि दोनों बहनों को साथ काम करना चाहिए. फिल्म में दोनों किसी भी सीन में एक साथ नहीं हैं, इसलिए जब दोनों बहनें मिलतीं तो अपने सीन डिस्कस नहीं करती थीं. असल ज़िंदगी में रिया सेन पहली बार रितुपर्णो घोष के साथ काम कर रही हैं. हालांकि उनकी बहन राइमा इस मामले में उनसे आगे हैं. रिया कहती हैं कि राइमा मुझसे सीनियर हैं. उन्होंने शूटिंग के पहले ही दिन तमाम क्रू मेंबर्स को बुलाकर मेरा ख्याल रखने के लिए कह दिया था. उस वक़्त मुझे लग रहा था कि मैं एक्ट्रेस न होकर सुचित्रा सेन की नातिन, मुनमुन सेन की बेटी और राइमा सेन की छोटी बहन हूं. वह इस क़दर कंफर्टेबल हो गईं कि शूटिंग के दौरान भी सेट पर शरारतें करने लगीं. रितुपर्णो ने रिया से कहा कि शरारत करने के बाद वह ख़ुद को इतना सीधा कैसे दिखा पाती हैं कि जैसे आपने कुछ किया ही न हो. रिया बताती हैं कि सेट पर मेरी शरारतें थमती ही नहीं थीं. रही बात ख़ुद को शरीफ़ दिखाने की, तो इसमें मेरी कोई ग़लती नहीं है. दरअसल, इसमें हमारी पूरी फैमिली माहिर है, लेकिन काम को लेकर हम सभी बहुत सीरियस हैं.

समीरा की परेशानी

बॉलीवुड में जहां लिंकअप और ब्रेकअप की ख़बरें इतनी ज़्यादा आती हैं कि स्टार उनका खंडन करते-करते थक जाते हैं, लेकिन समीरा रेड्डी की परेशानी दूसरी है. अब तक तो वह सिंगल हैं, मगर लगता है कि अब वह भी प्यार-व्यार के चक्कर में पड़ना चाहती हैं. जब किसी ने समीरा से सवाल किया कि वह आख़िर कब तक सिंगल रहने वाली हैं? समीरा ने तुरंत जवाब दिया कि वह तो किसी के साथ डेटिंग करने को तैयार हैं, मगर उन्हें उनके मनमुताबिक़ ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा है. दरअसल, समीरा इस मामले में बेहद चूज़ी हैं. वह ऐसा साथी चाहती हैं, जो ज़िंदगी भर उनका साथ निभाए. उनके अनुसार, किसी ऐसे व्यक्ति से रिश्ता जोड़ने से क्या फ़ायदा, जो एक दिन प्यार का इज़हार करे और दूसरे दिन लड़ाई-झगड़ा शुरू कर दे. समीरा शायद इस बात में विश्वास नहीं रखतीं कि लड़ाई प्यार की गहराई मापने का पैमाना है. थोड़ी-बहुत लड़ाई तो हर जोड़ी के बीच होती है. महत्वपूर्ण इतना है कि एक-दूसरे से प्यार करने वाले इसे किस तरह देखते हैं और किस तरह प्रदर्शित करते हैं. समीरा इन दिनों प्रभावित हैं सैफ़ और करीना की जोड़ी से. उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि वह सैफ़ और करीना की तरह रिलेशनशिप में रहना चाहती हैं. वैसे करीना और सैफ़ के ब्रेकअप की ख़बरें भी कम नहीं आईं और न उनके बीच लड़ाई-झगड़े की. फिर भी समीरा को उनकी जोड़ी क्यों पसंद है, यह राज़ की बात है. समीरा को बॉलीवुड में भले ही इन दिनों कम फिल्में मिल रही हों, मगर वह साउथ में कई फिल्मों को लेकर व्यस्त हैं.

फिल्म प्रीव्यू

आरक्षण

हमेशा मुद्दों पर आधारित फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर प्रकाश झा ने इस बार आरक्षण का मुद्दा उठाया है. यह आज की परिस्थितियों पर बनी फिल्म है और शिक्षा के व्यवसायीकरण के कारण नौजवानों और उनके परिवार को होने वाली परेशानियों व समस्याओं को सामने लाने का प्रयास है. झा के मुताबिक़, इस फिल्म का उद्देश्य दलित विरोध नहीं, बल्कि शिक्षा के व्यवसायीकरण और कैपिटेशन फीस पर रोशनी डालते हुए यह बताने का प्रयास किया गया है कि क्या समाज के कमज़ोर वर्ग का बच्चा ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त कर सकता है. काफ़ी विरोध के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) ने प्रकाश झा की इस विवादास्पद फिल्म को रिलीज के लिए हरी झंडी दे दी. स्क्रीनिंग के बाद इसे यूनिवर्सल सर्टिफिकेट दिया गया. फिल्म की कहानी प्राध्यापक प्रभाकर आनंद यानी अमिताभ बच्चन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कॉलेज में गणित विषय पढ़ाते हैं और अपने कॉलेज को स्टेट का सबसे बेहतर कॉलेज बनाना चाहते हैं. दीपक कुमार यानी सैफ अली ख़ान अपने आनंद सर के लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि वह उनकी बेटी पूर्वी यानी दीपिका पादुकोण से प्यार करता है. यह बॉलीवुड की ऐसी पहली फिल्म है, जिसमें आरक्षण का विरोध करने वालों को आड़े हाथों लिया गया है. इसके संगीत निर्देशक हैं प्रसून जोशी. फिल्म आगामी 12 अगस्त को रिलीज हो रही है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

लाजवाब तब्बू

यह तो सौ फ़ीसदी सत्य है कि मुश्किल की घड़ी में दोस्त ही होते हैं, जो अपने दोस्तों का ग़म हल्का करने में मदद करते हैं. ऐसी ही हमदर्द दोस्त हैं तब्बू. वैसे बॉलीवुड के चमकदार गलियारों में दोस्ती बनती-बिगड़ती रहती है, लेकिन तब्बू ने लाख मनमुटाव के बाद भी अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा और पहुंच गईं, उसके घर दु:ख पर मरहम लगाने. दरअसल तब्बू के यह ख़ास दोस्त हैं फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर. पिछले दिनों ऐश्वर्या राय की प्रेग्नेंसी ने मधुर को परेशान कर रखा था. ऐसा स्वाभाविक था, क्योंकि फिल्म बीच में अटक जाने से उनका पैसा और वक़्त दोनों बर्बाद हुआ. मधुर बेहद अपसेट थे, तभी तब्बू उनसे मिलने उनके घर पहुंच गईं. उन्होंने मधुर के घर जाते हुए वक़्त की परवाह नहीं की और रात पौने आठ बजे वह कक्कड़ एन्क्लेव पहुंच गईं. ऐसे में दूसरों को तो हैरानी हुई, मगर मधुर को ज़रूर अच्छा लगा. अब ऐसे दोस्त होते ही कितने हैं, जो आपके दु:ख में आपके पास चले आएं. तब्बू और मधुर की यह दोस्ती तब की है, जब दोनों ने फिल्म चांदनी बार में साथ काम किया था. तब दोनों के रोमांस की ख़बरें भी मीडिया में ख़ूब आई थीं. हालांकि भंडारकर तब्बू को लेकर फिल्म चांदनी बार का सीक्वल बनाने की भी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अब तक ऐसी कोई ख़बर आई नहीं है. वैसे मधुर के प्रति उमड़ते प्रेम को देखकर यही लगता है कि तब्बू के दिल में उन्हें लेकर अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है.

चार्मी की शानदार एंट्री

बॉलीवुड हमेशा से साउथ की अभिनेत्रियों को अवसर देता रहा है. हाल में आई फिल्म बुड्ढा होगा तेरा बाप से साउथ की अभिनेत्री चार्मी कौर ने बॉलीवुड में क़दम रखा. इस फिल्म से एक बढ़िया शुरुआत करने वाली चार्मी फिल्म में बिग बी के साथ काम करके बेहद ख़ुश हैं. फिल्म में उनके रोल को नोटिस किया गया है. यह रोल एक बिंदास लड़की का था, जो बिग बी की गर्लफ्रेंड रवीना की बेटी है और वह बिग बी से काफ़ी फ्रेंडली है. फिल्म में दोनों आपस में बिंदास तरीक़े से बातचीत करते हैं. इसी वजह से उनके काम की तारीफ़ हो रही है. दरअसल फिल्म के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ साउथ सिनेमा की एक बड़ी पर्सनैलिटी हैं. उन्होंने चार्मी को बिग बी के साथ काम करने का ऑफर दिया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि उन्होंने उन्हें लीड रोल में साइन किया. चार्मी कहती हैं कि वह काफ़ी कॉन्फिडेंट थीं और बिग बी बहुत अच्छे इंसान हैं. उन्होंने शूटिंग के पहले दिन ख़ुद ही उनके पास आकर कहा कि दोनों को रीयल शूट से पहले थोड़ी रिहर्सल करनी चाहिए. वैसे भी फिल्म में उनका रोल ऐसा है कि उनका बिग बी से खुलकर बात करना ज़रूरी था. साउथ और बॉलीवुड की फिल्मों में मुख्य फ़र्क़ क्या है? इस सवाल पर चार्मी कहती हैं कि साउथ में उन्होंने 10 साल काम किया और क़रीब 50 फिल्में कीं, लेकिन अपनी पहली हिंदी फिल्म शूट करते वक़्त उन्हें महसूस ही नहीं हुआ कि वह बॉलीवुड में काम कर रही हैं. डायरेक्टर पुरी ने हैदराबाद से काफ़ी आर्टिस्ट बुलाए थे, इसलिए उन्हें लग रहा था कि बिग बी उनकी टीम के साथ किसी तेलुगु फिल्म में काम कर रहे हैं. बॉलीवुड में काम कर रहीं साउथ की अन्य अभिनेत्रियों की तरह अब वह भी यहीं सेटल होना चाहती हैं. ख्याल तो नेक हैं, लेकिन चार्मी ज़्यादा प्लानिंग नहीं करतीं. पुरी ने उन्हें बॉलीवुड में एंट्री का मौक़ा दिया और चार्मी ने इसमें अपना बेस्ट दिया. यही वजह थी कि फिल्म को अच्छा रेस्पॉन्स मिला. एक-दो और निर्माताओं से बात चल रही है. उन्होंने तय कर लिया है कि अब वह बॉलीवुड को प्राथमिकता देंगी. चार्मी कहती हैं कि उन्होंने साउथ सिनेमा में सभी टॉप स्टारों के साथ काम किया है. बॉलीवुड में उन्हें सभी स्टार पसंद हैं और वह सबके साथ काम करना पसंद करेंगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 08 अगस्त-14 अगस्त 2011

www.chauthiduniya.com

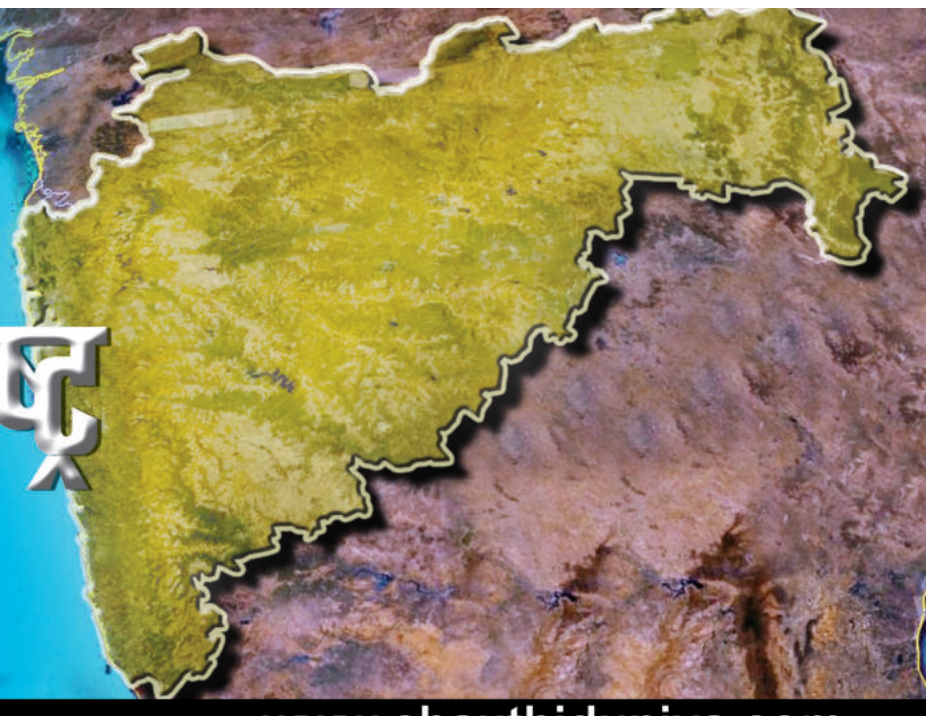

प्यासा रह जाएगा नागपुर

पेंच प्रकल्प की जिस राइट नहर से नागपुर मनपा को जलापूर्ति की जाती है, उस नहर की लंबाई 48.50 कि.मी. है और इस नहर में अधिकतम 28.40 घन मीटर प्रति सेकेंड की दर से पानी छोड़ा जाता है. गत दिनों कई जगह कई बार नहर की दीवारों में दरारें आईं. इसके बाद इस नहर से पानी छोड़ना बंद किया गया था. हालत यह है कि पिछले 20 वर्षों से नहर की सफ़ाई तक नहीं की गई है. नहर के तल में मैला जमा हुआ है. नहर को स्थाई रूप से दुरुस्त करने का समय भी मनपा नहीं देती है.

प्रवीण महाजन

नागपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति करने वाले पेंच प्रकल्प से आने वाली नहर की हालत इतनी गंभीर है कि अब यह कभी भी टूट सकती है और अगर ऐसा हो गया तो पूरे नागपुर शहर में पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा. जल संपदा विभाग द्वारा लगातार शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के बाद इसके विकल्प के रूप में महानगर पालिका ने पाइप लाइन डालने का काम शुरू किया है, लेकिन इस काम में भी क़रीब डेढ़ से दो साल लगने का अनुमान है. इसमें भी विशेषज्ञ बताते हैं कि यदि यह पाइप लाइन कभी फूट गई तो क्या होगा. आख़िर पानी की तो त्राहि-त्राहि मचने ही वाली है. बेहतर होता यदि एक की जगह कम मोटाई की दो पाइप लाइनें बिछाई जातीं. इससे जलापूर्ति अधिक सुरक्षित हो जाती है.

ज्ञात रहे कि पेंच प्रकल्प के नवेगांव खैरी से नागपुर महानगर पालिका के लिए 190 दस लाख घन मीटर (दलघमी) पानी आरक्षित है. प्रकल्प के नियोजन के अनुसार पहले यह आरक्षण सिर्फ़ 112 दलघमी ही था. 1998-99 में नागपुर मनपा के अंतर्गत पानी की खपत बढ़ने के बाद 78 दलघमी पानी का अतिरिक्त आरक्षण दे दिया गया. दिसंबर 2008 में शासन ने 78 दलघमी के अतिरिक्त आरक्षण को इस शर्त पर स्थाई करने की मान्यता दी थी कि नागपुर महानगर पालिका द्वारा पुनर्स्थापना ख़र्च के रूप में 84.45 करोड़ रुपए जमा कर दिया जाएगा. मनपा ने हालांकि यह राशि नहीं भरी, लेकिन उसके लिए शासन ने पानी का यह आरक्षण जारी रखा है. नागपुर शहर को पेंच प्रकल्प और कन्हान नदी पर बने जल शुद्धिकरण केंद्र से पानी की आपूर्ति की जाती है. इसमें पेंच प्रकल्प के पानी का बड़ा हिस्सा है.

पेंच प्रकल्प की जिस राइट नहर से नागपुर मनपा को जलापूर्ति की जाती है, उस नहर की लंबाई 48.50 कि.मी. है और इस नहर में अधिकतम 28.40 घन मीटर प्रति सेकेंड की दर से पानी छोड़ा जाता है. गत दिनों कई जगह कई बार नहर की दीवारों में दरारें आईं. इसके बाद इस नहर से पानी छोड़ना बंद किया गया था. हालत यह है कि पिछले 20 वर्षों से नहर की सफ़ाई तक नहीं की गई है. नहर के तल में मैला जमा हुआ है. नहर को स्थाई रूप से दुरुस्त करने का समय भी मनपा नहीं देती है. मनपा के पास नागपुर शहर को पानी आपूर्ति करने के लिए पानी स्टोरेज की सुविधा नहीं है. नागपुर शहर को महादुला पंप हाउस और कन्हान पंप हाउस से पानी फिल्टर होने के बाद पानी आपूर्ति की जाती है. यदि पेंच प्रकल्प से पानी देना बंद कर दिया गया तो गोरेवाड़ा तालाब में सिर्फ़ सात दिन के लिए पानी स्टोर करने की क्षमता है. जानकारों का कहना है कि सही में ऐसी नौबत आई तो सात दिन भी शहर को पानी की आपूर्ति करना असंभव हो जाएगा. शासन के नियम के अनुसार किसी शहर के लिए पानी आपूर्ति करने वाली एजेंसी के पास कम से कम दो माह तक आपूर्ति का पानी स्टोरेज करने की क्षमता होना ज़रूरी है. मनपा ने सरकार से जो अनुबंध किया है उसमें भी इस नियम का उल्लेख है पर अब तक मनपा प्रशासन ने पानी स्टोरेज करने की कोई व्यवस्था नहीं की है. नागपुर मनपा के साथ ही साथ खापरखेड़ा व कोराडी ताप विद्युत गृह को भी पानी दिया जाता है. यदि इस नहर को एक बार ख़ाली कर दिया गया तो फिर इसे एक छोर से दूसरे छोर तक भरने में लगभग 48 घंटे लग जाते हैं. ऐसी स्थिति में नागपुर के लोगों को बिना पानी के रहना होगा. .

शहरीकरण में आई तेज़ी से नागपुर शहर की आबादी बढ़ती जा रही है. इसके साथ ही लोगों की जीवनशैली में आए परिवर्तन से रहन-सहन अधिक सुविधाजनक हो गया है जिससे पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है, लेकिन अतिरिक्त पानी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है. कन्हान नदी पर ही मध्य प्रदेश में बनने वाला चौराई बांध पूरा होने के बाद और जल समझौते के अनुसार जब मध्यप्रदेश आवंटित पानी की पूरी मात्रा लेना शुरू कर देगा तो पानी की कमी होना लाज़िमी है. कन्हान नदी पर जामघाट कन्हान जल विद्युत प्रकल्प की रिपोर्ट मध्य प्रदेश शासन को भेजी गई है. यह प्रकल्प मध्य प्रदेश की पांढुरना तहसील में प्रस्तावित है. यह परियोजना पूरी हुई तो इससे महाराष्ट्र को 15 अक्टूबर से 30 जून की अवधि के बीच 10 अरब घन फुट पानी मिलेगा. कन्हान नदी पर ही प्रस्तावित कोची बैरेज को 2006 में प्रशासकीय मान्यता मिल गई थी. उस समय यह प्रकल्प 261 करोड़ रुपये का था. इस प्रकल्प से मात्र चार गांव प्रभावित होंगे जिनमें तीन महाराष्ट्र के और एक मध्यप्रदेश के अंतर्गत है. इसका पूरा ख़र्च महाराष्ट्र को करना है. इस परियोजना के वन प्रस्ताव को भी तत्वतः मान्यता मिली हुई है. पर्यावरण मान्यता का काम शुरू है. लेकिन इसका काम 5 साल बीत जाने के बाद भी अब तक शुरू नहीं हो सका है. इस योजना से 76 दलघमी पानी उपलब्ध हो सकेगा. गोसीखुर्द परियोजना की तरह ही इस परियोजना को भी लटकाया जा रहा है और इसकी लागत भी बढ़ती जा रही है. नागपुर महानगर पालिका के लिए एक अन्य प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की ओर से आया था. रहारी बांध का प्रस्ताव था. इस परियोजना को यदि क्रियान्वित कर दिया जाता तो मनपा को 128 दलघमी पानी उपलब्ध हो जाता. प्रकल्प की लागत अनुमानतः 362 करोड़ रुपये आंकी गई थी. मगर मनपा ने इस प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की. मनपा का इस ओर तर्क अलग है. मनपा का कहना है कि ख़र्च के हिसाब से यह परियोजना वायबल नहीं है. इस पूरी परियोजना में क़रीब 700 करोड़ रुपये का ख़र्च आएगा जो मनपा के लिए संभव नहीं है. इसे भी कन्हान नदी पर बनाया जाना है. क़रीब 135 मीटर की ऊंचाई तक पानी पंप करना पड़ेगा. ऊर्जा बचत, बिजली की खपत की दृष्टि से भी यह परियोजना ठीक नहीं है. 135 मीटर तक पंपिंग करने में बिजली की अच्छी ख़ासी खपत हो जाएगी.

feedback@chauthiduniya.com

बिछ रही है पाइप लाइन

पेंच प्रकल्प की जिस राइट नहर से मनपा नागपुर को पानी की आपूर्ति की जाती है, पेंच प्रकल्प से पानी लाने के लिए अब मनपा ने पाइप लाइन बिछाने का काम शुरू किया है. मनपा के कार्यकारी अभियंता उराडे ने बताया कि केंद्र की योजना जेएनएनयूआरएम के तहत यह काम किया जा रहा है. पाइप लाइन बिछाने में लगभग 210 करोड़ रुपये का ख़र्च अनुमानित है. काम पूरा होने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, क्योंकि बीच में इंटेकवेल बनाने होंगे. फिर 3 पुल भी पार करने होंगे. इसमें कन्हान, कोलार नदी के बड़े पुल होंगे और आमला नाला पर भी पुल का निर्माण करना पड़ेगा. इन सबमें समय लगेगा. अब तक 90 करोड़ रुपये ख़र्च किए जा चुके हैं. 27 कि.मी. तक पाइप लाइन बिछानी है, जिसमें से 16 कि.मी. तक का काम हो चुका है. योजना के तहत ख़र्च में केंद्र की हिस्सेदारी 50 फ़ीसदी, राज्य सरकार की 30 फ़ीसदी और मनपा की 20 फ़ीसदी रहने वाली है. इस कार्य की निविदा में 27 माह की कार्यावधि दी गई है. इस समय में कार्य पूरा होने की संभावना नहीं है इसलिए अवधि बढ़ानी पड़ेगी. लेकिन लागत में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी. जानकारों का कहना है कि मनपा इंटेकवेल 303 लेवल पर न लेते हुए यदि 310 लेवल पर लेते तो इंटेकवेल और पंप हाउस के बीच की दूरी भी कम होती थी. ईएसआर या बीपीटी के लिए जगह भी आसानी से मिल सकती थी. इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि इस पूरे काम की लागत तीन से चार करोड़ रुपये कम होती. यदि यह पाइप लाइन कोची बैरेज से सीधे महादुला पंप हाउस तक मनपा बिछाती तो आज जो 27 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाने का काम करना पड़ रहा है, वह 8 किलोमीटर ही करना पड़ता था. यहां पर पंप हाउस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी. इसमें मनपा के पैसे और समय की बचत भी होती थी. पेंच पाइप लाइन काम के लिए जिन लोगों की ज़मीन पर बिना परवानगी के पाइप लाइन का काम शुरू किया था उनके आपत्ति करने पर काम रोकना पड़ा. इसके बाद ज़मीन अधिग्रहण का सिलसिला चालू हुआ. मगर यह तथ्य भी सामने आए हैं कि जिन लोगों को ज़मीन के मुआवज़े की रक़म के चेक दिए गए थे, वे चेक के भुगतान कुछ कारणों से रुक गए थे. सभी प्रकल्पों की तरह इस प्रकल्प में भी जगह अधिग्रहण व उसके मुआवज़े को लेकर कई समस्याएं दिखाई दीं.

पानी खोजने के लिए 27 लाख - अजीत पवार के जल संपदा मंत्री रहते हुए रहारी बैरेज के लिए काफ़ी बैठकें हुईं. इस बैरेज को बनाकर नागपुर शहर को पानी आपूर्ति की जाए, इसके लिए उपर से दबाव था. लेकिन इस बैरेज को बनाना मनपा की आर्थिक स्थिति केमद्देनजर संभव नहीं था. जब कोई हल नहीं निकल पाया तो अब वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कन्हान नदी पर ही कामठी छावनी के पास से कन्हान वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को जोड़ने के उपाय खोजे जा रहे हैं. इसके लिए पुणे की एक कंपनी को टंडर भी दिया गया है जो सर्वेक्षण कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. मनपा ने इसके लिए 27 लाख रुपये भर दिए हैं. इसकी रिपोर्ट आने के बाद कोई मार्ग निकलने की उम्मीद की जा रही है.

विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ ही पूरे राज्य में कृषि कमोबेश बारिश पर ही आश्रित है. राज्य में सिर्फ़ 18 फ़ीसदी कृषि भूमि में सिंचाई की व्यवस्था अब तक की जा सकी है.

नागरिकों की भावनाओं व समस्याओं को सरकार के सामने लाकर उनका समाधान करना होगा. आज कश्मीर के लोगों को रोज़गार, मूलभूत सुविधाओं और विकास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है.

बारिश की मनमर्ज़ी सरकार बेख़बर

सोनू सावजी

देश की तरह ही राज्य की अर्थ व्यवस्था भी कृषि पर ही आश्रित है और कृषि का एक बड़ा हिस्सा बारिश के भरोसे है. मराठवाड़ा, विदर्भ में तो कृषि लगभग पूरी तरह बारिश की मेहरबानी पर ही टिकी रहती है. औद्योगिक, शैक्षणिक क्षेत्र में देश में आगे होने का दावा करने वाले इस राज्य में कृषि को लेकर कभी गंभीरता से विचार नहीं किया जाता है. हर साल की तरह इस साल भी मानसून ने अपने रंग-ढंग अच्छे से दिखा दिए. जुलाई के दूसरे पखवाड़े में ज़रूर अच्छी बारिश हो गई नहीं तो इस साल सूखे का संकट भी मंडराने लगा था. जुलाई तक सबसे कम बारिश चंद्रपुर में (सामान्य का महज़ 57.7 फ़ीसदी) में हुई. बाक़ी सभी ज़िलों में बारिश का आंकड़ा तो लगभग पूरा हो रहा है, लेकिन जिस समय होना चाहिए, उस समय नहीं हुई. साल-दर-साल लगातार मौसम के बदलते चक्र का सामना किसानों को करना पड़ रहा है. इसका नतीजा यह हो रहा है कि फ़सलें चौपट हो रही हैं और किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं. बारिश का मिज़ाज तो इस बार ऐसा था कि जुलाई के पहले महीने तक राज्य में मात्र 20 प्रतिशत रोपाई, बोआई का काम हो पाया था. 15 जुलाई के बाद ही बारिश ने अपने तेवर दिखाए और फिर शुरू हुआ खेती किसानी का काम ज़ोरों पर.

लगातार मौसमविद् इस ओर सरकारों का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं कि विशेषज्ञों की टीम बनाकर मौसम में हो रहे बदलाव पर शोध कर कोई निष्कर्ष सामने लाया जाए जिससे बार-बार प्रकृति के कारण होने वाले नुक़सान को कुछ कम किया जा सके, लेकिन इस ओर अब तक कोई कारगर क़दम नहीं उठाए गए हैं. हां, इतना ज़रूर किया जाता है कि जो पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध है भी, उसे भी अब ताप बिजली घरों को दिया जा रहा है. इस साल मानसून एकदम समय पर आया था. मुंबई में तो इसने समय के पहले ही उपस्थिति दर्ज करा दी थी. बाद में मानसून की सीमा आगे तो बढ़ती गई, पर मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों और पश्चिमी महाराष्ट्र को छोड़ कर शेष महाराष्ट्र में बारिश न के बराबर हुई. इस कारण मानसून के पहले आने के कारण जिन लोगों ने जून में बोआई कर दी थी, उनके सामने दोबारा बोआई की समस्या पैदा हो गई. बीजों की नई तकनीक विकसित करना तो दूर सरकार इस बात की व्यापक जानकारी भी किसानों को नहीं देती कि इस समय फ़सलों के लिए किस प्रकार की सावधानी बरतें. या बोआई करें या फिर न करें. राज्य के कृषि विभाग को इस असफलता की ज़िम्मेदारी लेनी ही होगी. मौसम विभाग के पास तो अब अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध है. नागपुर में डाप्लर राडार लग चुका है. इस विभाग से सतत संपर्क साध कर बारिश के पूर्वानुमान को किसानों तक पहुंचाने की ठोस योजना नहीं की जाती, बल्कि जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो लीपापोती शुरू कर दी जाती है.

विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ ही पूरे राज्य में कृषि कमोबेश बारिश पर ही आश्रित है. राज्य में अब तक सिर्फ़ 18 फ़ीसदी कृषि भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की जा सकी है. देश भर के आंकड़ों पर ग़ौर करें तो महाराष्ट्र की हालत उससे भी ख़राब है. देश में औसत 40 फ़ीसदी ज़मीन पर सिंचाई की व्यवस्था है, जबकि राज्य में यह आंकड़ा मात्र 18 प्रतिशत है. राज्य में लगभग 40 लाख हेक्टर क्षेत्रफल भूमि की सिंचाई उपलब्ध है. राज्य में कुएं या बोरवेल से 22 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है. राज्य के कुल क्षेत्रफल में कुएं के पानी से 56 फ़ीसदी, तालाब से 15 फ़ीसदी, जबकि 21 फ़ीसदी क्षेत्रफल में नहर द्वारा सिंचाई की जाती है. राज्य में सिंचाई के पांच महामंडल बनाए गए हैं. कृष्णा खोरे, विदर्भ, तापी, कोकण और गोदावरी मराठवाड़ा सिंचाई महामंडल होने के बावजूद किसानों की ज़मीनें बारिश के अभाव में सूखी रह जाती हैं. बारिश के जल के संरक्षण की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे भूजल स्तर अच्छा रहे और समय पड़ने पर किसान बोरवेल या कुएं से सिंचाई की व्यवस्था कर सकें. और तो और कृषि विभाग का भी किसानों के साथ कोई संवाद होता कभी नहीं दिखता है, न ही यह विभाग कभी कोई मार्गदर्शन जारी करता है. हां, कुछ ख़ानापूर्ति ज़रूर कर दी जाती है.

बारिश के बदलते क्रम का बारीकी से अध्ययन कर फ़सलों की नई प्रजातियों की खोज भी नहीं की जाती है. जो कुछ इस ओर हुआ है, वह सब फाइलों में बंद है. राज्य में कृषि से संबंधित उद्योगों या कृषि को ही उद्योग के रूप में विकसित करने की व्यापक संभावनाएं हैं. लेकिन जब ताप बिजली घरों को अनुमति देने की बात आती है, तब जैसी तत्परता दिखाई जाती है, वह कृषि के मामले में कभी नहीं दिखती. राज्य में कई गांव ऐसे भी हैं जहां कम बारिश के बावजूद गांव वालों ने सही मार्गदर्शन के कारण अपने गांव की धरती को सुजलाम सुफलाम बना लिया. यह देशी तकनीक पूरे राज्य में लागू क्यों नहीं की जा सकती.

feedback@chauthiduniya.com

विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ ही पूरे राज्य में कृषि कमोबेश बारिश पर ही आश्रित है. राज्य में अब तक सिर्फ़ 18 फ़ीसदी कृषि भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की जा सकी है. देश भर के आंकड़ों पर ग़ौर करें तो महाराष्ट्र की हालत उससे भी ख़राब है. देश में औसत 40 फ़ीसदी ज़मीन पर सिंचाई की व्यवस्था है, जबकि राज्य में यह आंकड़ा मात्र 18 प्रतिशत है. राज्य में लगभग 40 लाख हेक्टर क्षेत्रफल भूमि की सिंचाई उपलब्ध है.

कश्मीर दे रहा है एक नया संदेश

कश्मीर की वादियों में बदलाव आ रहा है. वहां के निवासी आतंकवाद की आग में और नहीं जलना चाहते हैं और न ही अपने भाइयों को जलता देखना चाहते हैं. हिंदू-मुस्लिम मिलकर कश्मीर की वादियों को ख़ुशहाल देखना चाहते हैं. इसीलिए तो पिछले दिनों हुए पंचायत चुनावों में मुस्लिम बहुल इलाक़े से एक हिंदू महिला चुनाव जीत सकी. इससे यह साफ़ हो जाता है कि कश्मीर के लोग सांप्रदायिकता के विष को त्याग कर सद्भावना का अमृत पान करने में विश्वास करने लगे हैं और वे तहेदिल से चाहते हैं कि जो उनके हिंदू-सिक्ख भाई कश्मीर छोड़कर चले गए थे, वे अपने घर वापस आ जाएं.

कश्मीर वासियों की स्थिति बेहद ही दयनीय है. दिनभर काम करते हैं तब जाकर शाम को पेट भरता है. यदि एक भी दिन काम न किया तो घर में चूल्हा नहीं जलता है. भूखे ही रहना पड़ता है. मुझे अपने ऐसे कश्मीरी भाइयों के लिए कुछ काम करना है. उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना है. उनके दुःख-सुख को बांटना है. उन्होंने मुझे बड़ी अपेक्षाओं के साथ चुना है. यह उद्‌गार व्यक्त करते समय कश्मीर के बारामूला ज़िले की मुस्लिम बहुल क्षेत्र से निर्वाचित पंचायत सदस्य आशा भट (पंडित) की आंखों में आंसू बहने लगते हैं. मानो वे शब्दों से दिल की भावना और अश्रुओं से कश्मीर वासियों की व्यथा व्यक्त कर रही हों. आज वह पंचायत में जिस मुस्लिम बहुल क्षेत्र का नेतृत्व कर रही हैं उससे वह कश्मीर सहित देश के लिए भी हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल बन गई हैं.

पिछले दिनों नागपुर आगमन पर आशा पंडित का सत्कार किया गया. इस अवसर पर उन्होंने कश्मीर के लोगों की व्यथा बताई और वहां के बदलते हालात से अवगत कराया. उन्होंने बताया कि दो दशक पहले कश्मीर घाटी से पलायन कर गए कश्मीरी पंडित अब अपनी मातृभूमि, घर वापस आना चाहते हैं. घाटी के मुस्लिम भाई भी उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं. परंतु विस्थापित होने के बाद मिलने वाली सुविधाओं को छोड़ कर वापसी करने पर पंडितों का मन विचलित हो जाता है. उन्हें भय लगता है कि यदि कश्मीर घाटी में लौटने पर उनका पुनर्वास नहीं हो सका तो विस्थापित होने पर मिल रही सुविधाएं भी जाएंगी और वहां रहना भी मुश्किल हो जाएगा. इस दुविधा के कारण कश्मीरी पंडित घाटी में वापसी करने से हिचकते हैं. सरकार कहती है कि माइग्रेशन कार्ड लाओ तो ही सब सुविधाएं मिलेंगी. ऐसे में कश्मीरी पंडितों का सवाल है कि क्या सरकार हमारे लिए नहीं है? इन सवालों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा तभी कश्मीरी पंडितों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है.

अपने निर्वाचन पर उनका कहना है कि पंचायत चुनाव जीतने के बाद मेरे नए जीवन की शुरुआत हुई. जब मैं 14 वर्ष की थी तब मेरा विवाह हुआ. मायके से दूर रहकर भी ससुराल में कोई कमी नहीं रही, कश्मीर में भरपूर प्यार मिला. कश्मीरी लोगों की स्थिति अति विकट है. अब चुनाव जीतने के बाद जो कुछ करना है उन्हीं के लिए करना है. स्थानीय नागरिकों की भावनाओं व समस्याओं को सरकार के सामने लाकर उनका समाधान करना होगा. आज कश्मीर के लोगों को रोज़गार, मूलभूत सुविधाओं और विकास की सबसे अधिक ज़रूरत है.

यह तो सर्वविदित है कि जब कश्मीर जल रहा था तब सबसे अधिक अपमान व मार कश्मीरी पंडितों को पड़ी. इससे मजबूरन उन्हें अपना घरबार छोड़कर कश्मीर से पलायन करना पड़ा. मगर अब हालात बदल रहे हैं. वहां के नागरिक हिंदू-मुस्लिमों में व्याप्त वैमनस्यता की भावना को त्याग कर भाईचारे के साथ मिलकर भारत की सांझा चूल्हे की संस्कृति को पुनः जीवंत कर दिया है. इसी के चलते वे जाति, संप्रदाय की भावना से परे होकर एक योग्य महिला को अपना जनप्रतिनिधि बनाते हैं. यह देश के लिए मिसाल है, क्योंकि आज जब चारों ओर जाति-संप्रदाय, अगड़ा-पिछड़ा, अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक की राजनीति का बोलबाला है. इस स्थिति में कश्मीर की अवाम भारत को एक नया संदेश दे रही है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

दो दशक पहले कश्मीर घाटी से पलायन कर गए कश्मीरी पंडित अब अपनी मातृभूमि, घर वापस आना चाहते हैं. घाटी के मुस्लिम भाई भी उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं. मगर कश्मीरी पंडितों का मन विचलित हो जाता है. उन्हें भय लगता है कि यदि कश्मीर घाटी में लौटने पर उनका पुनर्वास नहीं हो सका तो विस्थापित होने पर मिल रही सुविधाएं भी जाएंगी और वहां रहना भी मुश्किल हो जाएगा.

महाराष्ट्र हलचल

महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र से पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण द्वारा आयोजित सहयाद्रि अतिथिगृह में चाय पार्टी का लुफ्त उठाते कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मानिकराव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अनिल देशमुख, नारायण राणे, आर. आर. पाटिल व छगन भुजबल.

मुंबई भाजपा कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए विधान परिषद में विपक्षी दल के नेता पांडुरंग फुंडकर, प्रवक्ता माधव भंडारी व पूर्व विधायक अतुल शाह.

राज्य के निर्वाचन आयुक्त नीला सत्यनारायण द्वारा लिखित मराठी कादंबरी रात्र वणव्याची का विमोचन करते हुए अभिनेता विक्रम गोखले, मुंबई वि. वि. की पूर्व कुलगुरु डॉ. स्नेहलता देशमुख व अन्य.

नागपुर ज़िला नियोजन समिति की बैठक में विचार-विमर्श करते अविनाश पांडे, जि. प. अध्यक्ष सुरेश भोयर, राज्य के मंत्री राजेंद्र मुलक, अनिल देशमुख, पालक मंत्री शिवाजीराव मोघे विभागीय आयुक्त रेड्डी, नासुप्रा अध्यक्ष दराडे व अन्य.

नाग विदर्भ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जगदीश बंग का स्वागत करते निवर्तमान अध्यक्ष नीलेश सूचक व अन्य.

नागपुर में बी. एड. व डी. एड. के आदिवासी विद्यार्थी छात्रवृत्ति बंद करने के विरोध में प्रदर्शन करते हुए.

महंगाई और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ भैंस को सरकार का प्रतीक मानकर उसके सामने प्रदर्शन करते नागपुर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता.

चौथी दुनिया
महाराष्ट्र

सदस्यता फार्म (वार्षिक)

सदस्यता शुल्क- २५० /- रुपये
मैं "चौथी दुनिया" साप्ताहिक समाचार पत्र का सदस्य बनना चाहता/चाहती हूँ।
मेरा नाम श्री./ श्रीमती ....
मेरा पता ....
जिला..................राज्य ....पिन कोड..................
फोन (आ)..................(का)..................मोबाईल..................
ई -मेल..................
मैं रु. वार्षिक सदस्यता के लिए चेक क्रमांक..................
दिनांक ....बैंक..................शाखा.................. द्वारा भेज रहा/ रही हूँ

नोट- यह सदस्यता शुल्क भारत में ही मान्य है तथा यह योजना सीमित अवधि के लिए है। समाचार पत्र केवल साधारण डाक द्वारा भेजा जाएगा।

सदस्यता शुल्क केवल चेक द्वारा आशीर्वाद पब्लिकेशन प्रा. लि. नागपुर के पक्ष में सदस्यता फार्म के साथ निम्नलिखित पते पर प्रषित करे या फिर हमारे प्रतिनिधि को फार्म कलेक्ट करने के लिए फोन पर सूचित करे.

कार्यालय
"चौथी दुनिया"- महाराष्ट्र,
आशीर्वाद पब्लिकेशन प्रा.लि.,
२७, पिसे कॉम्प्लेक्स, धंतोली पुलिया के पास, ग्रेट नाग रोड, नागपुर.
फोन - ०७१२-२७०७४१४/१५ फैक्स- ०७१२-२७५२०२५
Email: chauthiduniyaa@gmail.com

पाठक ध्यान दें
जिन पाठको कों चौथी दुनिया की वार्षिक सदस्यता चाहिए वे फार्म भरकर भेजें या कार्यालय में संपर्क करें.

लेखकों से अपील

चौथी दुनिया में लिखने के इच्छुक लेखकों से उनके लेख आमंत्रित हैं. लेख तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक होने चाहिए. किसी अन्य समाचार पत्र-पत्रिका में प्रकाशित नहीं होने चाहिए. यदि लेख में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में कोई सबूत (दस्तावेज) हो तो उसकी फोटो कापी साथ में संलग्न करके भेजें. लेख हमारे ई मेल, फैक्स या चौथी दुनिया के नागपुर कार्यालय के पते पर भेजा जा सकता है

संपर्क
चौथी दुनिया महाराष्ट्र
27, पिसे काम्पलेक्स, धंतोली रेलवे पुल के पास, ग्रेट नाग रोड, नागपुर
फोन- 0712-2703415, 2703414,
फैक्स नं. : 0712-2752025
ई-मेल : chauthiduniyaa@gmail.com

मोघे उवाच

ये क्या हो रहा है...

मोघे जी

इंसान यानी माटी का पुतला. यह माटी का पुतला ग़लतियों पर ग़लतियां करता रहता है यानी इंसान ग़लतियों की गठरी भी है. जिस काम को समाज, बड़े-बुज़ुर्ग ख़राब, बुरा कहते हों उस कार्य को करने की प्रवृत्ति लोगों में अधिक पाई जाती है. मतलब कि समाज-क़ानून जिस ग़लती को करने से रोके टोके, उसे बार-बार करना कुछ लोग अपनी शान समझते हैं. ऐसा ही मामला है व्यसन व व्यसनमुक्ति का. जिन व्यक्तियों को हो जाए नशे की लत, वह परवाह नहीं करता किसी क़ानून या बंधन की. शराब का लती हो या हेरोइन, चरस-अफ़ीम या गांजे का, अपना व्यसन पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है. अब यह तो नहीं कहा जा सकता है कि व्यसनी को व्यसन के दुर्गुणों की जानकारी न हो. होती है पर सब अपने-अपने व्यसन को जायज़ ठहराने के लिए एक से बढ़कर एक तर्क देते हैं. इसलिए हर क़ानून व बंधन को ठेंगा दिखाने से उसे परहेज़ नहीं होता है. अब इसे सही कहो भइया या ग़लत, यहां तो क़ानून के रखवाले ही क़ानून तोड़ने का कारनामा करने में पीछे नहीं रहते हैं. वे तो इतने दुस्साहसी होते हैं कि क़ानून की कुर्सी पर बैठकर अपने व्यसन के शौक़ को पूरा करते हैं. कुर्सी के पावर से उन्हें मुफ्त में अपने व्यसन पूरा करने का सामान मिल जाता है. व्यसन से ग्रस्त आदमी को न अपने बीबी-बच्चों की फ़िक्र रहती है और न देश-समाज की. घर बर्बाद होता है तो होने दो. घर के बर्तन बेचने पड़ें तो बेचेंगे, पर अपना व्यसन पूरा करेंगे. इसीलिए तो क़ानून-क़ायदा होने के बाद भी शराबी-नशेड़ियों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है. कोई किसी क़ानून की परवाह नहीं कर रहा है. विशेषकर युवा पीढ़ी में शराब, सिगरेट व अन्य नशा करना स्टेट्स सिंबल बन गया है. युवतियां भी अब व्यसन करने में पीछे नहीं हैं. सोचने-विचारने वाली बात यह है कि अब तो पढ़े-लिखे लोग ही व्यसन की लत में लिप्त दिखाई देते हैं. जिन्हें यह मालूम है कि नशा करने से कैंसर, टीबी जैसे भयानक रोग हो सकते हैं. इसीलिए तो हमारे माननीय सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे को कहना पड़ रहा कि क़ायदे-क़ानून के दम पर किसी व्यक्ति को व्यसन मुक्त नहीं किया जा सकता है. सरकार ने क़ायदा बना दिया है. सार्वजनिक जगहों पर व्यसन करने पर रोक लगा दिया है. सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीते पाए जाने पर, पान की पीक थूकने पर जुर्माने तक का प्रावधान किया गया है पर लोगों को जुर्माना होने की ज़रा भी परवाह नहीं है. लोगों को मालूम है कि हमारे यहां क़ानून बताने के लिए बनते हैं, अमल के लिए नहीं. कभी अमल में आया भी तो क़ानून लागू करने वाले की मुट्ठी में दो-चार काग़ज़ का हरा-लाल टुकड़ा पकड़ा कर छुटकारा मिल जाएगा. अब डंकन ड्राइव का ही मामला लीजिए-क्या होता है? ट्रैफिक पुलिस बीयर-बारों के सामने आंख गड़ाए रखती है और कोई वहां से बाहर आया और अपनी दोपहिया-चौपहिया में सवार हो जैसे ही निकला उसके पीछे पड़ जाती है. कुछ दूर जाकर गाड़ी रोक कर उससे सबसे पहले उसका लाइसेंस मांगती है और यदि वह व्यक्ति सही में व्यसन किए रहा तो फिर थाने चलने, चालान काटने की बात होने लगती है. ऐसे में वह व्यक्ति पांच सौ-हज़ार रुपये देकर उनसे निजात पाना उचित समझता है. इससे दोनों ख़ुश हो जाते हैं. दूसरी बात मोघे साहब ने जो कही वह यह कि इसके लिए समाज प्रबोधन की ज़रूरत है. प्रबोधन से ही किसी व्यक्ति के आचार-विचार बदले जा सकते हैं. बात सही है, लेकिन प्रबोधन की सबसे अधिक गरज आज किसे है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यनगरी वर्धा है. सबको मालूम है कि वर्धा में शराब ख़रीदने-बेचने पर प्रतिबंध है. इसके बावजूद सबसे ज़्यादा शराब वहां आती है. बिकती है. लोग अपने पीने का शौक़ भी पूरा करते हैं. यह सब होता है, उन अधिकारियों की छत्र-छाया में, जिनके कंधों पर क़ानून लागू करने की ज़िम्मेदारी होती है, वही इसको बढ़ावा देते हैं. इतना ही नहीं इस गोरखधंधे में कई नेताओं के पुछल्ले भी लिप्त हैं. अब मोघे जी आप ही बताओ की आपके राज में ये क्या हो रहा है? प्रबोधन की सबसे अधिक ज़रूरत किसको है? क़ानून लागू करने वाले को या व्यसनी पदार्थ का व्यवसाय करने वाले को या आपकी सरकार को जो हर साल सैकड़ों-हज़ारों बीयर-बार खोलने का लाइसेंस बांटती है.

सोचिए... समझिए...
मोघेजी....इति.....!

सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीते पाए जाने पर, पान की पीक थूकने पर जुर्माने तक का प्रावधान किया गया है, पर लोगों को जुर्माना होने की ज़रा भी परवाह नहीं है. लोगों को मालूम है कि हमारे यहां क़ानून बताने के लिए बनते हैं, अमल के लिए नहीं. कभी अमल में आया भी तो क़ानून लागू करने वाले की मुट्ठी में दो-चार काग़ज़ का हरा-लाल टुकड़ा पकड़ा कर छुटकारा मिल जाएगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

पुलिस अब तक कोई निर्णय पर भले ही न पहुंची हो, पर मात्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को बम विस्फोट के बाद चमत्कार होने जैसा दृश्य लग रहा है. मानो कोई उनके कान में कोई मंत्र फूंका गया है.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

पृथ्वी बाबा सक्रिय

राकांपा की मुश्किल बढ़ी

फोटो-प्रभात पाण्डेय

युधिष्ठिर जोशी

आतंकवादी हमलों की छाया में रहने वाले मुंबईकर रोज़ की रोज़ी-रोटी की आपाधापी के अभ्यस्त हो गए हैं. इसलिए बम विस्फोट हो या गोलीबारी की घटनाएं हों, वे निर्विवाद रूप से क्षण भर के लिए उसकी ओर ध्यान केंद्रित कर निर्विकार भाव से उसको देखते हैं और कुछ ही मिनटों में पुनः रोज़ी-रोटी के लिए जूझने लगते हैं. उनकी इस प्रवृत्ति का राजनेता भूरी-भूरी प्रशंसा व स्तुति करते हैं- वाह...वाह मुंबईकरों का धैर्य! साक्षात मृत्यु का तांडव शुरू रहने पर भी यह जीवन संघर्ष आगे बढ़ता जाता है वग़ैरह-वग़ैरह. वास्तव में रोज़ी-रोटी के भीषण चक्र में मुंबईकरों की भावना और संवेदना बोझिल हो गई है और वह सोचता है-यह सब चलता रहता है. इसी तरह 13 जुलाई को हुए बम विस्फोट जैसी घटना घटे बहुत समय हुआ नहीं है. राज्य और केंद्र सरकार की अलग-अलग एजेंसियों द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है, पर अब तक इन घटनाओं के लिए ज़िम्मेदार लोग उनके हाथ नहीं आए हैं. मुंबई महानगर के 70 प्रतिशत परिवार रोज़ होने वाली अनिश्चित कमाई पर जीता है. इसके अलावा उनके पास कोई पर्याय नहीं है. इसलिए लोगों के शव लांघ कर भी रोज़गार के लिए उन्हें बाहर जाना ही पड़ता है. पुलिस अब तक कोई निर्णय पर भले ही न पहुंची हो, पर मात्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को बम विस्फोट के बाद चमत्कार होने जैसा दृश्य लग रहा है. बहुधा, दिल्ली में बैठे हाईकमान की ओर से उनके कान में कोई मंत्र फूंका गया है अथवा स्वतः पृथ्वीबाबा को यह साक्षात्कार हुआ होगा.

महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार है. कांग्रेस और राष्ट्रवादी की, राष्ट्रवादी कहें तो भी क्या, लेबल बदल चुकी कांग्रेस. दारू की बोतल वही मात्र लेबल अलग. शरद पवार की अखिल भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस मतलब एक प्रादेशिक पार्टी. राज्य के मतदाताओं का साथ होने से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय होने का डंका बजा सकती है, इतना ही इसका सरल और सीधा अर्थ है. ऐसी राजनीतिक पार्टी की यहां प्रगति हो रही है, यह कमाल ही है. सिर्फ़ शरद पवार के राजनीतिक खेल, दांवपेंच से निपटने वाला पर्यायी नेता कांग्रेस सहित राज्य के किसी भी पार्टी में नहीं होने के कारण राष्ट्रवादी पार्टी के मंत्रियों, विधायकों की दादागिरी, कूटनीति सहन करना ही कांग्रेस पार्टी के हाथ में बचा है. पृथ्वीराज चव्हाण के पहले विलासराव देशमुख और सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री पद आलटुन-पालटुन संभालते रहे, पर शरद पवार व उनकी मंडली का सीधा सामना करने से दोनों ही बचते रहे हैं, परंतु पृथ्वीराज चव्हाण ने इस तरह की रक्षात्मक भूमिका स्वीकार नहीं की और सीधा सींग पर वार लेने और सामना करना स्वीकार किया है.

13/7 को हुए बम विस्फोट के बाद मुंबई के पुलिस विभाग व गृह मंत्रालय द्वारा ढिलाई बरतने की तीखी टिप्पणी की. (13 जुलाई जैसे बम विस्फोट के बाद गृहमंत्री आरआर आबा पाटिल ने मौन साध लिया है.) पाटिल जैसा रसीला बोलनेवाला, घोषणाबाज़ आदमी मौन क्यों है? इस को लेकर सभी लोगों में तर्क-वितर्क शुरू हैं. राष्ट्रवादी के हाईकमान शरद पवार ने आबा के मुंह पर क्या टेप लगा दिया है, ऐसी चर्चा गृह मंत्रालय में हो रही है. परंतु मुख्यमंत्री ने कोई आगा-पीछा न देखते हुए सीधा टोला मार दिया कि गृह और वित्त मंत्रालय का कार्यभार कांग्रेस पार्टी के पास होना चाहिए. मुख्यमंत्री पृथ्वीबाबा के इस बयान से राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर ज़बरदस्त हलचल, कानाफूसी होना शुरू हो गई है, जो स्वाभाविक है. मुख्यमंत्री को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे, गठबंधन धर्म का ख्याल रखना चाहिए. ऐसे बयानों से गठबंधन संकट में पड़ सकता है, ऐसी सिर्फ़ सामान्य प्रतिक्रिया व्यक्त की गई. किंतु सदैव राजनीतिक सावधानी बरतने वाले शरद पवार जागरूक हो गए. स्वतः पवार ने अपने सूत्रों के माध्यम से मुंबई के पुलिस आयुक्त पारसनीस से बात कर स्थिति का जायज़ा लिया. आबा पाटिल को दिल्ली से ही गृह विभाग को सक्षम बनाने की ताक़ीद दी.

इस तरह का घटनाक्रम का इतिहास होने पर भी मुख्यमंत्री चव्हाण अपने बढ़ाये क़दम से ज़रा भी विचलित नहीं हुए. मुंबई महानगर के महत्वपूर्ण जगहों पर पांच हज़ार सीसीटीवी लगाने के लिए क़वायद शुरू कर दी है. गृहमंत्री को साथ लेकर मुंबई पुलिस आयुक्त के कार्यालय में जाकर उच्चाधिकारियों की बैठक ली. पुलिस नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया और वहां आने वाली दिक्क़तों को समझा, साथ ही किन-किन नई ज़रूरतों को पूरी करना ज़रूरी है, इसकी जानकारी ली. मुख्यमंत्री की बढ़ती इस सक्रियता से जहां राष्ट्रवादी पार्टी के मंत्रियों के मन में आशंका पैदा हो गई है. वहीं दूसरी ओर मुंबई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व महानगरीय नेता इससे उत्साहित हो रहे हैं.

पिछले दो दशक से सुलझा न सके गिरणी के मज़दूरों के घरों से जुड़ा सवाल मुख्यमंत्री ने एक ही बैठक कर सुलझा दिया. लालबाग परक जैसा गिरणगांव परिसर से उजड़े कामगारों के परिवार आज तक अपने हक़ से वंचित हैं. 1982 में गिरणी कामगारों की अभूतपूर्व संपानंतर मुंबई की गिरणियां एक के पीछे एक बंद होती गईं. एक करोड़ के क़रीब गिरणी कामगार व उनके परिवार संकट में पड़ गए. उस दरम्यान मुंबई में बिल्डरों की टोली ने बहुमंज़िला इमारत के निर्माण का काम शुरू ही किया था और खुली जगहों पर क़ब्ज़ा कर निर्माण कार्य बेधड़क हो रहे थे. इसका फ़ायदा उठाते हुए बंद गिरणी की ज़मीनों के विकास के नाम पर अपनी तिजोरी भरने का मार्ग गिरणी मालिकों ने अपनाया. परंतु रास्ते पर आ गए कामगारों का क्या, ख़ाली जगह पर घर बना कर देने की मांग की गई. मगर गिरणी मालिक किसी हालत में कामगारों को घर बनाकर देने को तैयार न थे. मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में गिरणी मालिकों की बैठक ली और तुरत-फुरत निर्णय लेकर हज़ारों गिरणी कामगारों के घरों से जुड़ा मामला हल कर दिया. प्रत्येक दो-तीन वर्ष के अंतराल में होने वाली बम विस्फोट की घटनाओं के प्रति आघाड़ी सरकार के रवैये से विचलित व परेशान हैं. कांग्रेस पार्टी मुंबईकरों की उपेक्षा कर रही है. इस महानगर के प्रति कांग्रेस सरकार के लापरवाह होने की बात मुंबईकरों की समझ में आ गई है. इससे मुंबईकरों में आक्रोश बढ़ रहा है और आगामी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में यह सामने आ सकता है. इस महानगर में कांग्रेस पार्टी को करारा झटका लगने वाला है. इसका भय पार्टी को सताने लगा है. इसलिए कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री को अभी से चेता दिया है. सर्वप्रथम सांसद गुरुदास कामत ने मुंबई में हुए बम विस्फोट के मामले में राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी दी है. पिछले लोकसभा चुनाव में मुंबई महानगर की छह सीटों में से पांच कांग्रेस ने जीत कर शिवसेना-भाजपा को करारा झटका दिया था. अगले वर्ष होने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में शिवसेना-भाजपा को कांग्रेस पराजित करने के मनसूबे बना रही है, परंतु आए दिन हो रहे बम विस्फोट से अक्रोशित मुंबईकरों ने अपनी भावना यदि मतपेटियों में व्यक्त कर दी तो यह कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी शर्मनाक रहेगा. इसका भय मुख्यमंत्री को परेशान किए हुए है. इसी के मद्देनज़र उनकी सक्रियता बढ़ गई है, यह मानना है राज्य के राजनीतिक विश्लेषकों का. कारण कोई भी हो पर मुख्यमंत्री पृथ्वीबाबा सक्रिय हो गए हैं, निर्णय लेने लगे हैं, यही कम है क्या.

feedback@chauthiduniya.com

पिछले दो दशक से सुलझा न सके गिरणी के मज़दूरों के घरों से जुड़ा सवाल मुख्यमंत्री ने एक ही बैठक कर सुलझा दिया. लालबाग परक जैसा गिरणगांव परिसर से उजड़े कामगारों के परिवार आज तक अपने हक़ से वंचित हैं. 1982 में गिरणी कामगारों की अभूतपूर्व संपानंतर मुंबई की गिरणियां एक के पीछे एक बंद होती गईं. एक करोड़ के क़रीब गिरणी कामगार व उनके परिवार संकट में पड़ गए. उस दरम्यान मुंबई में बिल्डरों की टोली ने बहुमंज़िला इमारत के निर्माण का काम शुरू ही किया था और खुली जगहों पर क़ब्ज़ा कर निर्माण कार्य बेधड़क हो रहे थे. इसका फ़ायदा उठाते हुए बंद गिरणी की ज़मीनों के विकास के नाम पर अपनी तिजोरी भरने का मार्ग गिरणी मालिकों ने अपनाया.

चौथी दुनिया
आज ही अपना अंक सुरक्षित करवाएं
महाराष्ट्र
आशिर्वाद पब्लिकेशन प्रा.लि.
२७, पिसे कॉम्प्लेक्स धंतोली रेलवे पुल के पास, ग्रेट नाग रोड, नागपुर- ४४०००३
फोन नं. - ०७१२- २७०७४१४/१५
Email:- chauthiduniyaa@gmail.com
हॉकर और बुक स्टॉल धारकों के लिए उपलब्ध
राष्ट्रीय साप्ताहिक १६ पृष्ठों के साथ महाराष्ट्र के रंगीन ४ पृष्ठ

नागपुर	: पाठक ब्रदर्स, नागपुर	– 0712 2420293
नागपुर	: दांगट न्यूज पेपर, रामदासपेठ, नागपुर	
जलगांव	: पाठक ब्रदर्स, जलगांव	– 0257–2225806
नासिक	: पाठक ब्रदर्स, नासिक	– 0253–2506898
पुणे	: आलोक मिश्रा, पुणे	– 9372922174
अकोला	: कृष्णा मार्केटिंग, अकोला	– 9011325700
चंद्रपूर–गडचिरोली	: रतन न्यूज पेपर एजन्सी	– 07172–258554
बुलढाणा	: अनुप महाजन चिखली, बुलढाणा	
यवतमाळ–वर्धा	: चिव परी न्यूज पेपर एजन्सी द्वारा संदिप खडेकर	– 9822698406
गोंदिया	: शर्मा न्यूज पेपर एजन्सी	– 9422831088

एजेंसी के लिए आवेदन आमंत्रित है.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 08 अगस्त–14 अगस्त 2011

www.chauthiduniya.com

उत्तर भारत का एकमात्र संस्थान जहाँ चेतन भगत, किरण बेदी, जोगिन्दर सिंह, कुलदीप नैयर, रघुराम जैसे लोग देते हैं छात्रों को सफलता का मंत्र.

बिजनेस एंड इकोनोमी और भाष्कर लक्ष्य द्वारा 50 बेहतर संस्थानों में चयनित बिहार का एकमात्र कॉलेज

नामांकन हेतु सम्पर्क करें www.abcollege.org

आरकेड बिजनेस कॉलेज

PERMANENTLY AFFILIATED TO MAGADH UNIVERSITY BODHGAYA

Arya Kumar Road, Rajendra Nagar, Patna 800 016

Tel. (0612) 2666000, 2663335, 9199662200

मगध विश्वविद्यालय के 100% रेगुलर पाठ्यक्रम

BCA | BBM

BBA (Retail)

MASS COMM

सरकार ने कहा, ऑल इज़ वेल

दरअसल जितनी तेज़ी से बियाडा ज़मीन का आवंटन हुआ, वह शक पैदा करता है, जबकि सभी जानते हैं कि यहां जाति प्रमाण पत्र बनवाने में भी महीनों लग जाते हैं. जितनी जल्दी में फोन पर जांच पूरी कर रिपोर्ट दी गई, उससे भी शक गहराता है. एक अहम सवाल यह भी कि क्या एक नौकरशाह का चयन रसूखदार नेताओं के ख़िलाफ़ जांच के लिए उचित था. यही कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर पूरा विपक्ष सड़क पर उतर आया है. पटना से लेकर दिल्ली तक विरोध जारी है, पर सरकार कह रही है ऑल इज वेल.

शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है
क़ातिल की ज़ुबां से क़त्ल की कहानी है

सरोज सिंह

बियाडा ज़मीन आवंटन मामले में जो चर्चित चेहरे शक के घेरे में आए उन्हीं से फोन पर बात कर जांच की औपचारिकता पूरी कर ली गई और उन्होंने जो कहा उसी आधार पर यह फ़रमान सुना दिया गया कि सब कुछ नियम के अनुसार हुआ है, लेकिन जिस तरह भूमि आवंटन के तरीक़े सवाल खड़े करते हैं, उसी तरह जांच के तरीक़े भी. बियाडा से लाभान्वित कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें आवेदन के महज़ 15 दिनों के भीतर भूमि आवंटित हो गई. कुछ कंपनियां तो ऐसी भी हैं जिन्हें आवेदन के तीन–चार दिन बाद ही भूमि आवंटित कर दी गई. समाज कल्याण मंत्री परवीन अमानुल्लाह की बेटी रहमत फ़ातिमा ने 24 मई 2011 को दो एकड़ भूमि आवंटन के लिए आवेदन दिया. बियाडा के प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी (पीसीसी) ने इसी दिन 24 मई को ही बैठक कर उन्हें बिहिया में दो एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय कर लिया और मात्र एक पखवाड़े बाद बियाडा की ओर से आवंटन आदेश भी जारी कर दिया गया. इसी तरह जहानाबाद के सांसद जगदीश शर्मा के विधायक पुत्र राहुल कुमार ने बियाडा में पीने वाला पानी तैयार करने हेतु संयंत्र लगाने को भूमि के लिए आवेदन दिया था. इसके एक पखवाड़े के भीतर पीसीसी की बैठक में उनकी कंपनी मेसर्स देवलोक विभरेज प्रा. लि. को 15500 वर्ग फीट भूमि का 44 लाख तैंतीस हज़ार रुपये में आवंटन का निर्णय ले लिया गया. उल्लेखनीय है कि राहुल कुमार उक्त कंपनी के निदेशक हैं, लेकिन उन्होंने नवंबर 2010 के विधानसभा चुनाव के समय दाख़िल चुनावी शपथ–पत्र में इस कंपनी में मात्र पांच लाख रुपये मूल्य के शेयर होने का ज़िक्र किया है, जबकि सिर्फ़ बियाडा द्वारा आवंटित भूमि के लीज मूल्य की प्रथम क़िस्त के रूप में उनकी कंपनी की ओर से एक अगस्त 2010 को 13 लाख 90 हज़ार रुपये जमा किए गए थे. एसए भीमराजा की कंपनी निभी इंडस्ट्रीज ने 24 अगस्त 2009 को बियाडा के समक्ष आवेदन दिया. मात्र चार दिन बाद पीसीसी की बैठक में इसे 653400 वर्ग फीट अर्थात 15 एकड़ ज़मीन को साढ़े आठ लाख प्रति एकड़ की दर से आवंटित कर दिया गया. उसे 2011 में भी और डेढ़ एकड़ भूमि प्रदान की गई है. आरोप उछला था कि भीमराजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सचिव एस. सिद्धार्थ के कथित रिश्तेदार हैं. ग़ौर करने वाली बात है कि कई आवेदकों का आवेदन लंबे अरसे तक इस आधार पर लटकाया गया कि पीसीसी की बैठक नहीं हुई है. बैठक होने पर सूचना दी जाएगी.

अनूप मुखर्जी

रिपोर्ट जारी करते उद्योग सचिव सी के मिश्रा.

वहीं प्रभावशाली लोगों के भूमि आवंटन में हैरतअंगेज़ तेज़ी के बारे में मुख्य सचिव की जांच रपट कुछ नहीं कहती. इसी तरह उक्त रपट को जारी करने वाले अधिकारी यह नहीं बता सके कि जांच का यह कौन सा तरीक़ा हुआ कि जिन्हें भूमि आवंटित हुई, उनमें से ही कुछ से फोन कर यह पूछा भर गया कि क्या वे अमुक के रिश्तेदार हैं? कथित आरोपी के कहने भर से ही आरोप को झूठा मान लिया गया. मुख्य सचिव अनूप मुखर्जी की 18 पृष्ठों की जांच रिपोर्ट जारी करने वाले उद्योग विभाग के प्रधान सचिव सीके मिश्रा ने जांच के इस अजीब तरीक़े को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि जांच की प्रक्रिया पर टिप्पणी करने के बजाय वह इस रिपोर्ट से सभी को अवगत कराना चाहते हैं. इसी रिपोर्ट में ज़िक्र है कि फारबिसगंज में अशोक चौधरी के फर्म को साढ़े पैंतीस एकड़ भूमि आवंटित की गई, लेकिन उनका भाजपाई एमएलसी अशोक अग्रवाल से कोई संबंध नहीं है. हालांकि स्थानीय मदद के लिए उन्होंने अशोक अग्रवाल के पुत्र सौरभ अग्रवाल को कंपनी के निदेशक मंडल में रखा था अर्थात भजनपुरा में पुलिसवालों का नंगा नाच उनकी स्थानीय मदद का ही एक स्वरूप था. जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि उर्वशी शाही के मैत्रेय एजुकेशन ट्रस्ट को हाजीपुर स्थित एक्सपोर्ट प्रामोशन इंडस्ट्रियल पार्क (ईपीआईपी) में ज़मीन दी गई है. केंद्र सरकार के सहयोग से 1990 में लागू हुई ईपीआईपी योजना के तहत केवल वैसी औद्योगिक इकाई को ज़मीन दी जा सकती है जो अपने उत्पाद का कम से कम 33 प्रतिशत निर्यात करे, लेकिन ईपीआईपी में मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट के लिए भूमि आवंटित हुई है. उद्योग विभाग के प्रधान सचिव सीके मिश्रा भी कहते हैं कि ईपीआईपी के प्रावधान में कोई संशोधन नहीं किया गया है. यह पूछे जाने पर कि क्या ईपीआईपी में शैक्षणिक संस्थान को ज़मीन दी जा सकती है तो उन्होंने कहा कि बियाडा की 20 प्रतिशत ज़मीन को शैक्षणिक संस्थानों को दिया जाना है. जांच रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि बियाडा के प्रावधान ईपीआईपी पर क्यों लागू हुए? मुख्य सचिव की जांच रिपोर्ट में मीडिया पर भी विधि सम्मत कारवाई की अनुशंसा की गई है. मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी गला घोटने की भी पूरी तैयारी है. ग़ौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से इस मामले पर मीडिया के रोल पर कोई रिपोर्ट नहीं मांगी थी. रिपोर्ट तैयार करते वक़्त इन मीडिया वालों से भी बात नहीं कि गई जो इस मामले को जनता के सामने ला रहे हैं.

क़ाबिले ग़ौर है कि बिहार के गया ज़िले में भी डोभी रोड पर बियाडा की तक़रीबन 31 एकड़ ज़मीन थी. जानकारों की राय है कि वहां ज़मीन करोड़ रुपये में भी नहीं मिलती है, परंतु वह ज़मीन मात्र 6 से 10 लाख रुपये एकड़ के मूल्य पर आवंटित कर दी गई. इसका आवंटन अगर विज्ञापन प्रकाशित कर किया जाता तो बड़ी–बड़ी कंपनियां वहां उद्योग लगातीं. ज़मीन का उचित मूल्य भी मिलता और रोज़गार के अवसर भी पैदा होते. गया में उद्योग लगाने वाली संस्थाओं को काफ़ी कम ज़मीन आवंटित की गई. वहीं एक कथित शिक्षा माफ़िया को विभिन्न संगठन बुद्धा मल्टीप्लेक्स एवं होटल मैनेजमेंट, बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओम समाज विकास परिषद और बुद्धा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्रस्ट के नाम पर तक़रीबन साढ़े पांच लाख वर्ग फीट ज़मीन आवंटित की गई. आवंटी अवधेश कुमार अशोक नगर गया का है. उल्लेखनीय है कि बिहार में शिक्षा को उद्योग घोषित नहीं किया गया है. वहां 29 फर्मों को भूमि आवंटित की गई, जिसमें अवधेश कुमार के चार शिक्षण संस्थानों को पांच लाख वर्ग फीट से ज़्यादा और अन्य 24 फर्मों को कुल मिलाकर मात्र तीन लाख 91 हज़ार 970 वर्ग फीट ज़मीन का आवंटन हुआ है. इन्हीं बातों को लेकर सारा विपक्ष सड़क पर है, पर सरकार कह रही है कि सब ठीक है. अब सबकी निगाहें कोर्ट पर लगी हैं.

feedback@chauthiduniya.com

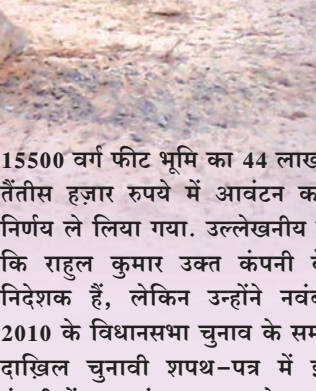

दीनू कुमार

सारे नियम ताक़ पर रख दिए गए : दीनू

पटना उच्च न्यायालय के वकील दीनू कुमार का कहना है कि बियाडा ज़मीन आवंटन मामले में सारे नियमों को ताक़ पर रख दिया गया. उनकी राय में यह पूरा आवंटन नैसर्गिक न्याय के ख़िलाफ़ है तथा क़ानून का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि औद्योगिक नीति 2006 में कहा गया था कि बियाडा ज़मीन की घेराबंदी कर तथा लाइटिंग का इंतज़ाम कर आवंटन करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ. बिना टेंडर व नीलामी के ज़मीन आवंटन से सबको समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन हुआ. दीनू कुमार मानते हैं कि कुछ ख़ास लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दिसंबर 2007 में नियमों मे परिवर्तन किया गया और ज़मीन की बंदरबांट की गई. उन्होंने कहा की एसी डीसी बिल मामले में भी सरकार की करतूत सामने आ गई है और अरबों रुपये के इस घोटाले में सरकार पूरी तरह घिर गई है. उन्होंने कहा कि अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.

Ph:0612-3296829, 9334252869, 9386941721

Approved by Govt. of India

... The Way to Grow

SKY CONSULTANCY SERVICE PVT. LTD

DIRECT & CONFIRM ADMISSION

Contact : 604, 6th Floor LUV-Kush Tower Exhibition Road, Patna-1

Ph: 0612-3296829
9334252869
9386941721

2010 Admission Report

Bangalore Chennai
Delhi/NCR Punjab
Pune Bhopal

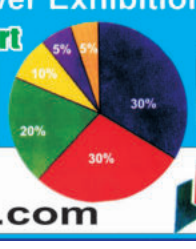

OUR EDUCATION PARTNER

Our Copration with you from 2001 to 2011

SCSPL

Engineering | MBA/PGDBM | MBBS | MCA | B.Ed

B.Pharma | Polytechnic | BBA | ITI

Branch: Yadav Market, Near Circut House Pakri Chowk Ara,
Mob;9798662051, 9334006756, Muzaffarpur Chhapra

Email : consultancy.sky.patna@gmail.com

चौथी दुनिया

दरअसल बात इतनी भर थी कि उस वक़्त बिहार में नीतीश की नहीं, बल्कि लालू की सरकार थी. विशेष राज्य का दर्जा दे राजग सरकार, और मज़ा लें लालू. यह भला नीतीश कैसे कर सकते थे.

एक नज़र

मांझी से लार रोड तक बिछेगी पटरी

सारण ज़िले के मांझी से उत्तर प्रदेश के लार रोड तक रेलवे लाइन बिछाने की क़वायद शुरू हो गई है. इससे बिहार व यूपी के सीमांत क्षेत्रों के लोगों की बहुप्रतिक्षित मांगे पूरी हो सकती हैं. यह क्षेत्र सुदूर ग्रामीण इलाक़ों में है और लंबे समय से यहां की आबादी रेल लाइन होने का सपना देख रही थी. दियारा क्षेत्र होने व सरयू नदी का तटीय इलाक़ा होने से यहां आवागमन के साधन भी सीमीत हैं. रेलवे लाइन के बिछ जाने से सिवान ज़िले के सिसवन रघुनाथपुर, आन्दर व दरौली प्रखंड क्षेत्रो के लोगों का सपना साकार होने की संभावना बलवती हो गई है. पिछले हफ्ते रेलवे की टीम मांझी से लेकर सिसवन क्षेत्र में रेल लाइन के लिए सर्वे कर रही हैं. टीम के सदस्यों ने इस बाबत कई स्थलों का मुआयना किया. जायज़ा लेने के उपरांत सर्वेक्षण टीम केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

- विजयेंद्र कुमार

शिवालय में चमत्कार से लोग हैरान

मुंगेर ज़िले केमयदरियापुर स्थित स्वामी अनुरागानंद द्वारा स्थापित शिव मंदिर शिवधाम इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. इस मंदिर के गर्भगृह में बने शिवलिंग और उसके पास दीवार से अचानक जल निकलने से पूरा का पूरा इलाक़ा भक्तिमय हो उठा है. लोग इसे भगवान का चमत्कार मान उसकी पूजा-अर्चना करने में जुट गए हैं. यह ख़बर जैसे ही गांववालों तक पहुंची तो लोग भागते हुए इसे देखने केलिए उमड़ पड़े. लोग इस गिर रहे जल को भगवान का प्रसाद मानकर पी रहे हैं. बर्तन के पात्रों में जल भर श्रद्धालु अपने घर ले जा रहे हैं और घर के कोने-कोने में छींट कर घर को पवित्र कर रहे हैं. बचे जल को पूजा घर में रख रहे हैं. दीवार से निकले जल का बहाव भी इतना है कि एक से दो घंटे में एक बड़ी बाल्टी भर जाए.

साहिल स्टडी के कार्यक्रम में प्रीति की धूम

बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं. यहां के विद्यार्थी मेहनती व लगनशील हैं, शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के विद्यार्थी विश्व में नाम रौशन कर रहे हैं, ये बातें श्रम मंत्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ने साहिल स्टडी सर्कल के वार्षिकोत्सव समारोह में कही. उन्होंने कहा कि यहां की प्रतिभा को उभारने की ज़रूरत है. उन्होंने संस्थान की तारीफ़ करते हुए कहा कि यहां के विद्यार्थी को कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे संस्थान लगन से कार्य करें तो हम कोटा को पीछे छोड़ देंगे. साहिल स्टडी सर्कल के निदेशक डॉ. मिथिलेश कुमार ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि विभिन्न मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के परिणाम से हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. इसने हमें सर्वोत्तम संस्था की पहचान दी है. साहिल स्टडी ...

लगन हो तो मंज़िल दूर नहीं : सरीन

ऋण सुविधा
वाहन ऋण, सावधि ऋण,
कैश क्रेडिट, पैक्सों के वास्ते
ऋण, सुविधा सस्ते ब्याज दर पर उपलब्ध है
दि कोशी सेन्ट्रल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड

LIFE LINES
NOT JUST PIPE LINES
NATRAJ
PVC PIPES
CASING, PLUMBING, S.W.R.

महादलितों को नदियों के गर्भ में ज़मीन मिली

राजेश सिन्हा

बिहार के विभिन्न ज़िलों में नदियों के गर्भ से निकली ज़मीन पर मालिकाना हक़ जताने के एवज में वैसे तो वर्षों से ख़ून की होली खेली जाती रही है. कई बार नरसंहार की घटनाओं को अंजाम देकर किसी की मांग उजाड़ी गई तो किसी की गोद सूनी कर दी गई, लेकिन इस बार सूबे के कई ज़िलों में अंचलाधिकारी और ज़िला निबंधक पदाधिकारियों ने तथाकथित भू-स्वामियों की मिलीभगत से नरसंहार की ऐसी बुनियाद खड़ी की है, जिसे अगर अविलंब ध्वस्त नहीं किया गया तो बिहार में नरसंहार की ऐसी गाथा लिखी जाएगी, जिसे भूला पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगी. दरसअसल राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक भूमिहीन महादलित परिवारों को तीन-तीन डिसमिल ज़मीन दिए जाने की नीति के तहत अंचलाधिकारियों ने दर्जनों महादलित परिवारों के नाम न केवल नदियों के गर्भ में पल रही ज़मीन का निबंधन करा दिया, बल्कि सरकारी राजस्व को जमकर चूना भी लगाया. बिहार के अन्य ज़िलों में महादलितों के साथ ज़मीन आवंटन के नाम नाम पर हुए धोखे का राज़ तो अभी नहीं खुला है, लेकिन सूबे के सबसे पिछड़े ज़िले खगड़िया में महादलितों के साथ हुए धोखे का मामला खुलकर सामने आ गया है.

कई माह तक इस मामले को दफ़न करने का प्रयास किया गया, लेकिन जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने वक़्त की नज़ाकत को भांपते हुए न केवल मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई, बल्कि मामले को जांचोपरांत सही पाकर आरोपी अंचलाधिकारी अशोक कुमार सिंह के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश भी जारी कर दिया. जिलाधिकारी धर्मेंद्र के आदेशानुसार खगड़िया के अनुमंडल पदाधिकारी सुभाष चंद्र मंडल द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद से अंचलाधिकारी अशोक भूमिगत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने भूमिगत रहने के दौरान चौथी दुनिया से वार्ता की. उन्होंने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि महादलितों के लिए तीन-तीन डिसमिल ज़मीन क्रय करने के मामले में अगर वह दोषी हैं, तो बिहार के सभी अंचलाधिकारियों के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि लगभग सभी अंचाधिकारियों ने इस मामले में वरीय पदाधिकारियों के आदेश पर सरकारी आदेश का उल्लंघन किया है. इस मामले की गुत्थी कब तक सुलझ पाएगी और कब तक सभी दोषी जेल की सलाख़ों के पीछे होंगे, यह कहना तो अभी जल्दबाज़ी होगी, लेकिन फिलवक़्त इस मामले की तह तक जाने की सख्त आवश्यकता है. खगड़िया के अंचाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने प्रखंड के रसौंक मौजा के बांध व नदी के बीच बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में असिंचित ज़मीन को सिंचित दिखाकर न केवल लाखों की सरकारी राशि की हेरा-फेरी की, बल्कि बागमती के गर्भ में पल रही ज़मीन को महादलितों के नाम निबंधित करा दिया गया. इस मामले पर हाय तौबा मचने के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर जन शिकायत कोषांग प्रभारी सह डीसीएलआर ने मामले को सही बताते हुए अपने पत्रांक 1020/09.07.2011 द्वारा अंचलाधिकारी अशोक कुमार सिंह को दोषी माना. इतना ही नहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए जनशिकायत कोषांग द्वारा पत्रांक ...

खगड़िया

राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक भूमिहीन महादलित परिवारों को तीन-तीन डिसमिल ज़मीन दिए जाने की नीति के तहत अंचलाधिकारियों ने दर्जनों महादलित परिवार के नाम न केवल नदियों के गर्भ में पल रही ज़मीन का निबंधन करा दिया, बल्कि सरकारी राजस्व को जमकर चूना भी लगाया. बिहार के अन्य ज़िलों में महादलितों के साथ ज़मीन आवंटन के नाम नाम पर हुए धोखे का राज़ तो अभी नहीं खुला है, लेकिन सूबे के सबसे पिछड़े ज़िले खगड़िया में महादलितों के साथ हुए धोखे का मामला खुलकर सामने आ गया है.

feedback@chauthiduniya.com

नीतीश कुमार 2002 में पीछे हट गए थे

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

सन 2002 में बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो उन दिनों केंद्र की राजग सरकार में एक महत्वपूर्ण मंत्री और प्रभावशाली नेता थे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस प्रस्ताव से क्यों अलग हो गए थे? इस मुद्दे पर गठित एक उच्च स्तरीय समिति की, जिसके वह एक प्रभावशाली सदस्य थे, की बैठकों में वह लगातार क्यों अनुपस्थित रहे? यदि वह चाहते तो उसी समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता था, तो उन्होंने गंभीरता क्यों नहीं बरती? आज फ़िर वही मुद्दा लेकर वह क्योंकर हाय-तौबा मचा रहे हैं? उस वक़्त यह ज़रूरी नहीं था. आज इतना ज़रूरी क्यों हो गया कि उन्हें इसकी ज़बरदस्त क़वायद करनी पड़ रही है और इसी क़वायद में राजग के सारे मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता लगे पड़े हैं? ये सवाल अब राजनीतिक गलियारों से निकलकर, शहरों के चौक-चौराहों और गांव के गलियारों और चौपालों में भी पूछे जा रहे हैं. अब वे लोग भी ऐसे सवालों से बचने के लिए नज़रें चुराने लग गए हैं, जिन्होंने राज्य की बेहतरी की आस में मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर अभियान में अपनी भागीदारी दी थी.

विगत 18 जुलाई को, कभी नीतीश के क़रीबी रहे, उपेंद्र कुशवाहा एवं लोजपा सुप्रीमो राम विलास पासवान ने, पटना में, दो अलग-अलग स्थानों पर संवाददाता-सम्मेलन किया. यह महज़ इत्तेफ़ाक़ था या कुछ और, मगर दोनों की वार्ता का केंद्रीय विषय यही था. दोनों ही नेताओं ने मोटे तौर पर एक ही बात कही, जिसका आशय यही था कि नीतीश ने इस मुद्दे पर उन दिनों कोताही बरती. यदि वह चाहते तो सन 2002 में ही प्रदेश को यह दर्जा मिल जाता, क्योंकि उस वक़्त सभी केंद्रीय नेताओं में इसको लेकर आम सहमति बन चुकी थी. अधिकांश लोग इस तथ्य से अवगत नहीं है कि सन 2000 में, बिहार के विभाजन के पश्चात, राज्य की विधानसभा ने सर्व-सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया था, क्योंकि विभाजन के कारण आर्थिक स्रोतों का एक बड़ा हिस्सा झारखंड में चला गया है तथा उससे प्रदेश में भारी आर्थिक तंगी पैदा हो रही है, इससे राज्य को उबारने के लिए इसे विशेष राज्य का दर्जा मिले. हालात की गंभीरता को समझते हुए केंद्र ने इस विषय पर निर्णय लेने के लिए एक उच्चाधिकार समिति गठित की थी, जिसमें नतीश कुमार, बिहार के प्रबल प्रतिनिधि के रूप में शामिल थे. यह सच है कि इस समिति की लगातार हुई कई बैठकों में नीतीश कुमार अनुपस्थित रहे. बिहार के संदर्भ में और उसमें भी इतने अहम मुद्दे पर नीतीश के बिना निर्णय हो तो कैसे हो, इसलिए ये बैठकें बिना किसी निर्णय के समाप्त होती रही. नीतीश इतने महत्व के मुद्दे पर इतने उदासीन क्यों रहे? इस सवाल का उत्तर किसी के पास नहीं है. किसी एक बैठक में अनुपस्थिति की वजह कोई अपरिहार्य-कारण मानी जा सकती है, किंतु यह बार-बार हो, तो किसी को दाल में काला लगे, तो इसे ग़लत कैसे कहा जाए?

दरअसल बात इतनी भर थी कि उस वक़्त बिहार में नीतीश की नहीं, बल्कि लालू की सरकार थी. विशेष राज्य का दर्जा दे राजग सरकार, और मज़ा लें लालू. यह भला नीतीश कैसे कर सकते थे. माना कि नीतीश बिहार का विकास चहते हैं, पर इसका श्रेय किसी और को मिले, नीतीश ऐसी राजनीतिक नादानी कैसे करते? लिहाज़ा वही हुआ जो नीतीश चाहते थे. मामला ठंडे बस्ते मे डाल दिया गया. अब परिस्थितियां बदल गई हैं. प्रदेश में लालू-राबड़ी की नहीं नीतीश की सरकार है. पिछली सरकार की लानत-मलानत करते पांच वर्ष कट गए. बीच-बीच में केंद्र सरकार को बाधक बता-बता कर भी काम चलाया गया, किंतु आगे ये दोनों शिगूफ़े और नहीं चलाए जा सकते थे. क्योंकि विकास की बातें और घोषणाएं छलावा सिद्ध हो रही थीं. विकास के नाम पर कुल जमा कुछ उच्च-पथों का निर्माण-पुनर्निर्माण और नगरों के पार्कों की सजावट दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा सकती थी. इनके अतिरिक्त बिजली-पानी, कल-कारख़ाने, शिक्षा-स्वास्थ्य, क़ानून-व्यवस्था, रोज़गार के अवसर जैसी प्राथमिकता वाले क्षेत्र लगातार उपेक्षित होते गए. आत्म-निर्भरता की दिशा में कोई ठोस पहल हो न सकी और जनता में खलबली बढ़ी तो ठंडे बस्ते में पड़ा यह प्रस्ताव यकायक नीतीश को याद आ गया. सरकार के प्रति जनता में फैल रही निराशा को नई दिशा देने में इससे अच्छा कोई दूसरा समीचीन मुद्दा नहीं हो सकता था. इसलिए इस दिशा में क़वायद शुरू हो गई, लेकिन यह मुद्दा क्या राज्य सरकार की विफलताओं को ढकने तथा इनसे जनता का ध्यान बंटाने मे सफल हो सकेगा? इसका उत्तर तो फ़िलवक़्त भविष्य के गर्भ में है. मगर इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि नीतीश का यही रवैया आने वाले दिनों में उनके गले की फांस बनने वाला सिद्ध होगा. नीतीश एक चालाक कूटनीतिज्ञ हैं यह तो सिद्ध होगा, लेकिन यह भी सिद्ध हो जाएगा कि वह जनता और बिहार के लिए ईमानदार नहीं हैं. वह भी उन्हीं लोगों की कतार के व्यक्ति हैं, जो केवल वही सब कुछ करता है, जो राजनीतिक फ़ायदे के लिए किए जाते हैं. वही तिकड़म की ओछी राजनीति. उससे अलग कुछ भी नहीं, जैसा शोर मचा-मचाकर कहने, दिखाने की कोशिशें होती रही हैं. सिक्के के दो पहलू की तरह. यदि विकास की बातें करें, जिसके लिए नीतीश का गुणगान विश्व-व्यापी किया जा रहा है, तो उन लोगों को बहुत निराशा होगी, जो प्रचार माध्यमों की सूचना पर नीतीश के बारे में एक बड़ी ऊंची राय बनाकर रखे हुए हैं. दरअसल नीतीश ने प्रचार माध्यमों का बहुत योजनाबद्ध तरीक़े से उपयोग किया है. देश-दुनिया में बिहार की छवि अच्छी बनी हो या नहीं, नीतीश की छवि बड़ी सुंदर दिखाई गई है. सच कहा जाए तो इस शासन में सबसे अच्छे ढंग से यही काम किया, कराया गया है. उदाहरण के तौर पर स्कूली छात्राओं के लिए निःशुल्क साइकिल योजना को लिया जा सकता है. कितनी लुभावन और कल्याणकारी योजना मालूम होती है, कहने की आवश्यकता नहीं. लड़कियां सुविधा से विद्यालय जा सकेंगी. छात्राओं में स्कूल जाने के लिए उत्साह बढ़ेगा, बढ़ा है. लेकिन कितने लोग इस सच को जानते हैं कि इसी सरकार में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में कितनी बड़ी धांधली और कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ. बिना किसी पात्रता-परीक्षा के, यहां तक कि बिना किसी साक्षात्कार या पूछताछ के हज़ारों की संख्या में, केवल ग्राम-पंचायतों के मुखियाओं की अनुशंसा पर शिक्षकों की नियुक्तियां हुईं. ऐसे-ऐसे शिक्षक बहाल हुए, जिन्हें अक्षर-ज्ञान भी था या नहीं, विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता. कई न्यूज चैनलों ने स्पष्ट दिखाया कि शिक्षक महोदय दिनों के नाम तक ब्लैक-बोर्ड पर सही नहीं लिख सकते थे. ऐसे गुरुओं से उनके शिष्य अधिक जानकार निकले, जो संवाददाताओं को सही-सही उत्तर बता पा रहे थे. छात्र कह रहे थे कि सर बोर्ड पर ग़लत लिख रहे हैं. यह तो ठीक है कि नीतीश की साइकिल पर सवार होकर लड़कियां विद्यालय जाया करेंगी, मगर वह पढ़ेंगी किन शिक्षकों से? एक तरफ़ वाह-वाही लूटने के लिए आप साइकिल दें, वहीं उनका भविष्य चौपट करने वाले शिक्षक हों, तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाएगा? क्या यह पाखंड नहीं है? चॉकलेट थमाकर, बहला-फुसलाकर बच्चों के भविष्य का अपहरण नहीं है? यदि कुछ जानकर और विपक्ष के लोग ऐसा कहते हैं, तो इसमें क्या ग़लत है? कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति में की गई वह ऐतिहासिक गड़बड़ी भी प्रदेश की एक बड़ी राजनीतिक शक्ति की इच्छा से हुई थी. सूत्रों की मानें तो राज्य के तत्कालीन मानव संसाधन विकास आयुक्त स्व. मदन मोहन झा ने संचिका में इस प्रस्ताव का विरोध किया था कि शिक्षकों की नियुक्ति केवल मुखिया की अनुशंसा पर हो, लेकिन स्व. झा को इसके लिए विवश किया गया कि वह वैसा ही प्रस्ताव दें. संचिका के उस अंश से संबंधित पृष्ठ को हटाकर, फ़िर से नई टिप्पणी लिखाई गई. स्व. झा एक नेक और ईमानदार पदाधिकारी ही नहीं, बल्कि बिहार के सच्चे हित-चिंतक भी थे. वह शिक्षा में गुणात्मक सुधार के पक्षधर थे. वह लगातार नेक प्रयासों में लगे रहते थे. इस घटना की भयावहता से वह परिचित थे. वह जान चुके थे कि यह गड़बड़ी बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने की भयंकर भूल सिद्ध होगी. उन्हें यह भी लगता था कि सरकार के इस महापाप में, विवशता में ही सही, किंतु उनकी भी भागीदारी हो गई है. यह भूल उन्हें अंदर ही अंदर खाये जा रही थी. इस पाप के लिए वह स्वयं को माफ़ नहीं कर पा रहे थे. उनके प्राण-घातक हृदय-आघात के प्रमुख कारणों में एक, इसे भी माना जा रहा है. यह सच है कि इस पूरे प्रकरण में गवाही देनेवाला इस वक़्त कोई नहीं है, किंतु यदि इसकी निष्पक्ष जांच हुई, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं, जो राजनीतिक भूचाल पैदा हो सकता है. यह एकमात्र उदाहरण नहीं है. इस सरकार के हर एक महकमे से भ्रष्टाचार की बदबू आने लगी है. नीतीश के पास अभी भी अवसर है कि वह अपनी कार्य-प्रणाली को सुधारे लें. यह तो तय है कि अगली बार उन्हें फ़िर अवसर नहीं मिलेगा, किंतु तब तक बिहार की बड़ी हानि हो चुकी होगी. ऐसी क्षति, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती. आनेवाली पीढ़ियां चकित होंगी कि एक ऐसा भी मुख्यमंत्री था, जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया की मीडिया में हो रही थी, और उसने ही प्रदेश की लुटिया डुबो दी.

अधिकांश लोग इस तथ्य से अवगत नहीं हैं कि सन 2000 में, बिहार के विभाजन के पशचात, राज्य की विधानसभा ने सर्व-सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया था, क्योंकि विभाजन के कारण आर्थिक स्रोतों का एक बड़ा हिस्सा झारखंड में चला गया है तथा उससे प्रदेश में भारी आर्थिक तंगी पैदा हो रही है, इससे राज्य को उबारने के लिए, इसे विशेष राज्य का दर्जा मिले.

डॉ. अनिल सुलभ
feedback@chauthiduniya.com

विद्युत विभाग की लापरवाही और मिलीभगत का ही नतीजा है कि अवैध विद्युत कनेक्शन टोंका फंसाने और बिजली चोरी के सबब ट्रांसफार्मर जलते रहते हैं.

अंधेरे में डूबा सीवान

विगत वर्षों के दौरान अनेक बार लोगों ने विद्युत की कमी और घोर अनियमितता को लेकर धरना-प्रदर्शन, हंगामा और विद्युतकर्मियों के साथ मारपीट भी हुई. इस दौरान कई लोग घायल और गिरफ्तार भी हुए. मगर विद्युत की लचर स्थिति दुरुस्त नहीं हो सकी.

धनंजय मिश्र

सीवान ज़िले में बदहाल विद्युत व्यवस्था से उपभोक्ता त्रस्त हैं. हालांकि कुछ माह पहले बिजली की स्थिति थोड़ी सुधरी थी, लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात की स्थिति हो गई है. बिजली आती है और तुरंत चली जाती है. बिजली आपूर्ति की आंख-मिचौनी की यह बदतर स्थिति पुरानी हो गई है. सुशासन का सपना पाले आम उपभोक्ता यह आस अपने मन में जागृत करते रहे हैं कि अब बिजली की स्थिति सुधरेगी, किंतु इसकी स्थिति हमेशा की तरह आज भी जस की तस बनी हुई है. सुशासन में लोगों ने सोचा था कि पड़ोसी उत्तरप्रदेश की भांति बिहार में भी बिजली आने और जाने की समय-सीमा निर्धारित होगी, जिससे किरोसीन की खपत भी कम होगी. लेकिन लोगों की यह आशा-निराशा में ही बदलती रही है. विद्युत विभाग की लापरवाही और मिलीभगत का ही नतीजा है कि अवैध विद्युत कनेक्शन टोंका फंसाने और बिजली चोरी के सबब ट्रांसफार्मर जलते रहते हैं, जिन्हें बदलने में दो, चार या छह महीने से भी अधिक समय लग जाता है. जिस दौरान ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर संबंधित उपभोक्ताओं से विद्युत विभागकर्मी मोटी रक़म भी वसूलते हैं. इस हालत में टोकाधारी अवैध उपभोक्ता उक्त वसूली रक़म में अपनी हिस्सेदारी देने से भी वंचित रह जाते हैं. यद्यपि जांच के दौरान अगर वे कभी पकड़े भी गए तो विद्युतकर्मियों को कुछ चढ़ावा देकर मुक्त हो जाते हैं. हालांकि विगत वर्षों के दौरान अनेक बार लोगों ने विद्युत की कमी और घोर अनियमितता को लेकर धरना-प्रदर्शन, हंगामा और विद्युतकर्मियों के साथ मारपीट भी हुई. इस दौरान कई लोग घायल और गिरफ्तार भी हुए. बावजूद इसके विद्युत की लचर स्थिति दुरुस्त नहीं हो सकी. अब तो लोग निराश मन से अनाप-शनाप बकते हुए बिजली का नाम लेते हैं.

सबसे दुःखद हाल रसोई गैस का है. हालांकि पूर्व जिलाधिकारियों की भांति डीएम लोकेश कुमार द्वारा भी रसोई गैस की क़िल्लत और कालाबाज़ारी रोकने हेतु अनेक बार प्रयास किया गया. इसके बाद इन डीलरों व एजेंसी प्रबंधकों, मालिकों से समाहरणालय में अनेक बैठकें आयोजित कर इस जनसमस्या को दूर करने का प्रयास किया गया. डीएम ने कड़ी चेतावनी देते हुए इन डीलरों को निर्देश दिया कि निर्धारित समय-सीमा 21 दिनों में गैस की आपूर्ति उपभोक्ताओं को की जाए, ताकि कालाबाज़ारी पर रोक लग पाए. गैस क़िल्लत के मद्देनज़र शहर के कई बड़े-छोटे होटलों में ज़िला प्रशासन द्वारा छापामारी कराई गई, कई होटलों से अवैध रसोई गैस के सिलेंडर बरामद किए गए, जिसके बाद प्रशासन की गाज केवल होटल मालिकों पर ही गिरी और गैस एजेंसी मालिकों के विरुद्ध कोई कारगर कार्रवाई नहीं की गई.

यद्यपि उपभोक्ताओं का कहना है कि कालाबाज़ारी तो वेंडरों के माध्यम से एजेंसी द्वारा कराई जाती है, जो आजकल 800-850 रुपये प्रति सिलेंडर रसोई गैस बेच रहे हैं. मसलन अपनी पुरानी आदत से लाचार पार्वती गैस एजेंसी द्वारा आजकल 40-42 दिनों पर रसोई गैस की आपूर्ति आम उपभोक्ताओं को की जा रही है. वहीं ऋचा गैस एजेंसी द्वारा 34-35 दिनों पर रसोई गैस उपभोक्ताओं को दी जा रही है. उपभोक्ताओं का कहना है कि कमोबेश यही स्थिति नई खुली गैस एजेंसी की भी है. उनका यह भी कहना है कि जिलाधिकारी को चाहिए कि कोई सख्त एवं साफ़ छवि के अफ़सर या दंडाधिकारी से नियमित जांच-पड़ताल कराएं. जो दंडाधिकारी रसोई गैस की आपूर्ति और वितरण सूची की मिलान आवश्यक रूप से दूसरे दिन भी कर सकें, ताकि रसोई गैस की क़िल्लत से उपभोक्ता निजात पा सकें.

feedback@chauthiduniya.com

कैल्शियम का भरपूर सेवन करें : डॉ. भुवन

कोसी इलाक़े में हड्डी रोगियों की संख्या में बड़े पैमाने पर हो रहे इज़ाफ़े के कारण, उपचार एवं नियंत्रण पर चौथी दुनिया ने सहरसा के प्रसिद्ध हड्डी रोग विषेषज्ञ डॉ. भुवन कुमार सिंह से बात की.

- **प्रश्न : हड्डी संबंधित रोगियों में हो रहे इज़ाफ़े का क्या कारण है ?**

डॉ. सिंह : कोसी इलाक़े में अधिकतर लोग ग़रीबी रेखा से नीचे जीते हैं, जिन्हें पर्याप्त मात्रा में दूध, फल एवं अंडे नहीं मिल पाते हैं. इससे उनके शरीर में आवश्यक कैल्शियम की पूर्ति नहीं हो पाती है और वे ऑस्टियोप्रोसिस रोग से ग्रसित हो जाते हैं. इलाक़े में इसके बहुतायत रोगी हैं.

डा0 भुवन कुमार सिंह

- **प्रश्न : ऐसे रोग से बचने के लिए खान-पान में क्या सावधानी बरतें?**

डॉ. सिंह : दूध, हरी सब्जी, दाल, अंडे व ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें कैल्शियम की मात्रा अधिक हो व चिकित्सक की सलाह हड्डी संबंधित रोग को दूर भगाने में सबसे अधिक कारगर सिद्ध होती है.

- **प्रश्न : युवाओं में हो रहे कमर दर्द की शिकायत की वृद्धि का क्या कारण है और इसका उपाय क्या है ?**

डॉ. सिंह : आधुनिक संसाधन ख़ासकर वाहनों का उपयोग युवाओं में कमर दर्द की शिकायत को बढ़ाता है. अगर युवाओं को वाहन का उपयोग करना आवश्यक हो तो वे अपनी कमर पर लंबो सेकेरल बेल्ट का उपयोग करें. यह उनके लिए आवश्यक है. जो मात्र 250-750 रुपये में उपलब्ध है.

- **प्रश्न : पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कमर दर्द व घुटने में दर्द की शिकायत अधिक पाई जाती है, क्यों ?**

डॉ. सिंह : 45 से 50 वर्ष की महिलाएं और जिनकी बच्चादानी निकाल दी गई हो, उनमें यह शिकायत अधिक पाई जाती है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में उनका मासिक धर्म बंद हो जाता है. इससे कैल्शिमय की कमी उनके शरीर में होने लगती है. ऐसी महिला को तुरंत चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, जिससे उनके शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित रखा जा सके.

- **प्रश्न : कम उम्र में हड्डियों के कमज़ोर होने का क्या कारण है?**

डॉ. सिंह : कोसी इलाक़े में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में जोड़ का टी.भी. (राईटिस) रोग अन्य जगहों की तुलना में अधिक देखा जा रहा है. ऐसे बच्चों को चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए. यह पूर्णतः ठीक होने वाली बीमारी है.

- **प्रश्न : वर्तमान समय में किस तरह के रोगी आते हैं आपके पास?**

डॉ. सिंह : सड़क दुर्घटना के शिकार बने रोगियों की संख्या सबसे अधिक है. जिसे मल्टीपुल ट्रामा कहते हैं. लेकिन ऐसे रोगियों को हम तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता है. अगर ऐसे रोगी को एक घंटे के भीतर कुशल चिकित्सक के पास पहुंचा दिया जाए तो उनकी जान एवं उनके अंगों की रक्षा पूर्णतः संभव है. इसके लिए अत्याधुनिक संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

करियर दुनिया

केमेस्ट्री में सफलता का राज : कॉम

आई.आई.टी-जेईई में सफलता के लिए Chemistry का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि Chemistry स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसको थोड़ा कम भी पढ़कर ज़्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं. यह मानना है कमैस्ट्री के जाने माने शिक्षक प्रो जे. आई. कॉम का. आईआईटी की तैयारी के लिए सबसे पहले XIth एवं XIIth को throught depth तक पढ़ें. theory एवं Numerical पर कमांड करें. theory एवं Numerical के लिए सबसे बेहतर किताब एनसीईआरटी, आर.सी. मुखर्जी और टीएमएच है. इस किताब को बार-बार बनाकर पूरा कमांड कर लिया जाए तो आईआईटी-जे ईई के लिए काफ़ी होगा. इसके साथ अरिहंत का गाईड एंड Question Set पर प्रेक्टिस करना चाहिए. कुछ लोग बहुत सारी किताब को एक बार या आधे अधूरे ढंग से पढ़कर यह समझ लेते हैं कि हमारी तैयारी पूरी हो गई, लेकिन यह क़तई समझदारी नहीं है. एक या दो किताब जैसे (RCM, TMH) को बार-बार पढ़कर इसके कॉन्सेप्ट तथा एक-एक Question पर कमांड कर ली जाए तो आईआईटी में सफलता निश्चित है. वैसे Com's Chemistry में इस पूरे Book के अलावा अलग से चैप्टर वाइज एसाइनमेंट एवं कंपटेटिव प्रश्न जो आईआईटी जेईई में पूछे गए हों या पूछने की संभावना हो, इस पैर्टन पर बहुत सारे प्रश्न एकत्रित कर विद्यार्थियों को दिए जाते हैं, जिससे उनकी परेशानी बहुत कम हो जाती है. सिर्फ़ Com's Chemistry के एसाइनमेंट एवं सीडीपीएस (Com's Daily practice set) को बना कर भी लड़के अच्छे रैंक लाते हैं. वैसे Com's Chemistry के विद्यार्थी को तो यहां से एसाइनमेंट उपलब्ध हो जाता है चाहे तो बाहर के विद्यार्थी भी Com's Chemistry के ऑफिस से यहां का एसाइनमेंट एवं मेटिरियल लेकर तैयारी कर सकते हैं. Chemistry में विशेष ध्यान देने वाला टॉपिक जहां से अधिकतम प्रश्न पूछे जाते हैं.

जे आई कॉम

- Atomic Structure और इसके Quantum No. से प्रश्न हमेशा रहते हैं.
- Chemical Bonding (MOT) Chemical Equilibirium, State of Matter, Solution Electrochemisty, Chemical kinetic इन सब टॉपिक से हमेशा और अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं.
- ऑर्गेनिक Isomerisum, GOC, Reaction, Mechanisim, streo chemistry, and Periodic table इन सभी टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं.

- देवेन्द्र दूबे

बिहार से छात्रों का पलायन रुका : के. सिंह

बिहार में विजन क्लासेज ने अलग पहचान बनाई है. इस कारण आईआईटी व पीएमटी की तैयारी करने वाले छात्रों का पलायन काफ़ी हद तक रुक गया है. कोटा के नामी संस्थानों में बिहारी छात्रों के नामांकन में 40 प्रतिशत की गिरावट आई है. अब कोटा के नामी संस्थान ज़मीनी स्तर पर प्रचार करके विद्यार्थियों को प्रभावित करने में जुट गए हैं. इसके बावजूद यह अपने मक़सद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं. विजन क्लासेज ने पिछले वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत का इज़ाफ़ा हुआ है. इससे साबित होता है कि विजन क्लासेज ने छात्रों के पलायन को रोकने में अपना सहयोग दिया है. हाल के वर्षों में विजन क्लासेज के प्रति छात्रों व अभिभावकों का भरोसा बढ़ा है. इस विश्वास को बरक़रार रखने के लिए संस्थान ने भी छात्रों को परिसर में सुविधाएं दी हैं. इसका फ़ायदा छात्रों को मिल रहा है और वह प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर रिजल्ट ला रहे हैं.

के. सिंह

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Maker Of Ariskon Pharma
Carbo-XT
Ferrous Ascorbate With Folic Acid Tab.
FLUCEN
Flupentixol & Melitracen Tablets

बाबा धाम का महाप्रसाद
बाबा सिन्दूर

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
CENTURY POLYPLAST INDUSTRIES

PATALIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT

EIILM UNIVERSITY SIKKIM
COURSES BA, BSc. B.Com. M.A., Misc. Mcom., Mphil, B.C.A, B.B.A., M.C.A., M.B.A.
Study Centre at
ST. MICHAEL ANGLO VIDYALAYA, TIWARI CHOWK, DEOGHAR
ENGLISH MEDIUM UNDER C.B.S.E
HOTEL FACILITY
RUN BY
KERALA EDUCATIONAL & SOCIAL WELFARE SOCIETY
Mob. : 9430345258 (J.C.RAJ)